खण्ड-452, अंक-10
बुधवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(2 मार्च, 2005 ई0)

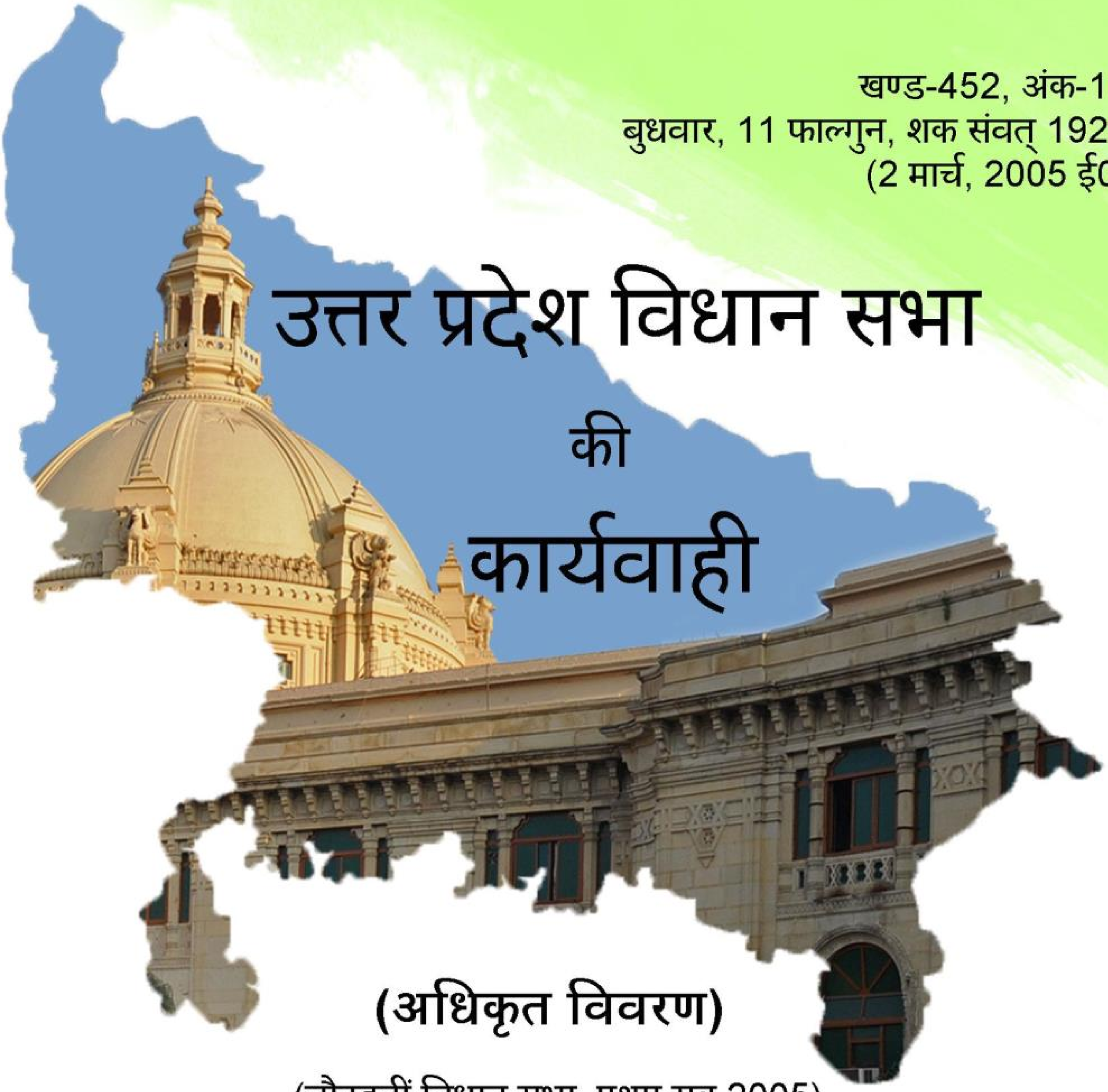

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 452 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ -संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ–झ
नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सुने जाने की मांग----	1
प्रश्नोत्तर----------(जारी)----	1- 2
संबंधित मंत्री द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न----	2- 7
प्रश्नोत्तर ----	7-42
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ----	43
पश्चिमांचल पावर कार्पोरेशन, मेरठ में कृषकों को नये नलकूप कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	44
मेरठ नगर की सीमा में गढ़ सोनीपत मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने मानक के अनुरूप निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	44
आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत मृतक सुखई के परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	45
जनपद-एटा के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही कथित धांधली एवं प्रबंधकों के उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	45-46
प्रदेश में सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण हेतु इंसीनेटर लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	46
सहारनपुर के ग्राम कोटा स्थित राजकीय महिला विद्यालय की छात्राओं की समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	46
जालौन के कालपी में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	46-47
मधुनगर ग्वालियर रोड चौराहे से सेमरी के ताल देवरी रोड जनपद-आगरा में नाला व सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	47
बुन्देलखण्ड में किसानों के सिंचाई कनेक्शनों में कृषि विद्युत उपभोक्ता दरें प्रदेश के अन्य जनपदों से दोगुनी वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	47

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत कुंवर गड्डी रजवाहा में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	48
बाराबंकी के नबाबगंज क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग नं0-28 सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रीज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	48
गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर कटया के पास गोघनी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	48-49
शाहजहांपुर विसरात घाट पर पैदल पुल के निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम के पास धन जमा होने के बाद भी पुल न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	49
जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर से स्याना बुलन्दशहर मार्ग के सुधार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	49
बलिया के ग्राम मल्लप हरसेनपुर के अध्यापक स्व0 राम जी मिश्र की पत्नी को पेंशन राशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----	49-50
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं----(जारी)	50-51
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का सत्रहवां प्रतिवेदन----(प्रस्तुत किया गया)----	51
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन----(प्रस्तुत किया गया)----	51
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं----	52
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का पंचम प्रतिवेदन----(प्रस्तुत किया गया)----	52
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का षष्ठं प्रतिवेदन----(प्रस्तुत किया गया)----	52
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव----(स्वीकृत)----	53-55
प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100-100 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाये जाने की मुख्य मंत्री की घोषणा का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न----	55-56
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग, विधेयक, 2005----(पुर-स्थापित)----	56-57

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं----	57- 78
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा----(जारी)----	78-119
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं----	119-122

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 2005

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य-340

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री मुरादाबाद
2-अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
3-अजय कुमार, डा0 बागपत
4-अजय राय, श्री वाराणसी
5-अजीम भाई, श्री फिरोजाबाद
6-अनवर महमूद, श्री बलरामपुर
7-अनार सिंह दिवाकर, श्री एटा
8-अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
9-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
10-अनिल कुमार मौर्य, श्री मिर्जापुर
11-अनिल कुमार वर्मा, श्री सीतापुर
12-अनिल कुमार पासवान, श्री हरदोई
13-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री एटा
14-अनिल सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
15-अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री पीलीभीत
16-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री देवरिया
17-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री बस्ती
18-अन्सार अहमद, श्री इलाहाबाद
19-अब्दुल कलाम, श्री सन्त कबीर नगर
20-अब्दुल मन्नान, श्री हरदोई
21-अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री बाराबंकी
22-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री फतेहपुर
23-अमरमणि, श्री महाराजगंज
24-अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री हाथरस
25-अमीता सिंह, श्रीमती सुल्तानपुर
26-अम्बेश कुमारी, श्रीमती महोबा
27-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
28-अरविन्द गिरि, श्री खीरी
29-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री बाराबंकी
30-अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 जालौन
31-अरुण कुमारी, श्रीमती कानपुर देहात
32-अरुणवीर सिंह, श्री बहराइच
33-अरुणा तोमर, श्री कानपुर नगर
34-अवधेश कुमार वर्मा, श्री शाहजहांपुर
35-अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
36-अशोक कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
37-अशोक बाजपेयी, डा0 हरदोई
38-अशोक सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
39-आदित्य बिक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री सिद्धार्थनगर
40-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री फतेहपुर
41-आर0 एस0 कुशवाहा, श्री खीरी
42-आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
43-आलम बदी, श्री आजमगढ़
44-आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
45-आशा किशोर, श्रीमती रायबरेली
46-आशीष यादव, श्री बदायूं
47-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
48-इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
49-इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
50-इन्द्रदेव सिंह, डा0 बिजनौर
51-इलम सिंह, श्री सहारनपुर
52-उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
53-उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
54-उदयराज यादव, श्री उन्नाव
55-उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
56-उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
57-ओइमवेश, स्वामी बिजनौर
58-ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
59-ओमप्रकाश, श्री सीतापुर

60-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
61-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
62-ओमप्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
63-ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
64-कपिल देव यादव, श्री मऊ
65-कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
66-कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
67-कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
68-कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
69-काशीराम, श्री रामपुर
70-किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
71-किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
72-किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
73-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74-कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
75-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
76-कैलाश, श्री गाजीपुर
77-कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
78-कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
79-कौकब हमीद खां, श्री बागपत
80-कौशल किशोर, श्री खीरी
81-कौशल किशोर, श्री लखनऊ
82-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
83-गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
84-गया चरन दिनकर, श्री बांदा
85-गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
86-गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
87-घूरा राम, श्री बलिया
88-चन्द्र किशोर, श्री महाराजगंज
89-चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
90-चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
91-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
92-चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
93-छेदी राम, श्री गाजीपुर
94-छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
95-छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
96-जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
97-जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
98-जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
99-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
100-जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
101-जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
102-जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
103-जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
104-जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
105-जयप्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
106-जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
107-जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
108-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री गोरखपुर
109-जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
110-ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महाराजगंज
111-डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री चित्रकूट
112-तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
113-दयाराम, श्री कौशाम्बी
114-दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
115-दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
116-दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
117-दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
118-दीनानाथ भाष्कर, श्री नगर भदोही सन्त रविदास
119-दुर्गाप्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
120-दैवकी नन्दन, श्री हाथरस
121-देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
122-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
123-द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर
124-धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
125-धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
126-धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
127-धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
128-नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
129-नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
130-नरेन्द्र कुमार, श्री गौतमबुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

131-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
132-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
133-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
134-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
135-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
136-नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
137-नारद राय, श्री बलिया
138-परमजीत, श्री मुजफ्फरनगर
139-परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
140-पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
141-पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
142-पीतम राम, श्री पीलीभीत
143-पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
144-पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
145-प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
146-प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
147-प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
148-प्रभु दयाल, श्री मेरठ
149-प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
150-प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
151-प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
152-प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
153-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
154-प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
155-प्रेम सिंह, श्री मथुरा
156-फतेह बहादुर, श्री महाराजगंज
157-फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) देवरिया
158-बंशीधर राज, श्री खीरी
159-बलराम यादव, श्री आजमगढ़
160-बाबूराम, एम0काम0, श्री जालौन
161-बाबू लाल, श्री गोण्डा
162-बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
163-बिजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
164-बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
165-बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
166-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज), श्री झांसी
167-बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
168-बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
169-भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
170-भरत सिंह, श्री बलिया
171-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
172-भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
173-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
174-मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
175-मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
176-मदन भैया, श्री बागपत
177-मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
178-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
179-मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
180-मशहूद खां, श्री बलरामपुर
181-मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
182-महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
183-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
184-महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी अलीगढ़
185-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
186-महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
187-महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
188-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
189-मान पाल सिंह, श्री एटा
190-माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
191-मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
192-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
193-मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
194-मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
195-मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
196-मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
197-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
198-मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
199-मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
200-मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
201-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद

202-मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
203-मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
204-यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
205-यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
206-याकूब, हाजी — मेरठ
207-योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
208-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
209-रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
210-रणवीर राणा, श्री — मेरठ
211-रतनलाल अहिरवार, श्री — झांसी
212-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
213-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
214-रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
215-राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकरनगर
216-राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
217-राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
218-राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
219-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
220-राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
221-राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
222-राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
223-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
224-राजा राम, श्री — प्रतापगढ
225-राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
226-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
227-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
228-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
229-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
230-राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
231-राजेश कुमार, श्री — खीरी
232-राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
233-राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
234-राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
235-राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
236-राम करन आर्य, श्री — बस्ती
237-राम किशुन, श्री — वाराणसी
238-राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
239-राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
240-राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
241-रामजी शुक्ला, श्री — औरैया
242-रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
243-राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
244-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
245-राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
246-रामबाबू हरित, डा0 — आगरा
247-राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
248-राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
249-राम मगन, श्री — बाराबंकी
250-राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
251-रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
252-रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
253-राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
254-राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
255-राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
256-रामहेत, श्री — सीतापुर
257-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
258-रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
259-रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
260-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 — मेरठ
261-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
262-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
263-लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
264-लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
265-लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
266-वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
267-वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
268-विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
269-विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदास नगर भदोही
270-विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
271-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र

272-विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
273-विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
274-विनय शाक्य, श्री — औरैया
275-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
276-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
277-विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
278-विनोद तिवारी, डा0 — पीलीभीत
279-विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
280-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
281-विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
282-वीरेन्द्र प्रताप सिंह, "मुन्ना" — शाहजहांपुर
283-वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
284-वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
285-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदास नगर भदोही
286-शब्बीर, श्री — बहराइच
287-शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
288-शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
289-शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
290-शाकिर अली, श्री — देवरिया
291-शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
292-शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
293-शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
294-शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
295-शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
296-शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
297-शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
298-शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर — प्रतापगढ़
299-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महाराजगंज
300-शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
301-श्याम सिंह अहेरिया, श्री — मथुरा
302-श्यामदेव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
303-श्याम नारायन, श्री — महाराजगंज
304-श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
305-श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
306-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
307-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
308-श्रद्धा यादव, श्रीमती — जौनपुर
309-श्रीराम भारती, श्री — मिर्जापुर
310-संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
311-संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
312-सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
313-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
314-सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
315-सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
316-समरपाल सिंह, श्री — बागपत
317-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 — मुरादाबाद
318-सलिल बिशनोई, श्री — कानपुर देहात
319-सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
320-सियाराम सागर, डा0 — बरेली
321-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
322-सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
323-सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
324-सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री — गाजियाबाद
325-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
326-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
327-सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
328-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
329-सुशील चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
330-सुशील चौधरी, डा0 — सहारनपुर
331-सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
332-सोमारू राम सरोज, श्री — जौनपुर
333-सोवरन सिंह, श्री — मैनपुरी
334-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
335-हरि ओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
336-हरि प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
337-हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
338-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी
339-हीरा लाल गौतम, श्री — आजमगढ़
340-हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

नोट :-परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सुने जाने की मांग

श्री मुंशी लाल गौतम-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने नियम 56 में सूचना दी है । एक लड़की के साथ बाप के सामने रेप किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने नियम 56 में सूचना दी है और आपको नियम पता है तो नियम के आने पर उसकी चर्चा करें ।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टंडन)-

मान्यवर, मुझे केवल इतना कहना है कि कल इन्होंने इसे उठाया था तो पीठ से ऐसे निर्देश हो गये थे कि आज इसे ले लिया जायेगा तो आज पहले वह ले लिया जाय। पहले का मेरा मतलब यह है कि जब नियम 56 लिया जाय तो उसे पहले ले लिया जाय ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरा भी था ।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, हमारी भी सूचना है वह ली गयी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठें ।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर तथा रोकने के उपाय

***1-डा0 सुशील चौधरी-**

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश की जनसंख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है ? क्या सरकार सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले अशिक्षित लोगों को जनसंख्या वृद्धि रोकने की जानकारी देने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की जानकारी देने तथा जनसंख्या नियंत्रण के साधनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक गांव में उसी गांव की एक शिक्षित महिला को तैनात करने से संबंधित एक योजना पर विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष-तारांकित प्रश्न संख्या-1

(परिवार कल्याण मंत्री के उपस्थित न रहने तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-1का उत्तर पढ़ने पर)

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे हैं ।

सम्बन्धित मंत्री द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ-)

वाजपेयी जी, आप हर समय सीरियस रहते हैं ।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, लगता है सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की जनसंख्या का नियंत्रण कर लिया है ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमारी सहानुभूति इनके साथ है लेकिन जो सम्बन्धित मंत्री है उनको सदन में बुलाया जाय । यह तो संसदीय कार्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि खड़े हो जाते हैं, लेकिन मान्यवर, जो संबंधित मंत्री हैं इतनी उपेक्षा करेंगे, प्रश्न उनका होगा और वह नहीं आयेंगे तो इस सदन की क्या आवश्यकता है ? मान्यवर, उन्होंने शपथ ले रखी है, सारी सुविधा मंत्री पद की ले रहे हैं और घर पर बैठे हुए हैं ।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, अगर माननीय विधायकों के जनहित के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह उपस्थित नहीं है तो कब तक माननीय संसदीय कार्यमंत्री चलायेंगे ?

(श्री हुकुम सिंह एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है । अगर मंत्रियों की यह पोजीशन आ जाय कि सदन को नहीं मानेंगे, उनके आदेश को नहीं मानेंगे तो सदन की क्या आवश्यकता है ? मान्यवर, आप निर्देश दें कि मंत्री जी यहां पर आयें, क्षमा माँगें और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, इसकी चिन्ता करें । प्रश्नकाल को गम्भीरता से लिया जाय।

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिये । यह पीठ को अधिकार है अगर कोई मंत्री उपस्थित नहीं होता है ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, ये हर समय सीरियस रहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

लक्ष्मीकान्त जी आप बैठें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पीठ से व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी वही कह रहे हैं, वाजपेयी जी, वही कह रहे हैं ।

मैंने संसदीय कार्यमंत्री जी से कहा है प्रश्नकाल को गम्भीरता से लिया जाय । संसदीय कार्यमंत्री इस बात की चिन्ता करें कि संबंधित मंत्री यहां पर उपस्थित रहें ।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, इस पीठ से कई बार निर्देश हो चुका है । इस सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने मंत्रियों को ताकीद की है कि वह अपने विभाग से संबंधित प्रकरणों पर स्वयं उपस्थित रहा करें। जहाँ तक संयुक्त उत्तरदायित्व की बात है, वह हमें मालूम है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। इस प्रश्न को आप तब तक स्थगित करें, जब तक संबंधित मंत्री सदन में आकर उत्तर न दें । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग बैठें । संसदीय कार्य मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन-)

मान्यवर, ऐसे में यह होता.....

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, क्या आपने चर्चा की इजाजत दे दी है ? मैंने तो आपसे निवेदन किया था । मुझे भी अपने

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कष्ट का इजहार करने दीजिये । 5 मिनट चर्चा हो गयी, उस बात पर, जो वाकया ही नहीं है । [XXX XXX XXX]

श्री उपाध्यक्ष-

यह आरोप है ।

श्री लालजी टण्डन-

हम तो इन्हीं के लिए कह रहे हैं, कि सारी फाइलें इन्हीं पर लाद दी जायें । इसमें दो रास्ते हैं या तो आप उन्हें अभी बुलवाइये अन्यथा इस प्रश्न को स्थगित कर दें, जब वह आयें तो उत्तर दें ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यर, आपके जैसे निर्देश हों । आप फरमायें कि मुझे इनका जवाब देना है या प्रश्न का जवाब देना है ? आपने तो एक ही पक्ष को सुना, मुझे भी तो सुन लेते । 6 मिनट हो गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने आपको पुकारा तो ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आपने मुझे कहाँ सुना ? मान्यवर, आप अपनी पीठ से यह निर्देश देंगे कि जो 6 मिनट बहस हुई है, मुझे उसका जवाब देना है या मुझे प्रश्न का जवाब देना है ?

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने प्रथम प्रश्न के लिये आपको बुलाया था । मैंने संसदीय कार्य मंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कहा और तारांकित प्रश्न क्रमांक-1 बुलाया । संबंधित मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मुझसे पहले आप यह सुन लेते कि वह किसलिये नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

यह विषय तो आपको ही रखना है ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मुझे बिल्कुल न सुने ही आपने टिप्पणी फरमा दी । आप कार्यवाही देख लें, टिप्पणी तो आ गयी और आपने मुझे सुना नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने आपसे आग्रह कि आप उत्तर दें ।

[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं क्षमा चाहूंगा । मेरा आपसे केवल इतना कहना है कि आपने मुझे सुने बगैर कह दिया कि संबंधित मंत्री क्यों नहीं आये हैं या क्यों नहीं आ सकते ? आपने एक टिप्पणी फरमा दी । कल यह अखबार में छप जायेगी । मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, आप कार्यवाही में देख सकते हैं । सरकार को इस तरह कठघरे में खड़ा करने के लिये विपक्ष जिम्मेदार है या हम खुद जिम्मेदार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष-

हम कार्यवाही देखकर निर्णय कर लेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

रिकार्ड पर टिप्पणी आ गयी । मुझे सुने बगैर आ गई । आपको यह जानकारी हुये बगैर कि संबंधित मंत्री क्यों नहीं आये, आपकी टिप्पणी आ गयी । तो मैं इसमें संरक्षण चाहूँगा कि यह टिप्पणी निकाली जायेगी या उसे रहने देंगे ।

श्री हुकुम सिंह-

यह सदन के इतिहास में पहली बार हो रहा है ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, पहले में मात्र इतनी जरूर इजाजत चाहूंगा कि जो टिप्पणी आपने मुझे बगैर सुने फरमा दी, उस टिप्पणी को आप देखकर कोई निर्णय लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप कह रहे हैं, मैं उसे देख लूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, उत्तर का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं उस टिप्पणी को देख लूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मुझे तो आप सुनेंगे, पहले में उस ऐतराज पर कुछ कह दूं । मैं प्रश्न का जवाब देने से पहले कह दूं कि मंत्री जी क्यों नहीं आये और उन्हें क्यों नहीं रि-प्रेजेन्ट किया गया । मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि मैं संसदीय कार्यमंत्री हूँ और इस पर किसी को ऐतराज का हक नहीं है । संसदीय कार्यमंत्री किसी प्रश्न का जवाब क्यों दे रहे हैं, तो मान्यवर, यह मेरा अधिकार है और मेरा दायित्व भी है, दूसरे अगर कोई मंत्री उपस्थित नहीं है तो सदन की सामूहिक जिम्मेदारी होने के नाते भी यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रश्न का जवाब दूँ । माननीय अहमद हसन साहब मंत्री हैं और वह विधान परिषद् में सदन के नेता हैं, इस बिना पर वह सदन में नहीं आ पाते हैं । मान्यवर, आपका आदेश हो जाए तो उन्हें परिषद् को छोड़कर यहाँ पर बुला लिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष-

तो मैं इस प्रश्न को स्थगित कर दूँ, जैसा आप कहें ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद-)

मान्यवर, जैसे ही प्रश्न आपके द्वारा उठाया गया, संसदीय कार्यमंत्री खड़े हो गये जवाब देने के लिये और उन्होंने जवाब देना शुरु कर दिया । मान्यवर, मंत्रि-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, ऐसी स्थिति में यह चिन्ता का विषय नहीं है कि प्रस्तुत उत्तर किसके द्वारा दिया जा रहा है ।...

(इस समय 11 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

जब प्रश्न एक का उत्तर देने के लिए संसदीय कार्यमंत्री खड़े हुए और उत्तर देना शुरु कर दिया...

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रश्न सं0-1 का नहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना शुरु कर दिया ।

श्री अवधेश प्रसाद-

उत्तर देते समय ही विपक्ष की तरफ से यह सवाल आया कि माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं? जब श्रीमन् सामूहिक जिम्मेदारी उत्तर देने की होती है तो यह बड़े अफसोस की बात है कि जिन माननीय सदस्यों की ओर से यह सवाल उठाया गया है, वह सभी सदस्य बहुत पुराने हैं, कई वर्षों से उन्हें काम करने का अनुभव है, उन्हें उत्तर देने का भी मौका मिला है, ऐसी स्थिति में जब सामूहिक जिम्मेदारी है तो यह चिन्ता का विषय निर्मूल है और जो संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, वह उत्तर देने में सक्षम हैं और उन्होंने माननीय मंत्री जी के उपस्थित न होने का कारण भी बता दिया है कि इस समय प्रश्न से संबंधित मंत्री जी विधान परिषद् में हैं और वहां के नेता हैं । ऐसी स्थिति में यह जो सवाल उठाया गया है, बिल्कुल निरर्थक है, परम्पराओं और नियमों के विपरीत है ।

श्री अध्यक्ष-

अब इस प्रकरण को समाप्त कीजिए । इस सन्दर्भ में जहाँ तक सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन और संसदीय कार्यमंत्री जी से बात करके इस समस्या का हल निकाल लिया जायेगा । अब प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिए । संसदीय कार्यमंत्री जी कृपया प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जब मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है तो फिर संसदीय कार्यमंत्री जी के जवाब देने से क्या समस्या पैदा हो गयी ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें । संसदीय कार्यमंत्री जी आप प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इस संबंध में आपका जो भी निर्देश है, वह शिरोधार्य है लेकिन इस वक्त समस्या के दो

पहलू हैं । एक तो यह कि रोजमर्रा का तरीका कि कोई एक व्यक्ति सभी बातों का जवाब दे बिल्कुल नापसन्दीदा बात है । (श्री लालजी वर्मा के कुछ कहने पर) वर्मा जी की जिज्ञासा व परेशानी बिल्कुल सही है । प्रश्नकाल का समय विपक्ष का होता है और 15 मिनट तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से व्यवधान किया है, वह पूरे विपक्ष का नुकसान है और इससे विपक्ष के दूसरे सदस्यों का परेशान होना लाजिमी है । मान्यवर, लगभग 16 मिनट हो गया, प्रश्न काल स्थगित रहा और इसका कोई मतलब नहीं रहा । एक गम्भीर मामला है, एक आम हालात में जवाब देना और किसी ऐसे मंत्री का जवाब देना जो विधान परिषद् में नेता हैं, जो आ नहीं सकता । इसके बावजूद अगर पीठ पर बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति के नरमी, उनकी अपनाईयत का ज्यादा फायदा उठाया जाये तो यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं सब दिखवा लूंगा, प्रश्न का उत्तर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी दें ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

नत्थी (क)

(तारांकित प्रश्न संख्या-1)

डॉ0 सुशील चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है और उसको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने में थोड़ा विलम्ब होने पर)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की कठिनाई समझ सकता हूं । आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें । मान्यवर, यह एक राष्ट्रीय समस्या है और जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी की कठिनाई समझ सकता हूं कि यह उनका विभाग नहीं है और संबंधित माननीय मंत्री जी आ नहीं सकते । वह जिस दिन आयेंगे उस दिन इसका जवाब ले लेंगे । (इसी बीच संसदीय कार्यमंत्री जी के पास एक स्लिप पहुंचायी गयी) इस तरह से स्लिप से सदन नहीं चलता है ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, 2.5 प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है । इसलिये समय लग रहा था कि मैं आपका इसका लम्बा जवाब देना चाह रहा था ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जनसंख्या दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत है । अप्रत्याशित जनसंख्या की वृद्धि से सारी विकास की योजनायें प्रभावित हो रही हैं । आपने उत्तर में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की जानकारी देने तथा जनसंख्या नियंत्रण के साधनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक गाँव में उसी गाँव की एक शिक्षित महिला को तैनात करने की कार्ययोजना तैयार की है ।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस महिला की क्वालिफिकेशन क्या होगी, वह महिला ट्रेण्ड होगी या अनट्रेण्ड होगी तथा उसको मानदेय दिया जायेगा या उसकी नियुक्ति होगी? जो सरकार की कार्ययोजना है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने की जिससे जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके, वह क्या है तथा वर्तमान समय में परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा है ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह प्रश्न अपने तरीके से सदन में कई बार आया है । माननीय सदस्यों की इस पर जिज्ञासा रही है, कल भी लगभग इससे मिलते-जुलते प्रश्न पर सदन में बहस हुई और मंत्री जी ने एक सर्वदलीय समिति बनाकर सबसे बात करने की बात कही है । यह सामाजिक समस्या है, आबादी के बढ़ते सैलाब को रुकना चाहिए, उसमें कमी होनी चाहिए लेकिन इसको रोकने के लिए तरीका क्या हो, इस पर विचार होना चाहिए । मान्यवर, दो तरीके हो सकते हैं । एक तरीका है कि सख्ती की जाय और एक तरीका है कि लोगों को समझा-बुझाकर इस बात के लिए तैयार किया जाय कि बच्चे कम पैदा करे । कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उनके लिए विचार करने की आवश्यकता है कि कौन से कारण हैं जिससे उनकी आबादी ज्यादा है । अशिक्षा, बेरोजगारी, कम से कम संसाधन, सैर और तफरी के कम से कम इंतजामात होने की बजह से उनकी जनसंख्या बढ़ती है । इसको किसी जाति और धर्म से अलग करके हमें देखना चाहिए । अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के वह लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनके यहां बच्चों की पैदावार कम है । जाहिर है कि उन्होंने अपनी आबादी पर कंट्रोल किया है । यह विचार बराबर चल रहा है कि किस तरह लोगों को तैयार करें ताकि वह कम से कम बच्चे पैदा करें । मान्यवर, जहां तक इस स्कीम का ताल्लुक है, यह भारत सरकार की स्कीम है । हमें विभागीय स्तर से जानकारी मिली है कि इसमें एक महिला का चयन किया जायेगा, अभी इस योजना के डिटेल्स नहीं आये हैं । अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह महिला थोड़ी पढ़ी-लिखी होगी और इसको एक हजार रुपये मानदेय दिया जायगा । वह महिला इस स्कीम के अन्तर्गत गॉव और वहां के लोकल लोगों में यह अहसास पैदा करेगी कि वह कम बच्चे पदा करें ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इससे सदन सहमत होगा कि जनसंख्या वृद्धि देश और प्रदेश के लिए घातक हो गई है । विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है । सच्चाई यह है कि आबादी इतनी बढ़ रही है कि हम आस्ट्रेलिया के बराबर आबादी प्रतिवर्ष बढ़ाते चले जा रहे हैं जबकि हमारे क्षेत्रफल और संसाधन वही हैं। क्या सरकार इसके लिए सर्वानुमति बनाकर दलों से बात करके कोई कानून बनाएगी, जनसंख्या को सीमित रखने के संबंध में किसी कानूनी विधेयक को लाने पर विचार करेगी ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या है दुनिया के बहुत से देशों की यह समस्या है । हमारे बराबर है एक देश चीन, उसकी आबादी हमसे कहीं ज्यादा है और बढ़ रही है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, जो उनकी बढ़ती हुई आबादी है उससे काम लेना शुरू किया है । उनके यहां जो भी सरकारें सत्ता में रही हैं वह उनसे काम ले पाती हैं, जबकि हम अपने देश में ऐसा नहीं कर सके । यह समस्या मात्र उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि की समस्या है।

मैं चाहूंगा कि इस पर कोई सख्त कानून, तगड़ा कानून बनाने, जबरन इसको लागू कराने में भारत सरकार सक्षम है । राष्ट्रीय स्तर पर वह कानून बनाए, उत्तर प्रदेश सरकार उसके बारे में विचार करेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

जो उत्तर आप चाहते हैं वह उत्तर देने के लिए मंत्री जी को बाध्य नहीं किया जा सकता । कल इस पर बहस हो चुकी है ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हम भारत की पार्लियामेन्ट में नहीं बैठे हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा में हम बैठे हैं । हमें उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न करने का अधिकार है । मैंने जबरदस्ती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है इसका मैं प्रतिकार करता हूं । मैंने कहा कि सर्वानुमति से कानून लाने पर विचार कर रही है । यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है आप विधेयक लाएं और उसकी संस्तुति केन्द्र को भेजें । क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई कानून बनाएगी, कोई प्रस्ताव लाएगी जिसे वह केन्द्र सरकार को भेजे मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नेता कांग्रेस पार्टी ने आबादी के कंट्रोल करने के संबंध में कानून बनाने की बात कही जाहिर है कि यह सख्त कानून से ही रुकेगी । समझाने बुझाने से जनसंख्या वृद्धि रुक नहीं रही है । वर्ष 1975 में कांग्रेस केन्द्र सरकार में थी और वह जोर जबरदस्ती करने का तजुर्बा हासिल कर चुकी है। इसलिए दूसरी बार भी कोई तजुर्बा करना चाहती है तो कर सकती है । अगर कोई भी जोर जबरदस्ती करना है तो उसके लिए केन्द्र सरकार को पूरा अधिकार है ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा भी एक अनुपूरक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

कल आप इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के मेडिकल कालेजों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों के डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने पर रोक लगाने के निर्देश

***1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-**

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों के डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिये

गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसका कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह-)

शासनादेश दिनांक 21.7.2003 द्वारा जिलाधिकारियों को नहीं अपितु मण्डलायुक्तों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों/शिक्षकों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

शासन द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने हेतु सतत रूप से प्रयास किया जाता रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, यह देखा जाता है कि जो सरकारी मेडिकल कालेज हैं या चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं वहां के चिकित्सकों को लम्बी तनख्वाहें दी जाती हैं और अन्यान्य सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी वहां के अध्यापक अध्यापन कार्यों या चिकित्सा में रुचि कम प्रदर्शित करते हैं और निजी प्रैक्टिस पर अधिक जोर देते हैं अधिक धन कमाने की चाह में । सरकार की ओर से इसको रोकने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है और इस हेतु 21.7.2003 को प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों और चिकित्सकों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं उसके तहत अभी तक आज की तिथि तक कितने चिकित्सकों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की गई ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह-

शासन से सभी संबंधित मण्डलों के मण्डलायुक्तों, संबंधित परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षकों, संबंधित मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों, संबंधित जिलाधिकारियों, संबंधित पुलिस अधीक्षकों, संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं । मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है जहां कहीं से शिकायत आती है उसकी जांच की जाती है और कार्यवाही करने का काम होता है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

जब से कठोरतम कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं तब से अब तक कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी यह बता दें जब से कार्यवाही की प्रक्रिया अपनाई है तब से अब तक कुछ लोग दंडित हुए हैं।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह-

अध्यक्ष जी उसके लिए सूचना संकलित कराई जा रही है । मूल प्रश्न में यह सवाल नहीं था यह मूल प्रश्न से हटकर है ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, प्रदेश के मेडिकल कालेजों में जो डाक्टर और प्रोफेसर हैं उनमें से अधिकांश प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं । इसी कारण से मेडिकल कालेज में मरीजों का जाना कम हो गया है । जो कहीं पर भी प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं वही वहां जाते हैं ।

मान्यवर, वे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और नॉन प्रैक्टिस एलाउन्स भी ले रहे हैं । आपने लिखा है, कठोर भी नहीं कठोरतम । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि डेढ़ साल के अन्दर आपने कितने मेडिकल कालेजों के अन्दर निरीक्षण कराया ? मान्यवर, मुझे जानकारी है और आपको भी होगी कि कितने लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने अभी तक जॉच नहीं करवाई। अगर इन्होंने निरीक्षण किया तो कितने लोग इसमें दोषी पाये गये और उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? इस तरह से जनता के साथ बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं ।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह-

मान्यवर, सूचना संकलित कराई जा रही है और मैं माननीय गौर साहब से कहूंगा कि आपके यहां इलाहाबाद मेडिकल कालेज है आपके क्षेत्र में शायद पड़ता होगा । अगर आपको कोई सूचना है तो आप लिखकर दे दें कठोर से कठोर कार्यवाही सरकार करेगी ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब, आप खुद मंत्री रहे हैं । जानते हैं । मंत्री जी ने कहा है कि इस तरह की शिकायत है तो आप लिखकर दे दीजिये ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत भिज्ञ हैं, अनुभवी हैं, स्वयं देख रहे हैं कि मंत्रीगण उपस्थित नहीं रहते हैं उत्तर देने के लिए और उसके कारण माननीय संसदीय कार्य मंत्री में उत्तेजना पैदा होती है ।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये । काहे को इतिहास दोहरा रहे हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, अगर संबंधित मंत्रीगण उपस्थित हैं तो भी....

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, देखिये कितने मंत्रीगण बैठे हैं इस समय सदन में, यह देख लिया जाय । महज इधर से एक फैशन बना लिया गया है इसलिये हमने अपने सदस्यों को कहा है कि थोड़ा सहयोग दे दें । अपने गिरेबां में झांककर देख लें, पुरानी कार्यवाहियों में देख लें कि कितने मंत्रीगण मौजूद रहते थे।

(किसी सदस्य के यह कहने पर कि व्यक्तिगत आक्षेप निकाल दिया जाय)

श्री अध्यक्ष-

व्यक्तिगत आक्षेप कार्यवाही से निकलवा देंगे । चौधरी जी, आप प्रश्न करिये ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की गरीब जनता से जुड़ा हुआ सवाल है और निश्चित रूप से जनता को

सरकार की तरफ से जो सुविधाएं अनुमन्य हैं वे नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि वे रुचि नहीं लेते हैं । दिनांक 21.7.2003 को कठोरतम कार्यवाही हेतु मण्डलायुक्तों को और एस0एस0पी0 को निर्देश दिये गये हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, हम सभी संरक्षण चाहेंगे । मान्यवर, प्रश्न आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष-

आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं ? उनको सुन लीजिए तब कहियेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, और भी सदस्य हैं और भी प्रश्न लगे हैं । सरकार जवाब देना चाहती है ।

श्री लाल जी टण्डन-

यह बड़ा आपत्तिजनक है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री पता नहीं क्यों आज दुःखी हैं या आक्रोश में हैं कि वे बार-बार चेयर के ऊपर, आज अभी पहले उपाध्यक्ष के ऊपर कहा । मान्यवर, जो संसदीय कार्यमंत्री हो और जिसे संसदीय ज्ञान हो वह इस तरह से बोलेंगे ? अभी आप बैठे हुए हैं तब भी इसी तरह से कहेंगे ? क्या यह चेयर अपना फैसला वहां से देगी ? मान्यवर, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं । ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में एक फ्रेज है-'स्पीकर, हू स्पीक्स लैस'

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा वास्तविक रूप से आक्षेप यह हुआ ।

श्री लाल जी टण्डन-

यह तो ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में और जितने भी संसदीय ज्ञान के लिये ग्रंथ हैं, उन सबमें लिखा हुआ है और वह हमेशा इस सदन में कोट किया जाता है । मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि आपकी मजबूरी है कि 'स्पीकर, हू स्पीक्स लैस' और उसका फायदा यह उठाते हैं । हर वक्त धौंस देकर सदन चलवायेंगे तो यह उचित नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष मैं किसी के धौंस या दवाब में काम नहीं करता हूं जो विधान सभा की नियमावली और कार्य पद्धति है उसके अनुसार काम करता हूं किसी के दवाब में काम नहीं करता हूं चौधरी साहब की आदत है भूमिका बनाकर प्रश्न पूछते हैं और संसदीय कार्यमंत्री जल्दी चाहते हैं । चौधरी साहब, आप प्रश्न करें ।

(श्री रामकरन आर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें । चौधरी साहब एक सवाल पूछें फिर आगे बढ़ें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

यह मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है । प्रदेश की जनता का सवाल था....

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछिए ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं 21.7.2003 को जो कठोरतम, सरकार मानकर चल रही है, अगर यह ऐसा कहते हैं कि 21.7.2003 को कठोरतम कार्यवाही के निर्देश दिए गए, संबंधित अधिकारी तय कर दिए गए । मैं अपने सवाल के माध्यम से, और आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है इस निर्देश के जारी होने के बाद से आज की तिथि तक ऐसे मेडिकल कालेज, चिकित्सा विश्वविद्यालय और चिकित्सकों के विरुद्ध जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनके विरुद्ध क्या कठोरतम कार्यवाही हुई ?

(श्री डी0 प्रसाद अहिरवार के खड़े होने पर)

श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पण्डित सिंह-

[xxx xxx xxx]

(व्यवधान)

(श्री ओमप्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री जगदीश नारायण राय, श्री लाल जी वर्मा, श्री डी0 प्रसाद अहिरवार आदि बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और नारे लगाने लगे ।)

श्री लालजी वर्मा (सदन के फ्लोर से)-

ऐसे [xxx] से सदन नहीं चलेगा पहले यह माफी माँगें । वहाँ से मंत्री जी धमकियाँ दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सब अपनी सीट पर जाएं, क्या चाहते हैं ?

(सदन के फ्लोर पर आए सभी सदस्य वापस अपनी सीट पर चले गए ।)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की कार्यवाही आपके निर्देशानुसार संचालित होती है । पीठ के निर्देशों को हम सब लोग मानते हैं, कुछ बातों में हम प्रतिरोध भी करते हैं । आपके निर्देशानुसार ही सदन, कार्य संचालन नियमावली के अनुसार चलता है । डी0 प्रसाद अहिरवार जी खड़े हुए उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग चिकित्सा शिक्षा, राज्य मंत्री ने किया है, वह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है । पूरा सदन गवाह है, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से वह निन्दनीय है और उसकी पूरे सदन को निन्दा करनी चाहिए । अध्यक्ष जी, मैं आपसे अपील करता हूं,

नोट :-[xxx] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

इससे पूरे सदन का अपमान हुआ है, इससे केवल एक व्यक्ति विशेष, दद्दू प्रसाद या लालजी वर्मा का ही अपमान नहीं हुआ है, यह पूरे सदन का अपमान है । यह गुण्डागर्दी के आधार पर सदन का संचालन कराना चाहते हैं, यह निश्चित रूप से निन्दनीय है । मान्यवर, मैं इस कृत्य के लिए आपसे अपील करना चाहता हूं कि मंत्री जी इसके लिए क्षमा मांगें, निश्चित रूप से उसके बाद ही कार्यवाही का संचालन होगा ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, इस समय जो कुछ सदन में हुआ ।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य के कुछ कहने पर)

तुम गूँगे बैठे रहोगे, तो मैं ही बोलूंगा ।

अध्यक्ष जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल की ओर से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, जो कुछ हुआ, आप प्रत्यक्ष साक्षी हैं । आपको यहां आते हुए दो दशक हो गए हैं, इस सदन में किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, यह भी आपके सामने स्पष्ट है, जो कुछ भी अभी सदन में घटा है, शायद वह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है । कम से कम इसकी रक्षा करने का जो दायित्व इस पीठ का है, उसका निर्वाह करते हुए आप इस सदन की गरिमा को बचायें और भविष्य में ऐसा न हो इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी-बड़ी गर्म बातें होती हैं, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त है, मैं भी कहता हूं, लेकिन अल्फाज ऐसे कि किसी को ज्यादती महसूस न हो और बातें निपट जाती हैं, उसमें कोई जातीय कटुता नहीं होती । नेता प्रतिपक्ष अभी कह रहे थे, मैं तो उनसे कभी नाराज होता ही नहीं हूं । हमें बाहर भी निकलना है, हमें एक-दूसरे से नमस्कार और सलाम के रिश्ते भी रखने हैं । हम एक दूसरे की खुशी और गम में भी शरीक होंगे । हमें तकलीफ है कि जो भी शब्द कहे गये, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वह कितने गम्भीर थे, कितने गैर गम्भीर थे लेकिन इतना जरूर है कि जो सुना गया वह ऐसा जरूर था जो अफसोसजनक था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए । मुझे इसके लिए तकलीफ है, खेद है । मैं चाहता हूं कि इधर से और उधर से कोई ऐसी बात न हो जिससे किसी की जातीय तौहीन हो ।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया है, मैं इसे दिखवा लूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष जी, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया है अब इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए ।

श्री लालजी टण्डन-

संसदीय कार्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सदन की गरिमा के अनुसार जो अनुचित था, उसे अनुचित ही कहा है । लेकिन ऐसे मौके पर अगर संसदीय कार्यमंत्री जी को या मुझे अपने सदस्यों की तरफ से खेद व्यक्त करना पड़े तो हम लोगों के लिए उचित नहीं है ।

जब यह शब्द मंत्री महोदय ने कहा था तो मंत्री महोदय यह कह देते कि मैं यह शब्द वापस लेता हूं। इससे हमारे मंत्रीगणों को ट्रेनिंग भी मिल जायेगी । मैं जब नेता सदन वहां ऊपर था तो मैं दिन में 5 बार माफी मांग लेता था । सदन से बड़ा कोई नहीं है । सदन से माफी मांगने में क्या परेशानी है । मैं बधाई देता हूं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस शब्द की संवेदनशीलता को महसूस किया ।

श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पण्डित सिंह-

मान्यवर, हम तो बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे बीच में श्री डी0 प्रसाद अहिरवार जी वहाँ से बार-बार बोल रहे थे । हमने सिर्फ इतना कहा कि सुन लीजिए । हमने कोई अपशब्द नहीं कहा । अगर इससे डी0 प्रसाद अहिरवार जी को कोई तकलीफ हुई है तो हम खेद प्रकट करते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस बात को समाप्त करते हैं ।

राजधानी लखनऊ में चेचक से पीड़ित रोगियों की जानकारी एवं बचाव के उपाय

***2-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-**

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ में चेचक (चिकनपाक्स) फैल रहा है और माह दिसम्बर, 2004 में विकास नगर मौहल्ले में चेचक के चार रोगी मिले हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वेक्षण कराकर चेचक से पीड़ित रोगियों को चिन्हित करके उसके बचाव के कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह-)

वर्तमान में जनपद लखनऊ में चेचक (चिकनपाक्स) का प्रकोप नहीं है तथापि दिसम्बर, 2004 में विकास नगर मौहल्ले में चिकनपाक्स के 04 रोगी प्रकाश में आये थे । तदनुक्रम में प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर रोगियों को चिन्हित कर उपचारात्मक कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैंने सीधा प्रश्न किया था कि क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चेचक (चिकनपाक्स) फैल रहा है ? उत्तर सुन लें-वर्तमान में जनपद लखनऊ में चेचक (चिकनपाक्स) का प्रकोप नहीं है । मैंने कहा है कि चेचक फैल रहा है । आगे उत्तर में दिया है, कि तथापि दिसम्बर, 2004 में विकास नगर मौहल्ले में चिकनपाक्स के 04 रोगी प्रकाश में आये थे, इसमें इन्होंने यह बात स्वीकार की । आगे इन्होंने अपने उत्तर में दिया है कि तदनुक्रम में प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर रोगियों को चिन्हित कर उपचारात्मक कार्यवाही की गयी । मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या आप उसके बचाव के कोई उपाय करेंगे ? आपका उत्तर है कि चिन्हित करके उपचारात्मक कार्यवाही की गयी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो चेचक के मरीज लखनऊ में मिल रहे हैं, मेरी आज की जानकारी में बक्शी का तालाब में 4 दर्जन चेचक के रोगी वहाँ पड़े हुए हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है, सरदार नगर और लखनऊ के अनेक मौहल्लों में यह चेचक

के मरीज बराबर मिल रहे हैं । आपने कोई सर्वेक्षण कराने की बात नहीं कही बल्कि आपने कहा कि प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर रोगयों को चिन्हित कर उपचारात्मक कार्यवाही की गयी । मेरा प्रश्न है कि पूरे लखनऊ में चेचक के मरीजों के सर्वेक्षण कराकर कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे ? नम्बर-2, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन अभियान, पोलियो अभियान आदि फेल हो गये । तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार चेचक (चिकनपाक्स) के उन्मूलन के लिए कोई अभियान चलाएगी ?

श्री जयवीर सिंह-

संभवत: माननीय श्री श्रीवास्तव जी को पूरा संज्ञान नहीं है । मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि स्माल पाक्स और चिकन पाक्स में अन्तर होता है । स्माल पाक्स का उन्मूलन पूरे विश्व से हो गया है । स्माल पाक्स के निवारण हेतु विश्व बैंक पोषित योजना थी । जब इसका उन्मूलन विश्व से हो गया है, तो वह समाप्त हो गयी है चिकन पाक्स के बारे में कहना चाहूंगा कि यह वायरल इन्फेक्शन है । इसमें बुखार आता है और उ के बाद शरीर में फफोले पड़ जाते हैं । आम जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको इसका ज्ञान नहीं है वह इसे चेचक कहने लगती है ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या यह ज्ञानी नहीं हैं ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं वह तो ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं । तो मैं यह कह रहा था कि जो चिकन पाक्स है, यह जो यूनिवर्सल टीकाकरण की योजना थी उसमें यह शामिल नहीं था और यह राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी शामिल नहीं है । इसमें बुखार हो जाता है और शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और दस से चौदह दिनों के अन्दर यह फफोले स्वत: ही समाप्त हो जाते हैं। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा रोगी नहीं है जो चिकन पाक्स के कारण मरा हो । फिर भी हम उपचार की समुचित व्यवस्था कर रहे हैं । माननीय सदस्य ने विकास नगर का हवाला दिया तो मैं यह बताना चाहूंगा, कि वहां पर चार रोगी थे । दस तारीख को उपचार करने के लिए भर्ती किया गया था लेकिन उनका उपचार करके डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है । पूरे प्रदेश में चिकन पाक्स के कारण किसी की मौत नहीं हुई है ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है । मैं दोबारा प्रश्न कर रहा हूं । मैंने यह कहा कि क्या लखनऊ में सर्वेक्षण कराकर, मैं सर्वोदय नगर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे लखनऊ में सर्वेक्षण कराने का कष्ट करेंगे तथा कोई प्रिवेन्टिव एक्शन लेंगे जिससे भविष्य में चिकन पाक्स न फैले ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जहां भी यह बतायेंगे, हम उसको दिखवा लेंगे । चूंकि भारत सरकार के जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उसमें चूंकि स्माल पाक्स का उन्मूलन हो चुका है और चिकन पाक्स इस श्रेणी में नहीं आता है । यह केवल वायरल इन्फेक्शन है, इसका हम समुचित उपचार करा रहे हैं और इसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था समुचित रूप से करा रहे हैं । पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जिससे किसी की मौत हुई हो ।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी हो गया, अब आप बैठ जायें । माननीय मंत्री जी का पूरा उत्तर आ गया है ।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मुझे एक अनुपूरक पूछ लेने दें । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक भी मौत नहीं हुई है और यह वायरल इन्फेक्शन से है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं, कि इससे बचने के लिए समस्त जनपदों में क्या व्यवस्था की गयी है, क्या-क्या मैडिसिन इस्तेमाल की जा रही हैं ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, वर्ष 2002-2003 में जब आपकी सरकार थी तो दवाओं के लिए चौंसठ करोड़ का बजट मद में उपलब्ध था । आदरणीय मुलायम सिंह जी की जब सरकार आयी तो उसने उसको दो गुना बढ़ाकर अर्थात् एक अरब तेइस करोड़ का बजट उपलब्ध कराया है । मान्यवर, किसी भी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में दवाओं की कोई कमी नहीं है । दवाएं भरपूर उपलब्ध कराई जा रही हैं, हर जगह दवा उपलब्ध है ।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में सी0 टी0 स्कैन मशीन लगाने की योजना की जानकारी

***3-श्री राम इकबाल सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन मशीन लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं ।

प्रत्येक जनपद में सी0टी0 स्कैन लगाने की योजना नहीं है, फिर भी क्षेत्रीय निदान केन्द्रों में भारत सरकार पोषित योजना के अन्तर्गत 13 जनपदों में एवं प्रदेश सरकार द्वारा 3 चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2004-2005 में धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ।

श्री राम इकबाल सिंह-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सम्वेदनशील प्रश्न का उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था, महोदय, आजादी के 58 वर्ष हो गए हैं, यह एक तरीके से प्राथमिक चिकित्सा है सी0 टी0 स्कैन मशीन, तमाम लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, अभी दिल्ली में भी एक महाविद्यालय

में इस सम्बन्ध में जांच हुई जिसमें 63 लोगों का ब्लड प्रेशर हाई पाया गया और वह मानसिक रूप से परेशान हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

अब तो रामदेव महाराज के शिविर भी लगते हैं ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

तो फिर आप रामदेव महाराज जी के सरकारी शिविर का आयोजन करा दें, जिससे सारे विधायक लोग लाभ ले सकें ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, इतने गम्भीर सवाल पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि वह 13 जनपद कौन-कौन हैं और उनमें कहां-कहां इसकी व्यवस्था की गई है ? जहां केन्द्र सरकार द्वारा संतृप्त किया गया है तथा तीन जनपद वह कौन हैं, जहां राज्य सरकार द्वारा संतृप्त किया गया है ? दूसरा प्रश्न यह है, मान्यवर, बलिया के लोगों को सी0 टी0 स्कैन के लिए 200 कि0मी0 दूर बनारस में आना पड़ता है, तो क्या इस वर्ष में माननीय मंत्री जी बलिया में सी0 टी0 स्कैन की व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे ? वैसे भी बलिया तो समाजवादी पार्टी के महान नेताओं की, श्री जय प्रकाश नारायण बगैरह की पावन जन्म भूमि रही है तो क्या उनके जनपद में सी0 टी0 स्कैन की व्यवस्था इस साल आप करा देंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने 13 जनपदों के बारे में जानकारी चाही है तो मैं बता दूं-

1-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ ।
2-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, वाराणसी ।
3-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजियाबाद ।
4-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर ।
5-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद ।
6-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर ।
7-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, आगरा ।
8-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, झांसी ।
9-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद ।
10-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ ।
11-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, फैजाबाद ।
12-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बरेली ।
13-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोण्डा ।

मान्यवर, उपरोक्त 13 जनपद भारत सरकार द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत हैं । अब मैं राज्य सरकार द्वारा जिन तीन जिलों में यह व्यवस्था की जा रही है, उनके नाम बता देता हूं-

1-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय (सिविल), लखनऊ ।

2-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ओपेक चिकित्सालय, बस्ती ।

3-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पी0 एल0 शर्मा चिकित्सालय, मेरठ ।

जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है मान्यवर, जो तीन स्टेट गवर्नमेण्ट से तथा आर0डी0सी0 में जो 13 जिलों में व्यवस्था की गई है तो उसमें मध्य क्षेत्र में लखनऊ, पूर्वी क्षेत्र में बस्ती और पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ में इस तरह की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैंने बलिया जनपद के बारे में विशेष रूप से पूछा है, जो समाजवादी पार्टी के महान नेताओं की जन्म भूमि है और सरकार भी समाजवादी पार्टी की ही है, तो क्या सरकार इस बजट में सी0टी0 स्केन की व्यवस्था बलिया में करायेगी ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, एक करोड़ से ऊपर सी0टी0 स्केन लगाने में लागत है, प्रदेश में जैसे-जैसे संसाधन होंगे, हम इसकी व्यवस्था करायेंगे ।

(माननीय सदस्य जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब, आपके बस्ती जिले में तो सी0 टी0 स्केन की व्यवस्था है ।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बस्ती में जो ओपेक अस्पताल है, उसको इससे आच्छादित किया है । मान्यवर, ओपेक देशों की वाह्य सहायता से पाँच सौ बिस्तरों का अस्पताल बस्ती में स्थापित है, जहां नेपाल, बस्ती और सिद्धार्थनगर, सन्त कबीर नगर और तमाम पड़ोसी जिलों के लोग उससे कवर होते हैं । मान्यवर, कुछ चिकित्सालयों को यहां के पी0जी0आई0 के माध्यम से सटेलाइट के द्वारा जोड़ने का फैसला किया गया है । मेरा प्रश्न है कि क्या उसे ओपेक देशों के द्वारा निर्मित पाँच सौ बेड के अस्पताल को पी0जी0आई0 की सेटलाइट प्रणाली के माध्यम से जोड़ने का फैसला लेंगे ? मान्यवर अभी बताया गया कि सी0टी0 स्केन की व्यवस्था वहां की गई है तो जो सूचना है वहां न्यूरो सर्जन और हृदय रोग विशेषज्ञ दोनों के पद रिक्त हैं जो सृजित भी हैं तो क्या उन दोनों पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में यहां सरकार का गठन होते ही, हमारी सरकार ने आम जनता और गरीब जनता के हित में उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिये हैं । हमने यह भी निर्णय लिया है कि जो उत्तर प्रदेश के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बराबर संसाधन उपलब्ध कराने की कार्ययोजना है । इसी

तरह से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनको जिला चिकित्सालय के बराबर संसाधन उपलब्ध कराने का विचार है । इसी तरह से जो जिला चिकित्सालय हैं, उनको मेडिकल कालेज के बराबर संसाधन उपलब्ध कराने की कार्य योजना है । मान्यवर, जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध होते रहेंगे, प्रदेश सरकार की मंशा है कि आम जनता तक सभी सुविधाएं पहुंचें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, जहां हम सी0टी0 स्केन मशीन उपलब्ध करा रहे हैं वहां टेक्नीशियन और दूसरे चिकित्सा अधिकारियों के खाली स्थानों की बात है, मान्यवर, अभी तक तो यह बात चलती आ रही थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तो एम0डी0 और एम0एम0 शिक्षित डाक्टर तैनात हैं, जबकि जिला चिकित्सालयों में एम0बी0बी0एस0 डाक्टर ही तैनात हैं । मान्यवर, इसी दृष्टिकोण से हमने विशेषज्ञ और नान-विशेषज्ञ का अलग-अलग कैडर करने का निर्णय लिया है जिसे हम 31 मार्च तक पूरा करने जा रहे हैं । मान्यवर, इसके अतिरिक्त जहां पर डाक्टरों की कमी है वहां पर संविदा पर डाक्टरों को रखने का निर्णय किया है । मान्यवर, इस दिशा में हमारी सरकार चिंतित है और हम चाहते हैं कि प्रदेश में हर व्यक्ति को चिकित्सा उपचार हेतु डाक्टर की सेवायें उपलब्ध रहें और दवायें समुचित रूप से उपलब्ध रहें, यह हमारी सरकार का मान्यवर, प्रयास है ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब आपका प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि मेरठ में सी0टी0 स्केन की मशीन स्थापित करने जा रहे हैं, क्या उसके संबंध में आदेश निर्गत हो गए हैं और यदि हां, तो कब तक वहां स्थापित हो जायेगी ? और क्या उस मशीन को आपरेट करने के लिए और उसकी परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए टेक्नीशियन और चिकित्सक की नियुक्ति भी साथ-साथ की जायेगी ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, जहां जहां मशीनें उपलब्ध की जा रही हैं वहां विशेषज्ञ भी तैनात किये जा रहे हैं । खरीद की प्रक्रिया अंतिम रूप से हो गयी है और इसी वित्तीय वर्ष में मशीनों के खरीद की प्रक्रिया सम्पन्न हो जायेगी ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, खुशी की बात है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर वाराणसी में जो चिकित्सालय है वह सी0टी0 स्केन मशीन से आच्छादित है, आपको बधाई है । मान्यवर, क्या जिनको सी0टी0 स्केन मशीन से जांच के लिए रिकमेंड किया जायेगा क्या उनसे कोई शुल्क भी लिया जायेगा?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, सारे परीक्षण जितने भी चिकत्सालयों में होते हैं उनका एक शैड्यूल बना हुआ है पूरा प्रदेश का, उसका जो शैड्यूल है, वह लगेगा ।

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी करने पर विचार

***4-श्री राम करन आर्य-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए क्या सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद-)

दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि दिनांक 28.1.2004 से की गयी है तथा बढ़ी हुई दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है । पूर्व दशम् कक्षाओं (कक्षा 1 से 10 तक) के छात्रों को कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 25 रुपये कक्षा 6 से 8 तक 40 रुपये तथा कक्षा 9 व 10 के छात्रों को 60 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति की दरें स्वीकृत हैं, जो छात्रों को वितरित की जा रही हैं ।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार ।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह केवल हाई स्कूल तक का ही है, इसमें विवरण दिया गया है । मैंने सवाल किया था कि क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए क्या सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? तो यह प्रश्न केवल 10वीं कक्षा तक का ही नहीं था बल्कि स्नातक, परास्नातक और विधि के छात्र का भी था और सम्पूर्ण छात्रों का है । पहली बात है कि इसमें केवल 10वीं कक्षा तक है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास रिपोर्ट है कि स्नातक और विधि के छात्रों का क्या है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि मैंने मंहगाई के अनुसार बात कही थी तो क्या सरकार 28.1.2004 से पहले कितनी छात्रवृत्ति थी और कितना बढ़ाया गया है क्या यह मंहगाई के अनुपात में है और नहीं है तो क्या इसे मंहगाई के अनुपात में बढ़ायेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 28.1.2004 से यह बढ़ाया गया है और यह बढ़ी हुई दरें लागू हैं वर्ष 03 से, तो इसमें कितना-कितना बढ़ा है यह सामूहिक क, ख, ग और घ का एक चार्ट है । आप कहें तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

उनको चार्ट दे दें ।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, ठीक है, उसमें सभी का है, यह जानकारी उनको मिल जायेगी यह दरें हैं ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में इस बढ़ी हुइ दरों के आधार पर, जो जनपदों में डिमान्ड है विभिन्न महाविद्यालयो या विद्यालयों की, उनके अनुकूल बजट सभी जिलों मे भेज दिया गया है ।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जहां तक बजट भेजने का सवाल है तो यह हमारी सरकार माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में है पिछली बार भी बजट बहुत पहले पास हुआ था । इस दिशा में निर्देश दे दिये गये हैं कि 15 मार्च तक निश्चित रूप से छात्रवृत्ति के संबंध में बजट भेज दिया जाय और काफी मात्रा में बजट भेज दिया गया है ।

प्रदेश में बेरोजगार विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

***5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों के उत्थान के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गयी है ? क्या मुख्य मंत्री बेरोजगार विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेंगे ?- यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)(श्री श्याम नारायन-)

प्रदेश मे विकलांगों के उत्थान के लिए निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं :--

(1) विकलाग छात्रों हेतु विशेष विद्यालय ।

(2) विकलांगों हेतु विशेष कर्मशाला ।

(3) विभिन्न श्रेणी के निराश्रित विकलांग व्यक्तियों हेतु भरण-पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन)।

(4) विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना ।

(5) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत कराने हेतु सहायक अनुदान योजना ।

(6) विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना ।

(7) विकलांगों के पुनर्वास हेतु दुकान-निर्माण/संचालन योजना ।

(8) विकलांगों को राज्य परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की योजना ।

(9) विकलांगता-निवारण हेतु शल्य चिकित्सा के लिए अनुदान ।

(10) दक्ष विकलांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों आदि को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना ।

(11) विकलांगता निवारण के लिए प्रचार प्रसार में संलग्न स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु अनुदान ।

प्रदेश के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल बेरोजगार विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की कोई योजना नहीं है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं सिर्फ दो छोटे-छोटे सवाल करना चाहता हूं । बेरोजगारी अपने आपमें अभिशाप है। बेरोजगार और विकलांग भी हो तो कितना बढ़ा अभिशाप हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बेरोजगार विकलांग सीधे-सीधे रोजी-रोटी पा सकें, इस तरह की कोइ योजना सरकार की है और दूसरा प्रश्न कि जो माननीय मंत्री जी के उत्तर में है कि विकलांग के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना, तो इसका जिलों में क्या लक्ष्य है और उसके लिये कितना रुपया एक विकलांग को दिया जाता है ?-

श्री श्याम नारायन-

मान्यवर, विकलांगों के लिये हमारी चिन्ता सबकी चिन्ता समान है । यह हमारे पूरे समाज के लिये ऐसा पहलू है, जो संवेदनशील पहलू है । हमें चिन्ता है आपको भी चिन्ता है । यह एक आपदा है । विकलांगता किसी के परिवार को कब ग्रसित कर ले, कोई नहीं जानता । इसमें आप प्रश्न कर रहे हैं, तो मैंने जवाब दिया कि बेरोजगार विकलांगों को रोजगार भत्ता नहीं दे सकते लेकिन 3 प्रतिशत सभी सरकारी सेवाओं में विकलांगों के लिये जगह आरक्षित कर दी गई हैं । यद्यपि इसमें कुछ जटिलतायें हैं । अगर 100 रिक्तियाँ हैं तो 3 जगह उनको मिलेगी । यदि 35 रिक्तियाँ हैं तो एक मिलेगी । इस हिसाब से सेना में और पुलिस बल को छोड़कर और जगह ऐसी रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हो पातीं । यह एक जटिलता है, उसके उपरान्त भी हमारी सरकार जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चल रही है, अत्यन्त संवेदनशील सरकार है । समाज का जो अन्तिम व्यक्ति है, उसके चेहरे पर भी हँसी-खुशी देखना चाहती है । हमारी तरफ से बराबर हर विभागों को लिखा गया है कि इनको प्राथमिकता दी जाय, विकलांग बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाय । अनुस्मारक भी बार-बार भेजा है, क्या कार्यवाही हो रही है, एक प्रश्न तो यह है । दूसरा प्रश्न आपका जो है, आप प्रश्न को दुहरा दें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं यह जानना चाहता हूं कि विकलांगों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/संचालन की जो योजना है, उसका प्रदेश में कितना लक्ष्य है, हर जिले में कितना लक्ष्य है और उसके लिये प्रत्येक विकलांग को कितना रुपया दिया जाता है ?

(सदस्य श्री अमरजीत सिंह जनसेवक के खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आप तो सदन में आ गये, हर विकलांग का यह भाग्य कहां है ?

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

मान्यवर, जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है कि तीन फीसदी का आरक्षण विकलांगों के लिए है, उसमें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जितनी संख्या में भर्ती होंगी, क्या उन नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे ? जैसे फतेहपुर में 20, बलिया में 27, रायबरेली में 28, सीतापुर में 30 नियुक्तियाँ हुईं तो यदि सारी नियुक्तियों को एक साथ जोड़ने के बाद माननीय मंत्री जी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे तो विकलांगों को ज्यादा लाभ मिल सकता है । मान्यवर, यह किसी पक्ष से जुड़ा प्रश्न नहीं है, यह एक संवेदनशील प्रकरण है, इसमें मैं केवल इतना ही जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी व्यवस्था कर देंगे ?

श्री श्याम नारायन-

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह एक संवेदनशील पहलू है और आपकी चिन्ता वाजिब है, हम उससे अपने को सम्बद्ध करते हैं । साधन उपलब्ध होने पर हमारी सरकार इसे अवश्य करेगी। ऐसी दिशा में हम कदम उठायेंगे और उसमें आपकी भी राय लेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

यह आपका प्रश्न अच्छा था । यह सही है कि कहीं पर 20 रिक्तियाँ हैं, कहीं पर 15 रिक्तियाँ हैं, इस पर विचार किया जायेगा और इसका समाधान होगा । दूसरे खन्ना साहब ने जो प्रश्न रखा था, वह भी बड़ा गम्भीर है । यह जरूरी नहीं है कि हम किसी एक विभाग से ही विकलांगों की सहायता कर सकते हैं । डूडा के द्वारा हम विकलांगों की सहायता करते हैं, जिनके पास पैर नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, उन लोगों को हम किड्स भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, अचार-मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग देते हैं और पैसा भी उपलब्ध कराते हैं । जहां तक रहने का प्रश्न है, बैनबे स्कीम में विकलांगों का भी कोटा है। अगर इस तरह के कोई हों तो उन्हें आप बता सकते हैं ।

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, विकलांगों की तरफ से जो जी0ओ0 जारी हुआ है कि विकलांगों के लिए विधायक निधि से 3 परसेंट खर्च कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, मुझे प्रश्न नहीं करना है । माननीय मंत्री जी इस प्रकार का निर्देश दे दें, जिससे कि हम लोग अपनी विधायक निधि से 3 परसेंट विकलांगों की सहायता के लिए दे सकें ।

खाद्य पदार्थों व दालों में मिलावट की रोकथाम हेतु उपाय

***6-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-**

क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि चटरी (खेसारी दाल) में न्यूरोटाकिसन होने के कारण इसके खाने से मनुष्यों को दोनों पैरों की अपंगता होने का खतरा रहता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सस्ती अरहर की दाल में उसकी मिलावट को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां ।

खाद्य पदार्थों व दालों में मिलावट की रोकथाम हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन जनपदों में ब्लाक स्तर पर कुल 487 खाद्य निरीक्षक तैनात हैं तथा विभिन्न नगर निगम/नगर पालिकाओं में नगर विकास विभाग के अधीन खाद्य एवं स्वच्छता निरीक्षक कार्यरत हैं । अरहर व अन्य दालों में खेसारी की मिलावट की रोकथाम तथा अपमिश्रण कर्ताओं को दण्डित किये जाने हेतु जनपदों

में खाद्य निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से नमूने एकत्रित किये जाते हैं तथा एकत्रित नमूनों की प्रयोगशाला से जांच कराकर अपमिश्रणकर्ताओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 व तत्संबंधी नियमावली, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोजन दाखिल कर दण्डित कराये जाने की कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप इसे न पढ़ें, माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, केवल इसका जवाब दे दें ।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, आज खाद्य की समस्या है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह खेसारी दाल है, इसके उत्पादन पर रोक है या इसे बनाने पर रोक है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, इसकी मिलावट दाल में हो जाती है, जिसके कारण मनुष्यों में विकलांग होने का खतरा रहता है । जो लोग ऐसा करते हैं, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

उत्तर प्रदेश के चिकित्सालयों में एक्सरे टेक्नीशियनों के पदों के सृजन पर विचार

***7-श्री जगदम्बिका पाल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सालयों में अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार शैय्या के मानक के अनुसार 30 शैय्या पर एक, 100 शैय्या पर दो, 200 शैय्या पर तीन, 300 शैय्या पर पांच, 500 शैय्या पर आठ तथा 24 घंटे इमरजेन्सी सेवा वाले चिकित्सालयों में दस एक्सरे टेक्नीशियनों के पदों के सृजन पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव-)

जी नहीं । एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों का सृजन चिकित्सालयों में शैय्या की संख्या के आधार पर नहीं किया जाता है ।

शासनादेश संख्या-2942 सेक-2/5-4(89)/84, दिनांक 01.09.1986 द्वारा एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों का मानक मशीनों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

प्रदेश में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी

***8-श्री कौशल किशोर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों के नियुक्ति प्राधिकारी

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

स्वास्थ्य सचिव हैं ? क्या शासनादेश के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षकों को केवल मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन ही कार्य करने के निर्देश हैं ? क्या यह सही है कि उक्त शासनादेशों का अतिक्रमण करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्रांक संख्या निदे0स्वा0/28फ/1892, दिनांक 4-11-03 के द्वारा खाद्य निरीक्षकों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र एवं अधीक्षक, सा0 स्वा0 केन्द्र दोनों के अधीन रहने, कार्य करने व वेतन प्राप्त करने के आदेश निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 4-11-03 को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

शासनादेश संख्या-903/16-10-1983, दिनांक 25-02-1983 द्वारा जिला स्तर पर मुख्य खाद्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षक संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रखे गये हैं ।

महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या-निदे0 स्वा0/कैम्प/1892, दिनांक 4-11-2003 द्वारा खाद्य निरीक्षकों को मूल तैनाती स्थान सा0 स्वा0 केन्द्रों/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किये जाने तथा वेतन का भुगतान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर आहरित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।

जी नहीं ।

उक्त आदेश के द्वारा खाद्य निरीक्षकों की उनकी तैनाती के क्षेत्र में जनहित में नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है ।

प्रदेश में पी0एस0डब्लू0 (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र

1-डा0 सुशील चौधरी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पी0एस0डब्लू0 (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र हैं ? उनमें से कितने केन्द्र बन्द हैं और कितने संचालित हैं ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बन्द प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार बन्द प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन-)

प्रदेश में वर्तमान में 40 बी0 एच0 डब्लू0 (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र हैं । कोई प्रशिक्षण केन्द्र बन्द नहीं है । इनमें से 26 प्रशिक्षण केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण वर्तमान समय में चल रहा है ।

शेष 14 प्रशिक्षण केन्द्रों जिन पर वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण नहीं चल रहा है उन केन्द्रों पर कुल 81 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर शीघ्र प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा ।

जन विश्लेषक, लखनऊ प्रयोगशाला लखनऊ के डा0 एन0 सी0 तिवारी के प्रमाण-पत्र व रिकार्ड की जांच की मांग

2-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एन0 सी0 तिवारी, जन विश्लेषक, लखनऊ प्रयोगशाला, लखनऊ के प्रमाण-पत्र व रिकार्ड की जांच करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-/105640/2004, दिनांक 2-8-2004 प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ । संदर्भित आदेश दिनांक 2-8-2004 विभाग में प्राप्त हुआ है, जो डा0 एस0 सी0 तिवारी के संबंध में है न कि डा0 एन0 सी0 तिवारी के सबंध में ।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अन्नपूर्णा एवं अन्त्योदय योजना कार्ड धारकों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

3-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्नपूर्णा एवं अन्त्योदय योजना कार्डधारकों की संख्या बढ़ाये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुँ0 रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया-)

जी नहीं । अन्नपूर्णा एवं अन्त्योदय योजना के कार्ड धारकों की संख्या का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास परियोजना अधिकारियों की पदोन्नति की मांग

4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में 31-12-2004 को जिला कार्यक्रम अधिकारी के कितने पद रिक्त थे ? क्या यह सत्य है कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों को 14 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने पर पदोन्नति वेतनमान (रु0 8000-13500) स्वीकृत किये जाने के वाबजूद उन्हें सेवा नियमावली के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी-)

दिनांक 31-12-2004 को 30 जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद रिक्त थे ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण न करने के कारण बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पदोन्नत किया जाना संभव नहीं था-अत: वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के धनवन्तरी छात्रावास की मरम्मत हेतु सरकार से धन की मांग

5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ने वाले छात्रों के रहने हेतु बना हुआ धनवन्तरी छात्रावास अत्यन्त जीर्ण शीर्ण है तथा चारों तरफ की चहार दीवारी गिर गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रावास भवन की मरम्मत कार्य करने के लिए धन आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-)

जी हाँ ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् उ0प्र0 लखनऊ द्वारा बिना शासन की स्वीकृति के अम्बेसडर गाड़ी क्रय कर उसके दुरुपयोग किये जाने की जांच

6-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश में जनवरी, 2005 चिकित्सा परिषद् के चेयरमैन एवं कार्यवाहक रजिस्ट्रार द्वारा बिना शासन की स्वीकृति एवं वित्तीय प्राविधान के एक एम्बेसडर गाडी क्रय कर ली गयी है तथा पूरे प्रदेश में भ्रमण कर परिषद् के धन का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करके दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासन की बिना स्वीकृति के बिना 28 दिसम्बर, 2004 को एक एम्बेसडर कार क्रय की गयी है । उक्त अनियमित क्रय एवं गाड़ी के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु शासन के आदेश दिनांक 4-2-2005 द्वारा निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ को निर्देशित किया गया है । जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 मोख्तार अहमद अन्सारी, जिला चिकित्सालय गाजीपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

7-श्री मोख्तार अंसारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 मोख्तार अहमद अन्सारी, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में कुल कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्तियां करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

डा0 मोख्तार अहमद अन्सारी, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर में श्रेणी "क" चिकित्सा अधिकारी के दो पद तथा श्रेणी "ख" चिकित्सा अधिकारी के 14 पद स्वीकृत हैं ।

वर्तमान में जिला चिकित्सालय, गाजीपुर में श्रेणी "क" के 06 तथा श्रेणी "ख" के 10 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं ।

रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य महिला आयोग में दर्ज मुकदमें

8-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य महिला आयोग में 1 जनवरी, 2004 से 31-12-04 तक हरिजन उत्पीड़न, बलात्कार, जान से मारने की धमकी, दहेज हत्या, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज न करने के कितने मामले दर्ज किये गये हैं ? प्राप्त मामलों में कितने में अब तक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राज्य महिला आयोग में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31-12-2004 तक निम्न मामले दर्ज किये गये :--

हरिजन उत्पीड़न	262
बलात्कार	99
जान से मारने की धमकी	467
दहेज हत्या	118
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज न करने के मामले	973

प्राप्त सभी प्रकरणों में राज्य महिला आयोग के स्तर से कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भारतीय चिकित्सा परिषद् उ0प्र0 में वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में यात्रा भत्ता, पेट्रोल व्यय, होटल व्यय में की गई धनराशि की जानकारी व जांच की मांग

9-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या चिकत्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 में वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में यात्रा भत्ता, पेट्रोल व्यय, टैक्सी किराया, होटल व्यय में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि भा0 चि0 परिषद् में इन मदों के लिए धन की व्यवस्था न होने पर भी अनियमित रूप से धन का आहरण कर अपने पद का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ में वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल दिनांक 26-11-2002 से अब तक यात्रा भत्ते पर रुपये 1,33,430/-, डीजल पर रुपये 26,395/- एवं एम्बेस्डर कार के अनुरक्षण पर रुपये 26,116/-, टैक्सी किराया पर रुपये 1,58,291/-, होटल किराये पर रु0 58,305/- अर्थात् उपर्युक्त मदों पर अब तक कुल रुपये 4,02,537/- की धनराशि व्यय की गयी है।

उपर्युक्त मदों पर व्यय की गयी उपरोक्त धनराशि के अनियमित व्यय एवं अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु शासन के पत्र दिनांक 04-02-2005 द्वारा निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ को आदेश दिया जा चुका है । जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला कल्याण विभाग, लखनऊ में तैनात श्री बाबू राम मित्रा, लिपिक के विरुद्ध छात्रवृत्ति में की गई अनियमितता की जांच की मांग

10-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वर्तमान में महिला कल्याण, विभाग में तैनात श्री बाबू राम मित्रा, लिपिक के विरुद्ध वर्ष 1982 से 1985 तक अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति में की गयी अनियमितताओं के संबंध में प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर थाना हसनगंज जनपद लखनऊ में श्री छोटेलाल पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 443/96 अन्तर्गत धारा 420/467/468/471/409 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज किया गया था?यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त दोषी कर्मी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

दिनांक 7-3-2002 ।

विभाग द्वारा आरोपी को दिनांक 10-5-2002 को निलंबित किया गया था तथा अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया । मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-5-2002 के समादर में निलम्बन को समाप्त करके अनन्तिम रूप से बहाल किया गया है। विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी की जांच आख्या प्राप्त हो गई है जिस पर निर्णय विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला महिला चिकित्सालय गाजीपुर में रिक्त पदों पर महिला डाक्टरों की नियुक्ति का प्रकरण

11-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला महिला चिकित्सालय गाजीपुर में महिला डाक्टरों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में कुल कितनी महिला डाक्टर कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर महिला डाक्टरों की नियुक्ति करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जिला महिला चिकित्सालय गाजीपुर में महिला चिकित्सक के 14 पद स्वीकृत हैं जिसमें 5 महिला चिकित्सक कार्यरत हैं तथा 9 रिक्त पद हैं।

जी हाँ ।

उपरोक्त पदों पर विशेषज्ञ संवर्ग गठन के पश्चात चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर महिला चिकित्सालय मुहम्मदाबाद में चिकित्सकों के पदों पर तैनाती की मांग

12-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में महिला चिकित्सालय मुहम्मदाबाद में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार महिला चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

महिला चिकित्सक का एक पद स्वीकृत है ।

रिक्त पद पर तैनाती की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में सांसद निधि से लगाये गये हैण्ड पम्पों की जांच

18-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में उत्तर

प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा सांसद निधि से पोषित वर्ष 2000-01 में 100 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये थे ? क्या यह सही है कि उक्त हैण्ड पम्प मानक के अनुरूप नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये कार्यों की जांच तकनीकी समिति गठित करके करायेगी तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

सांसद निधि से पोषित वर्ष 2000-2001 में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम को 100 हैण्डपम्पों की धनराशि अवमुक्त की गयी थी जिसके सापेक्ष उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा 02 हैण्डपम्पों की धनराशि अभिकरण कार्यालय को वापस कर दी गयी थी। अधिष्ठापित 98 हैण्डपम्पों में से विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 57 इण्डिया मार्क-2 तथा शेष हैण्डपम्प का अधिष्ठापन विधान सभा क्षेत्र वीरापुर में कराया गया है ।

जी नहीं ।

इस संबंध में उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है तथापि हैण्डपम्पों की गुणवत्ता हेतु जांच के आदेश दे दिए गए हैं ।

दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही जांच रिपोर्ट के परिणाम पर निर्भर हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में सभी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों/ कर्मचारियों की तैनाती की मांग

14-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के अनुसार चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त तैनाती कब तक कर दी जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

रिक्त पदों को भरने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के विभिन्न भागों में रह रहे गोडिया/गोड जाति/धुरिया, नायक, ओझा को अनुसूचित जाति/ जनजाति में शामिल करने की मांग

15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गोडिया/गोड जाति/धुरिया, नायक, ओझा जो प्रदेश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं उन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल करते हुये प्रदेश

शासन ने कोई आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो क्या उसमें जनपद प्रतापगढ़ की उक्त जातियों को शामिल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं । शासनादेश संख्या-1442/26-818-1957 दिनांक 22 मई,1957 के अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड मण्डल और जनपद मिर्जापुर के दक्षिण स्थित कैमूर रेंज में गौंड जाति को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था । कालान्तर में यह मांग किये जाने पर कि गौंड जाति के लोग उक्त क्षेत्र से जाकर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी रहने लगे हैं, उन्हें वहाँ पर भी अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया जाय । भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के माध्यम से इंगित क्षेत्र से अन्यत्र जाकर बसे गौंड जाति के लोगों को सम्पूर्ण उ0प्र0 में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया । प्रदेश के 13 जनपदों महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में निवासरत उक्त गोंड जाति के लोगों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है शेष जनपदों में निवासरत उक्त गोंड जाति के लोग अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत हैं । भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 15-12-2003 में धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड को गौंड का पर्यायवाची स्पष्ट किया गया है।

जी नहीं ।

यह जातियां गोंड की पर्यायवाची नहीं हैं ।

उ0प्र0 सचिवालय डिस्पेंसरी में एक्स-रे टेक्नीशियन की मांग

16-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के राजभवन डिस्पेंसरी एवं सचिवालय डिस्पेंसरी में एक्स-रे मशीनें कार्यशील हैं, परन्तु एक्स-रे टेक्नीशियन के पद सृजित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों का सृजन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी हां ।

पद सृजिन के लिए प्रक्रियागत अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर पद सृजन किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय बस्ती, बलिया, पडरौना, उन्नाव में एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों की जानकारी

17-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला चिकित्सालय बस्ती, बलिया, पडरौना

(कुशीनगर) उन्नाव में एक्स-रे मशीनें कार्यशील हैं, परन्तु उन्हें संचालित करने वाले एक्स-रे टेक्नीशियन के पद सृजित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन चिकित्सालयों में एक्स-रे टेक्नीशियन के पद सृजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ । एक्स-रे टेक्नीशियन के पद का समायोजन करके एक्स-रे मशीनों का संचालन कराया जा रहा है ।

जी हाँ । जिला योजना अनुश्रवण समिति से परिव्यय उपलब्ध होने एवं प्रस्ताव अनुमोदित होने पर एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों का सृजन किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के एक्स-रे टेक्नीशियन को जोखिम भत्ता देने की जानकारी

18-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक्स-रे टेक्नीशियनों को उनके जोखिम भरे कार्यों को देखते हुए क्या सरकार जोखिम भत्ता/रेडियेशन रिस्क एलाउन्स देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ से स्थानान्तरित निदेशालय से सम्बद्ध चिकित्सकों की सम्बद्धता समाप्ति का प्रकरण

19-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में जनपद-लखनऊ से स्थानान्तरित किये गये ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो निदेशालय से सम्बद्ध कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उनकी सम्बद्धता समाप्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के टी0बी0 चिकित्सालय, ठाकुरगंज के चिकित्सक डा0 इन्तिसार हुसैन की सैन्य सेवाओं को सेवा में सम्मिलित करने की जानकारी

20-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के टी0बी0 चिकित्सालय, ठाकुरगंज में वर्तमान

उत्तर प्रदेश विधान सभा

समय में कार्यरत चिकित्सक डा0 इन्तिसार हुसैन की सैन्य सेवाओं को सेवा में सम्मिलित किया जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन लम्बित है ? क्या यह सही है कि इस संदर्भ में रिट पिटीशन सं0 753 (एस0बी0)/2001 मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा उनकी सैन्य सेवाओं को उनकी सेवा में जोड़ने हेतु दिनांक 28-5-01 में दो माह में अनुपालन किये जाने के आदेश पारित किये हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी सैन्य सेवाओं को जोड़कर उनकी वरिष्ठता निर्धारित कर दी गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? उक्त मामला कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी नहीं, प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ ने दिनांक 28-05-01 को याची की सैन्य सेवाओं को उनकी सेवा में जोड़ने हेतु आदेश पारित नहीं किये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति इस विषय पर याची के प्रत्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर हैदरगढ़ बाजार के दवा विक्रेताओं द्वारा बिना लाइसेंस के नकली तथा ई0एस0आई0 की आपूर्ति की दवाओं की बिक्री पर रोक एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

21-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के विकास क्षेत्र तारून के हैदरगढ़ बाजार में स्थित मेडिकल स्टोर्स के विक्रेताओं द्वारा बिना लाइसेंस के नकली तथा ई0एस0आई0 की आपूर्ति की दवाओं की बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषी विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

22-डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फार्मेसिस्टों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने फार्मेसिस्ट वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर फार्मेसिस्टों की नियुक्ति किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ 5070 पद स्वीकृत हैं ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी हाँ, अधियाचन माँगे गये हैं ।

समस्त जनपदीय अधिकारियों से अधियाचन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि गबन करने के सम्बन्ध में जानकारी

23-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रविदास मेहरोत्रा, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी का शिकायती पत्र दिनांक 28 जनवरी, 2005 जो जनपद सीतापुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत धनराशि गबन किये जाने के संबंध में था, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गोंड जाति की जनसंख्या व इन्हें अनुसूचित जाति के अनुमन्य सुविधायें दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

24-श्री अक्षयवर लाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में गोंड़ जाति की जनसंख्या कितनी है ? क्या गोंड जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इन्हें अनुसूचित जाति के अनुमन्य सुविधायें दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वर्ष 2001 की जनगणना में अनुसूचित जाति/जनजातिवार आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के क्रम में जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जनपदों में गोंड जाति अनुसूचित जनजाति में तथा उक्त जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में गोंड जाति पूर्व से ही अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित महिला चिकित्सालय गोलागंज व हजरतगंज में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती की जानकारी

25-श्री रामकरन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महा-निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य उ0प्र0 के पत्र संख्या निदेशक (सी)/2004/2999 दिनांक 25-6-2004 द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सम्बद्धता तत्काल समाप्त कर मूल तैनाती स्थान पर ही कार्य लिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो लखनऊ स्थित महिला चिकित्सालय गोलागंज एवं हजरतगंज लखनऊ में कितने और कौन-कौन तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं जिनकी मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक केन्द्र/प्रा0स्वा0 केन्द्रों पर मूल तैनाती है और लखनऊ में चिकित्सालयों से सम्बद्ध/तैनात हैं? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को वापस भेजने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

लखनऊ स्थित महिला चिकित्सालय गोलागंज में कोई सम्बद्ध नहीं है । महिला चिकित्सालय हजरतगंज में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला श्रीमती उर्मिला व एक वरिष्ठ लिपिक श्री तनवीर खाँ, तृतीय श्रेणी कर्मचारी सम्बद्ध हैं ।

जी हाँ ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्र दिनांक 28-2-2005 के द्वारा सम्बद्धता समाप्त करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अरबन मलेरिया फाइलेरिया कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों को केन्द्र के समान जोखिम भत्ता आदि प्रदान करने की मांग

26-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि अरबन मलेरिया फाइलेरिया कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों की वर्ष 1993 से सेवा नियमावली संशोधन केन्द्र के समान वेतनमान साइकिल भत्ता, जोखिम भत्ता देने संबंधी प्रकरण शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो उसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुलायम सिंह यादव-

अरबन मलेरिया फाइलेरिया कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों की सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन तथा वर्दी, जोखिम भत्ता व सुरक्षात्मक उपकरण की सुविधा दिये जाने के प्रकरण में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है, जबकि केन्द्र के समान वेतनमान तथा साइकिल भत्ता दिये जाने के प्रकरण पर वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गयी ।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरदोई के अवशेष देयों के भुगतान का प्रकरण

27-श्री बादशाह सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अबुल इरफान अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरदोई के पद से दिनांक 31-10-2004 को सेवा निवृत्त हुए थे ? क्या उनके अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

अल्पसंख्यक, हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)(हाजी याकूब)-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

पेंशन/ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की स्वीकृति हेतु प्रकरण अवर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को भेजा गया है । सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि के भुगतान किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायी जायेगी ।

प्रदेश में भिक्षुओं को पुनर्वासित करने की मांग

28-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय भिक्षुक गृह संचालित हैं और उनमें कितने भिक्षुक निरूद्ध हैं ? क्या निरूद्ध भिक्षुकों को पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में अब तक कितने भिक्षुओं को पुनर्वासित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रदेश में 08 भिक्षुक गृह-मथुरा, आगरा, कानपुर-नगर, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद (महिला) एवं फैजाबाद (पुरूष) संचालित हैं ।

वर्तमान में कोई भिक्षुक निरूद्ध नहीं है ।

जी नहीं । मात्र निरूद्ध अवधि में भिक्षुकों को विभिन्न व्यवसायों यथा सिलाई, बुनाई, चर्मकला, काष्ठकला एवं बेतकला आदि में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न संस्थाओं से मुक्त होने वाले संवासियों को प्रदान किये जाने वाले पुनर्वासन अनुदान की योजना वर्ष 1994 में महिला एवं बाल विकास विभाग में स्थानान्तरित हो जाने के कारण ।

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों में फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों को भरने की मांग

29-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी

चिकित्सालयों में फार्मेसिस्टों के कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

वर्तमान में प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों के 249 पद रिक्त हैं ।

इन रिक्त पदों की चयन की कार्यवाही प्रगति पर है एवं इसे पूर्ण कर यथाशीघ्र भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मधुमेह, कैंसर तथा एड्स के रोगियों की दवाओं की कमी को दूर करने के उपाय

30-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में मधुमेह, कैंसर तथा एड्स के रोगियों हेतु दवाओं की कमी है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मधुमेह व कैंसर के रोगियों हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाएं चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं तथा एड्स रोगियों में पाये जाने अवसरवादी संक्रमणों के उपचार हेतु लखनऊ तथा वाराणसी मेडिकल कालेजों में रू0 2,00,000/- की (प्रत्येक को) धनराशि एवं 07 मेडिकल कालेजों को रू0 50,000/ की धनराशि आवंटित की गई हैं । इसके अतिरिक्त एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0 लखनऊ को रू0 1,00,000- की धनराशि प्रदान की गयी है ।

61 जिला चिकित्सालय पुरूष एवं 53 जिला चिकित्सालय महिला को रू0 25,000/- की धनराशि आवंटित की गई है ।

एच0आई0वी0/एड्स संक्रमण रोक-थाम एवं इलाज हेतु निम्न नवीन योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं :-

1-पी0पी0टी0सी0टी0 कार्यक्रम ।

2-बी0एच0यू0 वाराणसी में स्थापित ए0आर0टी0 सेन्टर द्वारा एन्टी रिट्रोवायरल ट्रीटमेन्ट ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ कार्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का प्रकरण

31-डा0 विनोद तिवारी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ

कार्यालय में कुल कितने विद्यालयों के (कक्षा 01 से 08 तक) अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 2004-2005 हेतु मांग पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सभी विद्यालयों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वर्ष 2004-2005 हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय लखनऊ में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति हेतु (कक्षा 1 से 8 तक) कुल 2546 विद्यालयों के मांग पत्र प्राप्त हुए हैं ।

जी नहीं ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी से अतिरिक्त धन की मांग का प्रस्ताव अवमुक्ति हेतु विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु "स्वास्थ्य फाउन्डेशन" के गठन की मांग

32-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के निमित्त लोगों से निवेश प्राप्त करने हेतु "स्वास्थ्य फाउन्डेशन" गठित है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

उ0प्र0 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु अप्रवासी भारतीय तथा प्रदेश से जुड़े देश के अन्य भागों में निवास करने वाले इच्छुक नागरिकों से निवेश प्राप्त करने हेतु "स्वास्थ्य फाउन्डेशन" का गठन किया गया है ।

स्वास्थ्य फाउण्डेशन राजकीय क्षेत्र से पृथक एक स्वायत्त शासी संस्था है । स्वास्थ्य फाउन्डेशन का अध्यक्ष एक गैर सरकारी व्यक्ति होता है । इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र से दो विख्यात व्यक्ति, उद्योग एवं सामाजिक क्षेत्र से दो विख्यात व्यक्ति तथा अप्रवासी भारतीयों के दो प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं । सरकारी सदस्य के रूप में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा अधिशासी निदेशक, सिफ्सा हैं । सिफ्सा स्वास्थ्य फाउण्डेशन का सचिवालय है । ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र में कमियों का चिन्हीकरण, निवेश हेतु प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना, निवेश को प्रोत्साहन, परियोजनाओं का विकास व विपणन, उपलब्ध निवेशों का चयन व विशिष्ट परियोजनाओं हेतु उसका उपयोग करना एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देने आदि का मुख्य कार्य स्वास्थ्य फाउण्डेशन द्वारा संपादित किये जाते हैं ।

प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तैनाती व स्थानान्तरण

33-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश दिनांक 10 जून 2004 (चिकित्सा-2) द्वारा प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की वर्ष 2004-2005 की स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी है जिसमें किसी इकाई में अधिकतम तैनाती

अवधि भी निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की स्पष्ट स्थानान्तरण नीति जिला चिकित्सालय/सामुदायिक/प्रा0स्वा0 केन्द्र/अन्य किसी इकाई में अधिकतम तैनाती अवधि निर्धारित करते हुए इनके नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तर/प्रदेश स्तर पर व्यवस्था करने पर विचार करेंगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में जिला संवर्गीय पदों को छोड़कर स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कार्यरत राजकीय दृष्टिबाधित, मूकबधिर मानसिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन की जानकारी

34-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के आदेश संख्या-वे0आ0-2-1262/दस-2001-53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001 के अन्तर्गत क्या प्रदेश में कार्यरत राजकीय दृष्टिबाधित , मूकबधिर, अक्षम तथा मानसिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम नारायण-

जी नहीं ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

वाराणसी के विकलांग जनों द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ को दिये ज्ञापन पर कार्यवाही की मांग

35-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 27-1-05 को वाराणसी के गरीब विकलांगजनों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के उपरान्त आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी को एक मांग पत्र दिया था? यदि हां, तो मांगें क्या थीं और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम नारायण-

जी हाँ, वाराणसी के विकलांगजनों द्वारा दिनांक 27-1-05 को जिला कार्यालय वाराणसी में अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ को एक ज्ञापन दिया गया था ।

ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें थीं :-

(क) विकलांगों को पेंशन 2004 का भुगतान बढ़ोत्तरी के साथ किया जाय ।

(ख) विकलांगों को आवास हेतु भूमि की व्यवस्था की जाय।

(ग) विकलांगों को नौकरी देने की व्यवस्था की जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(घ) विकलांगों के बीच भेदभाव न कर विकलांगों में साईकिल का वितरण अविलम्ब सुनिश्चित की जाय ।

(क) दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से विकलांग पेंशन की दर रू 125/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रू 150/ प्रतिमाह की जा चुकी है ।

(ख) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत विकलांगजनों को 03 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य हैं । तद्नुसार पात्र व्यक्तियों को आवंटन किया जा रहा है ।

(ग) लोक सेवाओं में विकलांगजन को 03 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है । तद्नुसार नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से कार्यवाही की जाती है ।

(घ) पात्र इच्छुक विकलांगजन को बिना किसी भेदभाव के ट्राई साईकिल उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में धान क्रय केन्द्र स्थापित करने की मांग

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में धान क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र ख-3/322282 दिनांक 27-8-04 एवं ख-/ 164776 दिनांक 16-9-04 पमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया-

जी हाँ ।

जनपद प्रतापगढ़ के विकासखण्ड गंगरौरा में गंगरौरा, परसण्डा, उतरास एवं बिहारगंज, विकासखण्ड पट्टी में पट्टी एवं महदहा तथा विकासखण्ड आसपुर देवसरा में आसपुर देवसरा, नचरौला, अकारीपुर एवं दाउदपुर में धान क्रय केन्द्र खरीफ सत्र 2004-2005 में खोले गये हैं । इसके अतिरिक्त अन्य धान क्रय केन्द्र खोलने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद मण्डल में अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजना में पात्र अभ्यर्थियों के लाभान्वित होने की जानकारी

37-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद मण्डल में अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2000 से अब तक प्रतिवर्ष कितना-कितना धन लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ब्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत कितने पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब कुरैशी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी :-

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की, पश्चिमांचल पावर कार्पोरेशन मेरठ में कृषकों को नये नलकूप कनेक्शन दिये जाने के संबंध में, दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, मेरठ नगर की सीमा में गढ़ सोनीपत मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने मानक के अनुरूप निर्माण करने के संबंध में, तीसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के मेह नगर क्षेत्रान्तर्गत मृतक सुखई के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में, चौथी सूचना श्री रणवीर राणा की, जनपद एटा के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही कथित धांधली एवं प्रबन्धकों के उत्पीड़न को रोकने के संबंध में, पाँचवीं सूचना डा0 सुशील चौधरी की, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण हेतु इन्सीलेटर लगाने के संबंध में, छठी सूचना श्रीमती विमला राकेश की, सहारनपुर के ग्राम कोटा स्थित राजकीय महिला विद्यालय की छात्राओं की समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में, सातवीं सूचना डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा की, जालौन के कालपी में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के संबंध में, आठवीं सूचना डा0 रामबाबू हरित एवं श्री किशन लाल बघेल की, मधुनगर ग्वालियर रोड चौराहे से सेमरी के ताल देवरी रोड, जनपद आगरा में नाला व सड़क का निर्माण करने के संबंध में, नवीं सूचना, श्री आर0के0 सिंह पटेल की बुन्देलखण्ड में किसानों के सिंचाई कनेक्शनों में कृषि विद्युत उपभोक्ता दरें प्रदेश के अन्य जनपदों से दोगुनी वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दसवीं सूचना, श्रीमती राजरानी रावत की, बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत कुंवर गड्डी रजवाहा में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में, ग्यारहवीं सूचना, श्री छोटे लाल यादव की, बाराबंकी के नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग नं0 - 28 सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाये जाने के संबंध में, बारहवीं सूचना श्री कालीचरन राजभर की, गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर कटया के पास गोधनी नदी पर पुल बनवाने के संबंध में है । अगली सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है, लेकिन वह उपस्थित नहीं है । तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, शाहजहांपुर विसरात घाट पर पैदल पुल के निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम के पास पैसा जमा होने के बाद भी पुल न बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौदहवीं सूचना श्री मदन चौहान की, जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर से सयाना बुलन्दशहर मार्ग के सुधार के संबंध में है । श्री रामचन्द्र यादव जी नहीं हैं इसलिए उनकी सूचना के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से श्री राम इकबाल सिंह जी की सूचना को जो बलिया के संबंध में है, ग्राम मल्लय हरसेनपुर के अध्यापक स्व0 रामजी मिश्र की पत्नी को पेंशन राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में है, स्वीकार किया जाता है ।

स्वीकार की गयी सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती है ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों-श्री अशोक सिंह चौहान, श्री आर0एस0 कुशवाहा, श्री कल्याण सिंह दोहरे, श्री आलम बदी, श्री कौशल किशोर, श्री विश्राम सिंह यादव एवं श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह) की सूचनायें अस्वीकार की गयी ।

पश्चिमांचल पावर कार्पोरेशन, मेरठ में कृषकों को नये नलकूप कनेक्शन दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकुम सिंह-

[मान्यवर, पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन, मेरठ के कृषकों के लगभग 3 हजार प्रार्थना-पत्र नये नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु लम्बित हैं । परन्तु एक भी कनेक्शन की स्वीकृति नहीं दी जा रही है, कारण पूछने पर बताया जाता है, कि नलकूप के नये कनेक्शनों पर पाबन्दी है, जिससे कृषकों में भारी असंतोष व्याप्त है और अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । यही स्थिति क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के बदलने की है । कृषकों को तीन-तीन महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं उपलब्ध हो पाता । ट्रांसफार्मर दिये जाने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है ।

यह प्रश्न हजारों कृषकों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है । अत: सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अपेक्षा करता हूं कि स्थिति में अविलम्ब सुधार किया जाए ।]

मेरठ नगर की सीमा से गढ़ सोनीपत मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने मानक के अनुरूप निर्माण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ नगर की सीमा में गढ़ सोनीपत मार्ग का मिसिंग जिंक (हापुड़ रोड से भूमिया पूल, सी0ओ0 आफिस शारदा रोड पुरानी दिल्ली चुंगी तथा सी0ओ0 आफिस से किशनपुरी होकर बागपत अड्डे तक) है ।

अर्थात् गढ़ रोड हापुड अड्डे पर समाप्त तथा बागपत रोड बागपत अड्डे पर समाप्त लेकिन इसका हैवी ट्रैफिक रात्रि 10 बजे से सुबह 7 बजे लगभग 1000 ट्रक से ऊपर इस मिसिंग लिंक पर से गुजरते हैं ।

यह मिसिंग लिंक टुकड़ा लगभग 1750 मीटर है, पी0डब्लू0डी0 मानक तथा हैवी ट्रैफिक के लिये यदि इसे बनाया जाये तो लगभग 35-40 लाख रूपये की आवश्यकता है । नगर निगम इसे शहरी मानक के अनुसार निर्माण करता है, गुजरता है, इस पर हैवी ट्रेफिक/परिणाम सड़क प्रत्येक वर्ष टूट जाती है ।

पी0डब्लू0डी0 इस सड़क को ले ले और इसे गढ़ सोनीपत मार्ग का भाग बना ले, तथा अपने मानक के अनुसार बना दें । पी0डब्लू0डी0 न तो सड़क को पी0डब्लू0डी0 सड़क के रूप में स्वीकार कर रहा है, न ही अपने हैवी ट्रैफिक की कोई व्यवस्था कर रहा है । जनता कष्ट में है ।

उचित है कि पी0डब्लू0डी0 इस सड़क को ले ले तथा अपने मानक से बनावे, अथवा इसको एक बार अपने मानक से बनाकर देवे ।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूँ ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत मृतक सुखई के परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के टाउन एरिया मेहनगर में दिनांक 22-2-2005 को ग्राम महामाई वार्ड नं0 2 में श्री सुखईराम पुत्र श्री गंगूराम की छत से गिर जाने से बहुत ही दर्दनांक और असामयिक ह्रदय विदारक मृत्यु हो गयी है । मृतक की विधवा बहुत ही शोक एवं दु:ख के आकण्ठ में डूबी हुई है । इसके छोटे-छोटे बच्चे जीविकाविहीन होने के नाते इनके भरण पोषण का कोई उपाय नहीं रह गया है । इस समय यह भुखमरी के शिकार हो रहे हैं । इनके पास भूमि भी उपलब्ध नहीं है न ही जीविका को कोई अन्य स्रोत्र । यह अनुसूचित जाति से संबंधित है । इनके पास मात्र दो विस्वा भूमि होने के नाते भरण पोषण सम्भव नहीं है । श्रमिक अनुसूचित जाति की मृत्यु हो जाने पर इन्हें शासन द्वारा कम से कम रू0 एक लाख दिये जाने की नीति भी बनाई गयी है । अभी तक मृतक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गयी है । आवेदिका द्वारा प्रार्थना भी की जा चुकी है । मैं भी समाज कल्याण अधिकारी को सरकारी नियमों के अनुसार सहायता के लिये अनुरोध कर चुकी हूँ । किन्तु अभी तक जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पायी ।

इस लोकमहत्व के प्रश्न को नियम 301 के अन्तर्गत उठाते हुए मैं मांग करती हूं कि मृतक के परिवार को रू0 एक लाख की आर्थिक सहायता सरकारी कोष से दिये जाने के आदेश प्रसारण करने की कृपा करें ।]

जनपद एटा के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही कथित धांधली एवं प्रबन्धकों के उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणवीर राणा-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से आपका ध्यान जनपद एटा के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही धांधली एवं प्रबन्धकों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूँ ।

उपरोक्त जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ द्वारा अधिकांश विद्यालयों के परीक्षा केन्द्र 30 से 60 कि0मी0 की दूरी पर बताये गये हैं जबकि शासन की नीति के अनुसार स्व केन्द्र परीक्षा के आदेश दिये गये हैं । उपरोक्त जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक भेदभाव एवं नियमों की धज्जियां उड़ाकर कार्य कर रहे हैं । कुछ ऐसे भी परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं कि उनके परीक्षा केन्द्र तो है किन्तु उनके विद्यालय के बच्चों को 30-60 कि0मी0 की दूरी पर परीक्षा हेतु सम्बद्ध (लगाया) किया गया है जबकि वह छात्र विद्यालय के पंजीकृत छात्र हैं ।

जनपद एटा के एक विद्यालय जिसका नाम ए0के0एस0 इण्टर कालेज मल्लाहनगर सोरों एटा को भी परीक्षा केन्द्र बनाया जबकि निवर्तमान जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2002 में परीक्षा के दौरान प्रबन्धक द्वारा गड़बड़ी एवं नकल कराते हुए छापामार कार्यवाही में केन्द्र व्यवस्थापक को निलंबित एवं अन्य कई कर्मचारियों (शिक्षकों) को दोषी पाया गया था । प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी थी ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय विषय पर तत्काल कार्यवाही कराने हेतु सरकार को निर्देशित करने एवं दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश देने की कृपा करें ।]

प्रदेश में सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण हेतु इन्सीलेटर लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सुशील चौधरी-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूं, प्रदेश में सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे को कोई भी निस्तारण न होने के कारण प्रदेश में संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है, सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण के संबंध में सरकार ने कई बार इन्सीलेटर लगाने का आश्वासन दिया, मगर अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में सरकार इन्सीलेटर कचरा निपटाने हेतु लगा नहीं सकी । यह प्रदेश की 17 करोड़ जनता के साथ सरकार द्वारा विश्वासघात किया जा रहा है सरकार द्वारा कोरे आश्वासन देकर जनता को गुमराह करने के अलावा कोई भी कार्य जनता के हित में नहीं किया जा रहा है ।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को सरकारी अस्पतालों में तत्काल इन्सीलेटर लगाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

सहारनपुर के ग्राम कोटा स्थित राजकीय महिला विद्यालय की छात्राओं की समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला राकेश-

[महोदय, मैं आपका ध्यान ग्राम कोटा जनपद सहारनपुर में राजकीय महाविद्यालय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, इस राजकीय महाविद्यालय में 120 छात्रायें अध्यनरत हैं छात्राओं के बैठने के लिये फर्नीचर तक की कोई व्यवस्था नहीं है । महाविद्यालय भी इण्टर कालेज के चार कमरों में चल रहा है । राजकीय महिला महाविद्यालय में मात्र 1 प्रवक्ता डा0 उषा रानी हैं जो प्राचार्य क्लर्क चतुर्थ श्रेणी की जिम्मेदारी को संभाल रही है । प्राचार्य व क्लर्क की कोई व्यवस्था नहीं है गृह विज्ञान प्रायोगिक विषय के लिये भी कोई प्रवक्ता नहीं है जिससे छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा है ।

अत: मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करती हूं कि छात्राओं के हित में प्राचार्य, प्रवक्ता, क्लर्क की नियुक्ति तथा बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाये ।]

जालौन के कालपी में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

[मान्यवर, कालपी जनपद जालौन में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किया जाना

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रस्तावित है । इस उपकेन्द्र के स्थापित होने से कालपी के कागज उद्योग तथा क्षेत्रीय किसानों को ट्यूबवेल हेतु विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा साथ ही अन्य कुटीर उद्योग भी स्थापित हो सकेंगे ।

इस प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र की सम्पूर्ण कार्यवाही विद्युत विभाग (शक्ति भवन) स्तर से पूर्ण हो चुकी है किन्तु सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति अब तक नहीं दी गयी है ।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषयवर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

मधुनगर ग्वालियर रोड चौराहे से सेमरी के ताल देवरी रोड जनपद आगरा में नाला व सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राम बाबू हरित, श्री किशन लाल बघेल सेठ-

[महोदय, मधुनगर ग्वालियर रोड चौराहे से सेमरी के ताल देवरी रोड थाना सदर जनपद आगरा में लगभग 4 किलोमीटर सड़क पर हर समय पानी भरा रहता है जिससे गन्दगी व्याप्त है, मच्छर, बदबू का साम्राज्य स्थापित हो गया है । समय-समय पर सर्वदलीय नाला सड़क निर्माण संघर्ष समिति द्वारा अनशन, प्रदर्शन, संबंधित अधिकारियों को मांग पत्र दिये गये हैं । जनता काफी दुखी, परेशान है, कभी भी सड़कों पर उतर कर कानून व्यवस्था भंग कर सकती है ।

अत: जनहित में वहां नाला व सड़क निर्माण कराकर इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करें ।]

बुन्देलखण्ड में किसानों के सिंचाई कनेक्शनों में कृषि विद्युत उपभोक्ता दरें प्रदेश के अन्य जनपदों से दोगुनी वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0के0 सिंह पटेल-

[महोदय, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर कराना चाहूंगा बुन्देलखण्ड प्रदेश का सबसे पिछड़ा हिस्सा है । यहां सिंचाई के समुचित साधन नहीं है किसानों को निजी नलकूप लगाने हेतु सरकारें छूट देती आयी हैं किन्तु जहां नलकूप लगाने से लेकर विद्युत कनेक्शन देने मे छूट दी जाती है वहीं विद्युत मूल्य वसूल करने में प्रदेश के सभी जनपदों से भिन्न दूनी दरें किसानों से वसूल की जा रही हैं । प्रदेश में 60-65 रू0 प्रति हार्सपावर विद्युत बिल लिया जा रहा है जबकि बुन्देलखण्ड के किसानों से 120 से 130 रू0 प्रति विद्युत मूल्य वसूल किया जाता है । जो घोर अनियमितता है, जिससे चित्रकूट, बांदा, झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर जिलों के किसान परेशान हैं भेदभाव से किसानों में रोष व्याप्त हैं किसान आन्दोलित हो रहे हैं ।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने के साथ ही प्रदेश के पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यान्चल के समान ही बुन्देलखण्ड के किसानों से सिंचाई विद्युत कनेक्शनों के बिल समान रूप से वसूल किये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत कुंवर गड्डी रजवाहा में टेल तक पानी पहुंचायें जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजरानी रावत-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद बाराबंकी के कुंवर गड्डी रजवाहे में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे सिंचाई में कठिनाई हो रही है । मेरे द्वारा इस संबंध में दिनांक 5-8-2004 को भी सदन में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी जिस पर मा0 मंत्री जी का वक्तव्य भी आया था परन्तु आज तक उक्त रजवाहे के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है जो कि खेद का विषय है । प्रश्नगत रजवाहा, माइनर शारदा संगठन सिंचाई विभाग के अधीन सीतापुर प्रखण्ड शारदानहर सीतापुर के अन्तर्गत आता है । जिसमें टेल तक [illegible] नहीं पहुंच पा रहा है जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है ।

अत: लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं ।]

बाराबंकी के नबावगंज क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग नं0-28 सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल यादव-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नबावगंज जनपद बाराबंकी के राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 28 सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग जहां पर पूर्वोत्तर व उत्तर रेलवे क्रास करती है लखनऊ से पूर्वांचल के सारे जनपद चाहे वह देवरिया हो गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बहराईच, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर आदि के महत्वपूर्ण लोगों का एक ही मात्र रास्ता है जो सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग होकर राजधानी को आता है यहां तक कि लखनऊ से पूरा पूर्वांचल व नैपाल देश भी इस क्रासिंग से प्रभावित होता है गम्भीर रूप से घायल एवं बीमार लोग राज नेता व अधिकारीगण ओवर ब्रिज न होने के कारण जाम में फंस जाते हैं और सही समय पर इलाज न होने पर मौत हो जाती है । ओवरब्रिज की मांग जनता व समस्त पार्टी के लोगों द्वारा 12 वर्षो से करते चले जा रहे हैं । इससे जनमानस में रोष है और महत्वपूर्ण विषय है अविलम्बनीय है लोक महत्व का है ।

अत: इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त मार्ग पर ओवरब्रिज बनाये जाने की मांग करता हूं ।]

गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर कटया के पास गोधनी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन राजभर-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद के अन्तर्गत राजापुर कटया के पास से गोधनी नदी बहती है । बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण जो इस नदी को पार करके रास्ता बरेसर तक जाता है लोगों का आवागमन रूक जाता है । मैंने कई बार इस मांग को विधानसभा में उठाने का काम किया है । लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते शासन को सूचना तोड़-मरोड़कर दी जाती है कि

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वहां पुल बना हुआ है जबकि पुल के नाम पर सिर्फ सीमेन्ट के पतले दो ह्यूम पाइप लगे हैं जिससे बाढ़ आ जाने के कारण आस-पास के गांवों से सम्पर्क टूट जाता है जिससे लोगों में काफी आक्रोश है तथा दुख व्याप्त है ।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय मांग को ध्यान रखते हुए इस सदन में चर्चा कराने की तथा पुल बनवाने की मांग करता हूं ।]

शाहजहांपुर बिसरात घाट पर पैदल पुल के निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम के पास धनराशि जमा होने के बाद भी पुल न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर जनपद में विसरात घाट पर एक पैदल पुल बनने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से दो साल पहले 15 लाख रूपया दिया गया था । यह रूपया राजकीय निर्माण निगम के पास पिछले दो वर्ष से जमा है । पहले राजकीय निर्माण निगम ने इस पुल को 19.04 लाख में बनाने का कहा था बाद में इसका स्टीमेट बढ़ाकर 26 लाख कर दिया गया, लेकिन आज तक पुल का निर्माण शुरू नहीं किया गया । इस संबंध में मैंने विधायक निधि से 11 लाख रूपये दिये जाने का पत्र भी संबंधित विभाग के सक्षम आधेकारी को दे दिया । पहले ही पुल के निर्माण की लागत 7 लाख बढ़ चुकी है, जितनी देरी हो रही है उतनी लागत में और वृद्धि हो रही है । जनहित में पुल बनना अत्यन्त आवश्यक है ।

अत: लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से पुल बनाने की माँग करता हूं ।]

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर से स्याना, बुलन्दशहर मार्ग के सुधार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय, गढ़ मुक्तेश्वर से बुलन्दशहर मार्ग में गढ़ कस्बा से स्याना चौराहे तक, सालारपुर आबादी भाग, डहरा कुटी का भाग बेहद जर्जर है । यह मार्ग स्टेट हाइवे के अन्तर्गत आता है । बहुत अधिक आवागमन है । आज अधिक टूटने के कारण रोड़ी इधर उधर बिखरी हुई है । आम जनता को भारी परेशानी है । यह अत्यन्त लोक महत्व व अविलम्बनीय भी है । अत: तीर्थनगर व पर्यटन स्थल होने के कारण और अधिक महत्व है ।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराकर शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध करता हूं । अत: निर्देश देने की कृपा करें ।]

बलिया के ग्राम मल्लप हरसेनपुर के अध्यापक स्व0 राम जी मिश्र की पत्नी को पेंशन राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम इकबाल सिंह-

[मान्यवर, स्व0 श्री रामजी मिश्र ग्राम मल्लप हरसेनपुर जनपद बलिया प्राइमरी पाठशाला [illegible]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

से 01-06-1976 को अवकाश ग्रहण किये । 20-09-2001 को उनका निधन हो गया । बेसिक शिक्षा कार्यालय, बलिया उनकी पत्नी श्रीमती राजमुनी देवी को पेंशन देने में आनाकानी करता रहा । तब उन्हें रिट संख्या 42665 के माध्यम से उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की शरण में जाना पड़ा । न्यायालय ने पेंशन देने का आदेश 4-10-2004 को दिया, मगर विभाग धन उगाही के चक्कर में अब तक पेंशन की राशि अवमुक्त नहीं की ।

अत: अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02-03-2005 को नियम-300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी की, नियम-49 के अंतर्गत चर्चाओं को नियम-51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं से पहले लिये जाने के संबंध में, दूसरी सूचना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा एवं श्री रामहेत की, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100-100 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने की घोषणा का अनुपालन न किये जाने के संबंध में है । इस संबंध में पहले चैम्बर में बात हो चुकी है । तीसरी सूचना, श्री जगदम्बिका पाल व श्री प्रमोद कुमार की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान 15 दिनों के अन्दर न किये जाने के संबंध में, चौथी सूचना, श्री मुकुल उपाध्याय व श्री रामवीर उपाध्याय की, जनपद अलीगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा सरकारी सम्पत्ति का दुरूपयोग करने के संबंध में है ।

ये कोई भी सूचनायें नियम-300 में नहीं आती हैं इसलिए इन्हें अस्वीकार करता हूं ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी सूचना तो नियम-300 में आती है ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना में है कि नियम-49 की चर्चाओं को पहले ले लें । इसमें तो मौखिक रूप से बात कर लें ।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं, कृपया सुन लें ।

मान्यवर, आप सुनते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलना चाहते हैं तो नियमों में उठायें ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी एक सूचना नियम 300 में है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

आपने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उसमें नियम-49 की चर्चा नियम-51 के पहले करने की मांग की है यह औचित्य का प्रश्न कहाँ है ? कार्यसूची में रखने पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमों के खिलाफ बोलते हैं । आप तो मंत्री रह चुके हैं, इस विषय में संसदीय कार्य मंत्री और अन्य लोगों से बात हो चुकी है । डाक्टर साहब और आपके नेता भी थे उनसे पूछ लीजिएगा ।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं । मुझे क्या मालूम कि चैम्बर में क्या बात हुई है ।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरे चैम्बर में आइए पूरी बात समझा दी जायेगी, आप बैठ जाएं ।

श्री सतीश महाना-

मैं बैठूंगा नहीं चाहे आप सदन से बाहर निकाल दें ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का सत्रहवां प्रतिवेदन†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) उक्त समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1996-97 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित हैं, प्रस्तुत करता हूँ ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003-2004) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन, जो समिति (1999-2000) के तेइसवें प्रतिवेदन में निहित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड से संबंधित संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

नोट :- †छापा नहीं गया ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं, उसके बारे में आपने बताया कि चेम्बर में बात हो गई है । गौर साहब कह रहे हैं कि वह थे नहीं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता, प्रतिपक्ष आप बैठ जाएं, संसदीय कार्य मंत्री बैठ जाएं, पूरी जानकारी हो जाएगी, इसमें समय क्यों लगाते हैं ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, आप चाहें तो बैठक बंद करा दें या चलायें ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री राधेश्याम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का पंचम प्रतिवेदन, जो सिंचाई विभाग के वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के प्राक्कलनों के परीक्षण के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय सदस्य जानकारी करना चाहते हैं । माननीय सदस्यों को जानकारी दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप मौर्या जी रूक जाइये । मैं आपकी बात अभी सुनता हूं । प्रतिवेदन को प्रस्तुत हो जाने दीजिये ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का षष्ठं प्रतिवेदन†

श्री राधेश्याम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का षष्ठं प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण विभाग के वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के प्राक्कलनों के परीक्षण के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

नोट :- †छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 01 मार्च, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 02 मार्च से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

मार्च, 2005

2 बुधवार — 1-वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण-चर्चा ।

3 गुरूवार — 1-निधन के निर्देश ।

2-वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

3-"प्रदेश के खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" श्री लालजी टण्डन, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सुखदेव राजभर, श्री राजेश कुमार, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक बंसल, श्री प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री सुरेश श्रीवास्तव, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा-डेढ़ घण्टा ।

4 शुक्रवार — 1-वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2-"प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में" श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, डा0 विनोद तिवारी, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री डा0 प्रसाद अहिरवार, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री मलिक मसूद, श्री अब्दुल मन्नान, श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास, श्री अनीस अहमद, श्रीमती माया प्रसाद, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सदल प्रसाद, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री शिव चरण प्रजापति, चौधरी धूराम लोधी, श्री इरशाद खाँ, श्री जयराम विमल, श्री धर्मराज निषाद, चौधरी महेन्द्र सिंह श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री रमेश बिन्द, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्रीमती अमिता सिंह, श्री उदयभान करवरिया तथा श्री मुंशीलाल गौतम, सदस्यगण विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा एक घण्टा ।

5 शनिवार, 6 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

7 सोमवार — वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

8 मंगलवार — बैठक नहीं होगी । (महाशिवरात्रि का अवकाश) ।

मार्च, 2005	बैठक नहीं होगी ।
9 बुधवार 10 गुरूवार	
11 शुक्रवार 12 शनिवार	वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
13 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
14 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । **3.00 बजे अपराह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
15 मंगलवार 16 बुधवार 17 गुरूवार 18 शुक्रवार	बैठक होगी ।
19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
21 सोमवार	असरकारी दिवस ।
22 मंगलवार	1-असरकारी दिवस । 2-विधायी कार्य (आधा दिन)
23 बुधवार 24 गुरूवार	विधायी कार्य ।
25 शुक्रवार 26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी । (होली का अवकाश)
28 सोमवार 29 मंगलवार	विधायी कार्य ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लाल जी वर्मा-

अध्यक्ष-महोदय, एजेण्डे में लिखा हुआ है कि बैठक नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष-

बैठक होगी । मैंने इसको देख लिया है जिसने इसको छाप दिया है उसके खिलाफ कार्यवाही भी होगी ।

संसदीय कार्यमंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करिये ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100-100 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने की मुख्य मंत्री की घोषणा का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत हमने सूचना दी है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन के अन्दर घोषणा की थी कि सभी विधायकों को 100-100 इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प दिए जायेंगे । उसके बाद से एक सत्र बीत गया यह दूसरा सत्र चल रहा है लेकिन अभी तक वर्ष 2004-2005 के लिए किसी विधायक को सदन में हुई घोषणा के मुताबिक एक भी हैण्ड पम्प नहीं मिला है । यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके क्षेत्रों में पानी की समस्या है तो उसके निदान के लिए हैण्ड पम्प की नितान्त आवश्यकता है इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी पीठ से निर्देश होना चाहिए जिससे विधायकों को 100-100 हैण्ड पम्प मिल जायं ।

***सतीश महाना-**

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत कहना है कि 100-100 हैंड पम्प पूरे विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्यों को अभी तक नहीं मिले । इस पर आपने व्यवस्था दी कि इस संदर्भ में सदन में बात-चीत होगी । इस सदन में जो 403 विधायक चुनकर आते हैं उनको 100-100 हैंड पम्प मिलने चाहिए । आपने अगर चैम्बर में किसी एक सदस्य को बुलाकर व्यवस्था दे दी तो उससे कुछ नहीं । यह सदन का विषय है और इसके बारे में सदन में आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जाय । संसदीय कार्य मंत्री जी यह 100-100 हैण्ड पम्प की बात कई बार उठ चुकी है । इसके बारे में आप कुछ बतायेगें ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, गत सत्र गुजरा है उसमें भी नेता सदन ने आश्वासन दिया था। सत्र उठने के पहले

भी यहाँ माननीय सदस्यों ने कहा था और मेरे संज्ञान में भी है । मैं इस संबंध में नेता सदन से जरूर चाहूंगा कि जैसे आपके सुझाव हों उसके अनुसार बात हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

बेहतर यह होगा कि सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर इस बारे में बात कर लें ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

यह नेता सदन की घोषणा है और उनका वायदा भी है ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, नेता सदन से बात करके इसका निस्तारण करा लें ।

(माननीय सदस्य, डी0 प्रसाद अहिरवार के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

डी0 प्रसार अहिरवार जी अब बात आ गई है ।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, चैम्बर में क्या हुआ था, बात दीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

आप व्यवधान न करिये । कैसे आप मंत्री थे, मैं तो आश्चर्य में हूँ ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने महाना जी को तो सुन लिया । किसानों ने क्या अन्याय किया है ।

श्री अध्यक्ष-

अभी बैठिये । मैं आगे की मद ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग, विधेयक, 2005†

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†दिनांक 2 मार्च, 2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

धैर्य से सुनिये । यह गम्भीर विषय है । आप लोग रूक जायं । कहने तो दीजिये । आज दिनांक 02 मार्च, 2005 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार और श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी) की नेपाल से लगी प्रदेश की सीमा पर माओवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना, श्री नवाब सिंह नागर की जनपद गाजियाबाद के भू-माफिया श्री मोतीलाल गोयल के द्वारा शहरी क्षेत्र की भूमि से संबंधित करोड़ों रूपये के घोटाले के सम्बन्ध है । तीसरी सूचना, श्री लाल जी वर्मा की, जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम प्रधान श्री राम नयन वर्मा को माफियाओं द्वारा पिटाई एवं आतंकित किये जाने के संबंध में है । चौथी सूचना, श्री भरत सिंह की जनपद बलिया के द्वाबा क्षेत्र में भू-जल में आर्सनिक युक्त पानी पीने से विगत वर्षों में हजारों लोगों के मरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पाँचवीं सूचना, श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर के थाना अहमदगढ़ में नाबालिग दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार एवं लूटपाट किये जाने के संबंध में है । छठवीं सूचना, श्री लाल जी टण्डन और डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश के विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2004 के चयन में भारी अनियमितता किये जाने के संबंध में है यह जो ब्रैकिट में दिया है उसके बारे में यह बताना है कि सूची लम्बी है, मैंने पढ़ी है इसलिये इस संबंध में विभागीय मंत्री एवं विभागीय सचिव तथा निदेशक के साथ कक्ष में वार्ता की जायेगी, जब आप टाइम दें । वार्ता से यदि कोई निराकरण नहीं होगा तो आप उसे सदन में लाइयेगा ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, बहुत गम्भीर विषय है । हजारों शिक्षकों की नियुक्ति होनी है । जब समय आयेगा, सुन लीजियेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मुंशी लाल गौतम का ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

वह तो है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे ।)

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मुकुल उपाध्याय की सुरक्षा के संबंध में कई बार अनुरोध किया गया है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

श्री अध्यक्ष-

सुन लीजिए, निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई है । श्री मुकुल उपाध्याय, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मिथिलेश कुमार, श्री कौशल कुमार, श्री आर0के0 सिंह पटेल, श्री राम इकबाल सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री छोटेलाल वर्मा, श्री भगेलू राम, श्रीमती विद्या चौधरी, डा0 रामबाबू हरित, श्री रामहेत भारती, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री रिजवान अहमद खां, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री प्रागीलाल अहिरवार, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की सूचना नियम-51 में परिवर्तित कर दी गई है । श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) जी आपकी सूचना भी नियम-51 में परिवर्तित कर दी गई है ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरी भी नियम-51 में परिवर्तित कर दें ।

श्री अध्यक्ष-

उपाध्याय जी, कल सुरक्षा के बारे में चर्चा हुई थी मैं उस समय नहीं था ।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मैंने कई बार मामले को उठाया है । लेकिन उसको नहीं लिया जा रहा है ।

(श्री रामवीर उपाध्याय, श्री राम इकबाल सिंह, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री प्रागीलाल अहिरवार आदि माननीय सदस्य एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर बोल रहे थे ।)

श्री अध्यक्ष-

विधायक हैं, सुरक्षा के लिए आप मुख्य मंत्री जी से बात कर लें ।

श्री छोटे लाल वर्मा-

कई बार मैंने मामला उठाया लेकिन मेरा मामला नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पार्टी का तो आता है आप कहते हैं नहीं आता है ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मेरा बलिया सं संबंधित मामला है । दलित वर्ग के लोगों को उजाड़ दिया....

श्री अध्यक्ष-

देखिए सूचनायें ज्यादा आती हैं उसको देखकर लिया जाता है । इतनी सूचनायें लगी हैं । मौर्या जी, आपने जो कहा है हमारे स्तर पर जो हो सकता है वह करेंगे ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

विधायक जी सुरक्षा से संबंधित मामला है । इसमें कार्यवाही नहीं हो रही है । सदन के अन्दर इसको रख दिया गया है । अब क्या राजूपाल जैसी हत्या के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यह सदन बैठेगा ।

श्री अध्यक्ष-

एक-एक करके बोलें सब एक साथ बोल रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मेरे प्रकरण का आप संज्ञान ले लें ।

श्री राम इकबाल सिंह-

बलिया के मामले पर आप चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष-

एक दिन में सब कैसे हो जाएगा ? अभी तो सदन के बहुत दिन हैं । बजट भाषण चल रहा है उसमें भी आप अपनी बात कह सकते हैं और उसमें जो बात आप कहेंगे वह भी प्रोसीडिंग का अंग बन जायेगी । आप बैठिये ।

(श्री प्रागीलाल अहिरवार, राम इकबाल सिंह, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), मुकुल उपाध्याय और कुछ अन्य सदस्य अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे थे ।)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) जी, आप बैठिए, आप क्यों खड़े हैं ?

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, आपने मेरी सूचना को नियम-51 में बदल दिया है लेकिन विशेष उल्लेख में केवल एक मिनट हमें कहने का मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए । हमारे एक सदस्य पहली बार बोल रहे हैं, उन्हें बोल लेने दीजिए ।

***श्री मुकुल उपाध्याय-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी सुरक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं कि मेरे साथ 10 सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उनमें से 8 सुरक्षाकर्मियों को हटा लिया गया है और अब केवल दो गनर लगे हुए हैं । मैंने कई बार लिखकर दिया लेकिन आज तक एक भी गनर नहीं बढ़ाया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मान्यवर, [xxx xxx], के कुछ लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं । मैंने इसके लिए आपसे भी अनुरोध किया था, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी लिखा लेकिन आज तक मेरी सुरक्षा नहीं बढ़ायी गई । मान्यवर, गृह सचिव का 16 फरवरी का पत्र इसी सदन में पढ़ा गया था कि बसपा के दो विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई हैं । आज 16 दिन हो गए हैं लेकिन किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ायी गई है । हमारे एक विधायक राजू पाल की हत्या हो गई है और अब मेरी हत्या कराना चाहते हैं । मुख्यमंत्री [xxx xxx] के कुछ लोग हमारी हत्या कराना चाहते हैं, [xxx xxx] हमारी हत्या करा सकते हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरी सुरक्षा बढ़ायी जाए । माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कई बार अनुरोध किया है, आखिर मेरी सुरक्षा कब बढ़ायी जाएगी, जब मैं मार दिया जाऊंगा ? मैंने गृह सचिव को भी लिखा है लेकिन मेरी सुरक्षा नहीं बढ़ायी गई । इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है कि वह मेरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आप अपनी पीठ से निर्देश दें, हमारे एक नए विधायक जिन पर जानलेवा हमले का खतरा है उससे उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए या संसदीय कार्यमंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करायें ।

***श्री जगदम्बिका पाल-**

माननीय अध्यक्ष जी, इनका किसी नियम के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है । यह [xxx] का नाम ले रहे हैं, [xxx xxx] का नाम ले रहे हैं । एक नया फैशन हो गया है । किसी को सुरक्षा का खतरा है, वह लिखकर दे, संसदीय कार्य मंत्री को लिखकर दे । आपने नियम-56 पुकार लिया, बिना नियम के आप उनको अवसर दे रहे हैं । मान्यवर, अगर इस तरीके से सदन चलेगा तो यह ठीक नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ----------इस पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, का जवाब आना चाहिए जिससे माननीय सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था की चिंता सुनिश्चित हो सके ।

***श्री तेजपाल सिंह-**

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य की सुरक्षा-व्यवस्था का मामला है । मेरा कहना है कि उनकी सुरक्षा-व्यवस्था करायी जाये, इसके लिए हम भी अनुरोध करेंगे लेकिन उन्होंने [xxx xxx] का नाम लेकर कहा और [xxx xxx] के माननीय सदस्य का नाम लेकर भी कहा तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है । मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि धवारीकला, हाथरस में बैठकर श्री रामवीर उपाध्याय और इन्होंने वहां [xx xxx] के लोगों के खिलाफ एस0सी0फ/एस0टी0 की रिपोर्ट लिखाई । एस0एस0पी0, सी0ओ0 को गुमराह करके आज भी फर्जी मुकदमें लिखे हुए हैं । मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए लेकिन किसी दल का नाम लेकर नहीं कहना चाहिए । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि लोक दल का नाम कार्यवाही से निकलवा दें ।

(श्री रामवीर उपाध्याय, श्री प्रागीलाल अहिरवार, श्री राम इकबाल सिंह सहित कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी-अपनी बात एक साथ कहने लगे ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायं ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, [xxx] के जिस सदस्य का नाम लेकर उन्होंने कहा है कृपया उसे भी कार्यवाही से निकलवा दें ।

(श्री भरत सिंह के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, आपको बोलने का मौका मिलेगा, संसदीय कार्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं उन्हें सुन लें ।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-**

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने बारे में जो भय व्यक्त किया है कि अमुक दलों के कुछ लोग उनकी हत्या करोना चाहते हैं । इस बात से मैं सहमत नहीं हूं । आपने चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर भी दिया है और नेता सदन के स्तर पर इस पर कार्यवाही शुरू भी हो गयी है । सदन में बार-बार कहा गया कि पहले तो किसी भी व्यक्ति की जानमाल की जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य को इस प्रकार का खतरा हो तो गम्भीरता और बढ़ जाती है । इसे देख लिया जायेगा और जो भी कमी सुरक्षा-व्यवस्था में होगी उसको पूरा किया जायेगा । लेकिन माननीय सदस्य ने दो राजनीतिक दलों का नाम लेकर कहा है कृपया उसे कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसको देख लिया जायेगा । माननीय राम इकबाल जी, आप बैठ जायं ।

श्री राम इकबाल सिंह-

लेकिन मान्यवर, आपने तो कल कहा था कि ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय, इकबाल सिंह जी, रोज तो आप इतना बोलते हैं । आज मेरी बात मान लीजिये । नियम-51 और 300 में आप रोज समस्या उठाते हैं अपनी बलिया की । आप तो केवल बलिया तक ही सीमित होकर रह गये हैं । यह माओवादी का मामला है इससे पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा है इस पर हो जाने दें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, एक खतरे की ओर मैं आपका ध्यान एवं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और उससे सदन की भिज्ञ होगा, जो हमारे पड़ोसी राज्य नैपाल की सीमा में हो रहा है । मान्यवर, वहां के प्रजातंत्र को खतरा है । आज जिस तरह से वहां पर प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रतिबन्ध लगा और जिस तरह से वह व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और वहां पर आये दिन घटनाएं हो रही हैं, नृशंस हत्याएं हो रही है.....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

नैपाल में क्या हो रहा है इसका जिक्र आप न करें । यहां पर आपको क्या खतरा है उसके बारे में बतायें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हमारे सीमा सुरक्षा बल के आई0जी0 श्री सत्यव्रत ने पत्रकार वार्ता की उसको आपने भी देखा होगा। उन्होंने नैपाल के दो माओवादी रोशन लाल और भूरे को गिरफ्तार किया गया । जो भारतीय मूल के लोग नैपाल की सीमा पर रहते थे आज वह भय के कारण भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं । आज जिस तरह से माओवादी भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं वह इससे परिलक्षित हो जाता है कि सीमा सुरक्षा बल के लोगों ने दो माओवादी को गिरफ्तार किया और उसके पास से एस0एल0आर0, ए0के0 47 तथा अन्य हथियार बरामद किये हैं उससे भारत में बड़ा खतरा पैदा हो गया है । जो भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं उन्हें मरेशिया कहते हैं आज वह माओवादी के निशाने पर हैं । पिछले दिनों 28 तारीख को 6 लोगों की हत्या और 26 तारीख को भी घटना हुई । इसमें कई लोग घायल हुए हैं जो पटना नर्सिंग होम में इलाज करा रहे हैं । इस चीज को आई0जी0 ने भी स्वीकार किया है । आज दूसरे राष्ट्र से माओवादी भारतीय सीमा में आ गये हैं और वह दुष्प्रचार में लगे हैं इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिस तरह से नैपाल के लोग भारतीय सीमा में आ रहे हैं, आपका जनपद भी उससे लगा हुआ है, जिस तरह से बंगलादेश और पूर्वी पाकिस्तान के लोग यहां पर आये थे, जम्मू कश्मीर से लोग दिल्ली में पड़े हैं,तो यह समस्या बन गये हैं । सिद्धार्थनगर, बहराईच, खीरी लखीमपुर, महाराजगंज यह सीमाएं खुली हुई हैं । इनके आने में कोई रोक टोक नहीं है । आज भारतीय मूल के लोग अपनी जान बचाने के लिए, जो नैपाली नागरिक हो गये हैं, डा0 शाह जो वहां के एम0पी0 हैं और भारतीय मूल के हैं वह नैपाल छोड़कर भारत आ गये हैं, उनका परिवार आ गया है और अपनी जान बचाने में लगा है । इससे यह साबित हो जाता है कि वहां के भारतीय मूल के लोग सांसद, विधायक पलायन कर रहे हैं । यहां की सीमा को खतरा हो रहा है माओवादी के आने से । जो नैपाल हमारा कभी मित्र था । यहां से खाद्यान्न, साग सब्जी इत्यादि वहां जाती थी आज वह सब बंद हो गया है और सारा व्यापार प्रभावित हो रहा है ।

***श्री लाल जी टण्डन-**

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, नैपाल हमारा मित्र देश है, वहां जो हो रहा है, वह उनका आन्तरिक मामला है । वहां के मामले पर यहां विस्तृत चर्चा कराया जाना, यह अन्तर्राष्ट्रीय कूट नीति के विपरीत है । यहां माओवादी जो आ रहे हैं, वह हमारे अपने प्रदेश का मामला है । वहां कौन पलायन कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, नैपाल में यह तो उस पर बता रहे हैं, बार्डर पर क्या हो रहा है, माओवादी क्या कर रहे हैं ? नैपाल में क्या हो रहा है, यह नैपाल जाने ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष, तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौक को जानते हैं, जहां वह रहते हैं और जो सबसे सुरक्षित है । मैं केवल उस घटना का उल्लेख कर रहा हूं जो भारतीय सीमा पर भारत की धरती पर हो रहा है । आज बड़ी संख्या में लोग भारत शरणार्थी के रूप में पलायन करके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आ रहे हैं, वहां पर माओवादियों का डर है, उनके आतंक के कारण भय की स्थिति है । आज वहां के सांसद भी यहां पर चले आ रहे हैं या जिस तरह से माओवादी पकड़े जा रहे हैं, यह कोई कम चिन्ताजनक विषय नहीं है, मैं तो समझता था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बात को इण्डोर्स करेंगे । जहां सब अपने बार्डर्स पर बाड़ लगाने की बात कर रहे हैं और हमारे बार्डर्स खुले हुए हैं । मान्यवर, एक कोई लाईन आर्डर की बात आ जाएगी तो यह बड़े गम्भीर हो जाएंगे, यह ठीक है कि यह नैपाल का आन्तरिक मामला था, हम उन पहलुओं को इंगित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भारत के लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिए चिन्तित हैं, इसलिए कि हम जन प्रतिनिधि हैं । आज पूरे प्रदेश में माओवादी घटनाओं से लोगों में चिन्ता पैदा हो गई हैं । मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर, अवलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए आज सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा लें।

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है, नैपाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन हमारी जो नैपाल से लगी हुई सीमा है, उसके बारे में कहना चाहेगें, सीमाओं से जो रिपोर्ट मुझे मिली है, मान्यवर, वहां की बड़ी भयावह स्थिति है आज भी उस क्षेत्र में मान्यवर, मैं साढ़े सात वर्षों तक वहां का जन प्रतिनिधि रहा हूं, मैं सब जानता हूं । मैं सब जानता हूं अभी अगर सचेत होकर सरकार ने ठीक से इस तरफ ध्यान नहीं दिया और भारत सरकार को इस संबंध में सूचित नहीं किया गया तो मैं स्पष्ट कह देना चाहूंगा कि नैपाल से लगी उत्तर प्रदेश की सीमा और उसका इलाका, उसके गाँव कश्मीर बन जाऐंगे, जो पूर्ववर्ती प्रदेश हैं, उनके समान स्थिति आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है । मान्यवर, माओवादी घटना के संबंध में जो माननीय माल साहब ने कहा है वह ठीक है । जो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, सत्यव्रत जी है उनका स्टेटमेंट आ गया है सभी अखबारों में, मैंने भी पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि दो माओवादी तो पकड़े गए हैं बहुत से माओवादी गाँवों में आकर छिप कर बैठ गये हैं । उनकी तलाश जारी है । उन्होंने यह भी कहा कि एक साल में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में 44 माओवादी अपनी सीमा में पकड़े गए हैं, तो जेलों में बन्द हैं । मान्यवर, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बहराइच जिले में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी है मैनाखोर, तो मैनाखोर चौकी को सूचना आई कि सौ की तादात में माओवादी भारतीय सीमा में घुस रहे हैं, हमारे सीमा सुरक्षा बल के लोग वहाँ पहुंच गये, दोनों में मुठभेड़ हुई, जिसमें काफी सारे माओवादी मारे गये, जिनमें उत्तर प्रदेश के कई लोग भी हैं ।

मान्यवर, मतीराम, सत्तार, लाले-समेत चार लोग उसमें मारे गये हैं और चार सुरक्षा कर्मी भी उसमें शहीद हुए हैं दर्जनों जानवर और कुछ ग्राम वासी घायल हुए हैं । यह घटना बता रही है कि वहां की स्थिति ठीक नहीं है । मान्यवर, बसन्तपुर के श्री मधुनन्दन त्रिपाठी को आप जानते हैं वह आए हैं उनकी रिपोर्ट के अनुरूप नैपाल से सटी जो हमारी सीमा हैं वहां के गांवों में बहुत से माओवादी आकर शरण लिये हुए हैं । आप तो मान्यवर, उसी जिले से आते हैं । श्री जगदम्बिका पाल वहां से लोक सभा का चुनाव लड़ चुके हैं । मान्यवर, आप देखें कि पाकिस्तान से लोग आकर कश्मीर में घुस गये और वहां की स्थिति क्या है । इसी तरह से उनको वहां शरण देने वाले मिल गये हैं । इसके अतिरिक्त माओवादी और अन्य लोगों ने वहां बहुत सी जमीनें भी खरीद ली हैं हमारे बार्डर के सभी जिलों में । मान्यवर, यह जांच का विषय है कि साल भर में कितनी जमीनें वहां बिकी हैं और कौन-कौन लोग हैं जिन्होंने वह जमीनें खरीदी हैं । आज आप देखें कि हमारी सीमाओं पर की हालत कितनी खराब होती जा रही हैं । सीमा पर की जो रिपोर्ट हमारे पास आयी है उसमें सिद्धार्थनगर, बहराइच की भी सूचनायें आ रही है । इससे वहां लोगों में आतंक व्याप्त हैं । सीमा सुरक्षा बल के लोगों द्वारा इस तरह से वहां से आने वाले

लोगों को रोका जाय उन्हें किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने न दिया जाय । यह जो माओवादी वहां आ रहे हैं मान्यवर, बिल्कुल कश्मीर की तरह वहां के हालात हो जायेगें । वह गांव में घुसते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमें राशन दो, ठहरने की जगह दो और कहीं कुछ बताया तो जान नहीं बचेगी और मारपीट कर लूटकर चले जा रहे हैं । मान्यवर, नैपाल से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इन माओवादियों ने नैपाल को तो तबाह किया है, अब हमारी सीमाओं में घुसकर हमारे प्रदेश की हालत खराब कर रहे हैं भारतीय गांव के लोगों में भय और आतंक व्याप्त हो गया है । यह मान्यवर, एक गम्भीर मामला है, इस पर खुली चर्चा सदन में होनी चाहिए, यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है । हमारी सीमाओं पर सुरक्षा बनी रहे और हमारे गांव वाले अमन-चैन से रह पायें यह महत्वपूर्ण प्रश्न है यह स्थिति आज वहां पैदा होना नितान्त आवश्यक है और माओवादी किसी तरह से हावी न होने पाये । इसके लिये सरकार पूरी तरह से सजग और तैयार हो । सुरक्षा बल बढ़ा दिए जायें और सीमा की जनता में सुरक्षा का विश्वास जगाया जाए ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इस मामले की गंभीरता से इंकार नहीं है । लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई बहुत कमजोर है और इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है । मान्यवर, वहां ऐसा कोई भय नहीं है कि माओवादियों से कोई बड़ा भारी खतरा हो गया है । कानून व्यवस्था कुछ बिगड़ी हो ऐसा कुछ नहीं है । दूसरे मान्यवर, यह बात भी सही है कि यह उनका आन्तरिक मामला है, उससे हमारा लेना-देना नहीं है । मान्यवर, जो यहां के मूल निवासी हैं वहां पर रह रहे हैं किसी इलेक्शन में खड़े हुए हैं या वहां कारोबार है तो उनको अधिकार यहां भी उसकी तरह का है । जमीन की खरीद के बारे में जो आपने जिज्ञासा व्यक्त की है इसे अवश्य दिखवा लिया जायेगा । मान्यवर, जमीन खरीदने के अपने मानक हैं कि उसे यहां के बाशिन्दे लेंगे । यह मुमकिन है कि यहां के लोगों को शरीक कर के जमीनें ली जाती हों इस मामले को दिखवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

हम और हरीश जी, हम लोग वहां से आते हैं उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है । मैं तो यहां स्पीकर हूं ज्यादा नहीं कह सकता, मैं तो बिल्कुल वहां बार्डर पर हूं, मेरी जमीन भी बार्डर पर है । मुझे इसकी काफी जानकारी है । मैंने इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

***श्री नवाब सिंह नागर-**

मान्यवर, आपने मुझे उत्तर प्रदेश की सरकारी भूमि के संबंध में हिन्दुस्तान के आज तक के सबसे बड़े घोटाले पर सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिए आभारी हूं । मान्यवर, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ा मामला है ।

श्री अध्यक्ष-

क्यों यह महत्वपूर्ण है इस पर बोलें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र में लगभग 12 लाख हेक्टेयर भूमि मोती लाल गोयल नाम के भू-माफिया ने बेचा हेराफेरी करके सरकारी राजस्व के कागजों में फर्जी प्रविष्टियां करके हड़प कर लिया है और उसकी कीमत लगभग 12 साढ़े 12 अरब बनती है । गाजियाबाद के डीएम श्री संतोष कुमार यादव ने अभी पिछले माह इस संबंध में 3 एफआईआर स्थायी गेट थाने में करायी है । यह जमीनें यूपीएसआईडीसी, नोयडा, ग्रेटर नोयडा और आवास विकास विभागों के क्षेत्र में पड़ने वाली जमीनें हैं । यह जमीनें नहरों, तालाबों, पोखरों और ग्रामसभाओं की है । इसका पट्टा करके फर्जी प्रविष्टियां करके, राजस्व के कागजों में हेराफेरी करके इन पट्टों को एसडीएम के यहाँ 229 बी में रेगुलराइज कराने की बहुत बड़ी हेराफेरी की गयी है । इस मामले में तत्कालीन आवास आयुक्त श्री राजेन्द्र भौजवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी से इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी और उसके आदेश भी हो गये थे और उसके बाद इस फाइल को गुम कर दिया गया है । इस मैटर में इतनी एफआईआर के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही आज तक नहीं की है ।

इस मामले में नोयडा और ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में भी कुछ पट्टे फर्जी पाये गये हैं और इसी 27 तारीख को 3 दिन पहले कासना थाने में रिपोर्ट की गयी है । यह एक ऐसा विषय है जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक लोग इनवाल्व हैं इस कारण से इस मामले की जांच सामान्य रूप से होना सम्भव नहीं है । इस मामले में 103 करोड़ रूपये का मुआवजा फर्जी तरीके से मोती लाल गोयल सिंचाई विभाग नोयडा से प्राप्त कर चुके हैं । कासना, हल्दौना, अमरपुर, चुहणपुर और शाहपुर आदि गांवों के 400 करोड़ के फर्जी पट्टे निरस्त हो करके उनकी एफआईआर कासना थाने में हुई है । शाहपुर, अमरपुर गोबर्धनपुर की जमीन जो इस तरह की थी तत्कालीन आईडीसी के नाम हस्तान्तरित की गयी है । उक्त गांवों के पट्टों को रेगुलराइज कराने वाले तत्कालीन डीएम बुलन्दशहर इस समय नोयडा प्राधिकरण में चैयरमैन के पद पर विराजमान हैं । मान्यवर, यह जांच का विषय है । उस समय जो उद्योग के प्रमुख थे उनके नाम बैनामा कराया गया है इस प्रकार से इस मामले में बहुत वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए हैं । उस समय जो तत्कालीन एसडीएम थे अब नोयडा प्राधिकरण में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हैं और ये लोग नोयडा में बैठकर इस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं । अगर इस तरह से चला जायेगा तो उत्तर प्रदेश कंगाल हो जायेगा, अगर इस पर ध्यान नहीं देगें । इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । अगर इस तरह से भू-माफिया करेंगे तो सरकारी जमीन खाली हो जायेगी । नोयडा और ग्रेटर नोयडा में जहां पर पट्टा लेना बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर इन्होंने कई एकड़ जमीन जो प्राधिकरण ने अधिग्रहीत कर लिया था ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, अगर यह कार्यवाही में नहीं आयेगा तो इस में कोई कार्यवाही नहीं होगी इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे 2 मिनट और दे दें ।

मान्यवर, नोयडा और ग्रेटर नोयडा के अन्तर्गत कई एकड़ जमीन गांव मोरना, गिझोड़ और होशियारपुर में जो प्राधिकरण ने अधिग्रहीत की थी, उसको डिनोटीफाइड करा लिया गया है, जो अभी खाली पड़ी है और इसका नक्शा कोर्ट से पास कराने का प्रयास किया जा रहा है । चूंकि इस मामले

में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, पीसीएस अधिकारी जुड़े हुए हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इससे ज्यादा गम्भीर और कोई विषय नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी मांग है कि इस प्रकार के भू-माफियाओं पर और संलिप्त अधिकारियों पर रासुका लगाया जाय और पूरे प्रकरण की सीबीआई जाँच कराई जाय । जब तक सीबीआई से इसकी जांच नहीं करायेंगे तो यह किसी भी कीमत पर सही जांच तक पहुंचने में सक्षम नहीं होने देंगे, इसलिये इसकी सी0बी0आई0 जाँच कराई जाय, यह मैं मांग करता हूं ताकि उत्तर प्रदेश की सरकारी जमीनों को बचाया जा सके ।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, यह माननीय सदस्य, पूर्व मंत्री भी रह हैं, जब यह घोटाला हुआ, उस वक्त बी0जे0पी0 और बसपा की सरकार थी, यह इनके समय में हुआ । इन्हें तो आज की सरकार को बधाई देना चाहिये कि इसने इस मामले में एफ0आई0आर0 करा दी ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान ।)

इस मामले में तो इन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिये । ये आज यह मामला उठा रहे हैं, तब कहाँ सो रहे थे, इस सरकार ने तो एफ0आई0आर0 करा दी है ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, माननीय सदस्य कई मौकों पर नोएडा की जमीनों पर बड़े चिन्तित रहे हैं, चिन्ता इनकी सही भी है । काफी दिलचस्पी रहती है, इन जमीनों को बचाने की । हम भी सहयोग करेंगे । यह गंभीर प्रकरण है और कार्यवाही भी हो रही है । सरकार की जानकारी में हैं । किसी भी तरह से जमीनों का दुरूपयोग नहीं होने दिया जायेगा । लेकिन जिनके खिलाफ कार्यवाही होनी है, उसे रोका जाना संभव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया इससे पहले भी नियम-51 में पिछली बार भी यह मामला आ चुका है ।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, सी0बी0आई0 जांच के बारे में तो बता दीजिए ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अगर आपका कोई प्लाट हो, जिसमें आप दिलचस्पी रखते हों, अगर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा हो, अगर कोई ऐसा प्लाट हो, जिसमें आपकी शिकायत हो तो उसके बारे में जानकारी दे दें तो अलग से जांच करा लूँगा ।

श्री नवाब सिंह नागर-

कौन सी जाँच करा देंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, नोएडा की जमीनों का मामला है और सारी जमीनों की प्लाटिंग है, उनके नं0 हैं, अगर किसी नं0 के बारे में माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो जाँच करा लेंगे, इसमें मैंने कौन सी खता

कर दी । अगर आप किसी प्लाट में शिकायत करना चाहते हैं तो उसकी अलग से जॉच हो जायेगी ।

(नवाब सिंह नागर के पुन: बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी, उत्तर भी आ गया । अब इनको बोलने दें ।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

मान्यवर, सारी जमीनों का तो कोई नं0 होगा, उसकी अलग से जॉच करा लेंगे । मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि आपकी परेशानी, दिलचस्पी और जितनी आपकी जिज्ञासा है और जितनी आपको चिन्ता है, सरकारी प्लाट के लिये, सरकारी जमीन के लिये कि उसका दुरूपयोग न हो तो मैं तो इसका स्वागत कर रहा हूं । इसमें आपसे तो हमें जानकारी मिली है, उस पर अवश्य कार्यवाही करेगें ।

***श्री भरत सिंह-**

मान्यवर, मेरे जनपद बलिया के दोआबा विधान सभा क्षेत्र में दर्जनों गांव की आम जनता, गरीब लोगों की जनमानस की समस्या है । लगभग दो दर्जन गांवों में आरसेनिक की वजह से भूजल एकदम जहरीला हो गया है । अक्टूबर, 2003 में यह बात प्रकाश में आई । हमारे यहां शाहपुर के एच0एन0 मिश्रा ने कम्प्लेन किया और जांच के बाद वैज्ञानिकों ने यह पाया कि यह पानी पीने योग्य नही है । 900 से अधिक हैण्डपंपों के नमूने ले करके जॉच हुई, उसमें पाया गया कि पेयजल में 10 परसेंट से अधिक पी0पी0बी0 मौजूद है । वर्ष 2003 के अक्टूबर माह में दीनानाथ सिंह जो बेलहरी ब्लाक के रहने वाले हैं, उनको स्किन कैंसर हो गया । हमारे इलाके में दो दर्जन गांवों में लोगों के पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है, समस्त हैण्डपंपों का पानी अर्सेनिक युक्त हो गया है । मैंने इस विषय पर वर्ष 2004 में भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और उस समय भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की तरफ से जवाब दिया गया था कि ऐसी कोई समस्या नहीं है । मान्यवर, बहुत सालों से गंगा के किनारे के गांवों में यह समस्या है और हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं । मैं इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज भी वहॉं के गांवों गंगापुर, बलिहार, केयरपुर और राजपुर एकौनी जैसे दर्जनों गांवों में जांच करा ली जाए तो मान्यवर, आज भी इन गांवों में सैकड़ों लोग पीड़ित हैं, स्किन कैंसर से पीड़ित हैं, पेट की किस्म-किस्म की बीमारियों से पीड़ित हैं, चर्म रोग से पीड़ित हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी यही समस्या है, यह समस्या गंगा नदी के किनारे वाले गांवों में होती है और यह अर्सेनिक तत्व हिमालय से आता है । अभी 27 जनवरी, को बनारस में सी0एस0ई0....

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री भरत सिंह-

[XXX XXX]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :-[XXX] यह अंश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

यह आक्षेप है ।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, मैं तो इस पर कुछ कहना चाहता हूं, भरत सिंह जी क्या आप इस पर चर्चा कराना चाहते हैं ।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, जब आप ही नहीं सुनेंगे तो हम आखिर किसे सुनायेंगे । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अर्सेनिक जहर तो पानी में मिला हुआ है, इसके पीने से स्किन कैंसर हो जाता है, पेट की बीमारी हो जाती है । मान्यवर, आपको हंसी आ रही है, हजारों लोग काल के गाल में समा गये हैं । हमारे और आपके जैसे सक्षम लोग तो मिनरल वाटर पी सकते हैं, लेकिन गाँव का आदमी तो वही जहरीला पानी ही पी सकता है । इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन गांवों का परीक्षण करवा लें, ताकि जनता को शुद्ध पानी तो मिल सके ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि तीन-चार सौ मीटर नीचे जॉच कराकर, अगर वहाँ पानी जहरीला नहीं हुआ है तो उस पानी का उपयोग पीने के लिए किया जा सकता है, उसकी व्यवस्था करायें । अभी वाराणसी में एक सेमिनार हुआ था जिसमें सुश्री सुनीता नारायणन ने बताया कि गंगा जल दूषित नहीं है और पाइप लगाकर गंगा जल के पानी को पिया जा सकता है अत: इसकी व्यवस्था करायी जाये । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे दोआबा क्षेत्र के गंगापुर, बलिहार आदि गांवों में नीचे 400 फुट से 1000 फुट नीचे पाइप डाल करके और जल निगम द्वारा टंकी बनाकर वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए । इस रोग से जो पीड़ित है उनके इलाज के लिए कोई कारगर दवाई का इंतजाम हो । मान्यवर, कोई भी दवा इस रोग में कारगर नहीं होती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आप नगर विकास मंत्री भी हैं, इसकी कोई समुचित व्यवस्था करें, जिससे समस्या का समाधान हो सके ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, भरत सिंह जी की बातों को सुनकर काफी ज्ञान बढ़ा । लेकिन आखिरी बात सुनकर मेरी परेशानी बढ़ गयी, इलाज नहीं है तो चलिये हम सब मिलकरके दुआ करते हैं । दुआ मैं भी करता हूं और आप भी कीजिए । (भरत सिंह द्वारा यह कहने पर कि आप पानी का इंतजाम नहीं करायेंगे) मित्र लोग भी डाटेंगे । अगर मौके पर डॉट लिये होते तो समस्या का समाधान हो गया होता । दवा तो है नहीं, दुआ से काम करेंगे । रही पानी की बात तो अगर भरत सिंह जी ने एक बार भी प्यार से कह दिया होता तो व्यवस्था हो गयी होती । मान्यवर, जरूरत यह है कि यह हमें प्यार से कहें तो हम पानी का इंतजाम कर देंगे ।

श्री भरत सिंह-

मैं तो हजार बार प्यार से कहने के लिये तैयार हूं । माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्यमंत्री जी मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री थे और मैं हिन्दू विश्वविद्यालय छात्रसंघ का महामंत्री था । संसदीय कार्यमंत्री जी, हमारे साथ ही 14 महीने तक जेल में रहे । इसलिए हमारे मित्र हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मेरा और भरत सिंह का बड़ा पुराना साथ रहा है । बड़े बुरे दिनों में साथ रहे, जेल के साथी हैं। वहाँ कुछ था ही नहीं सिवाय एक दूसरे के गम के साथी होने के । आप एक पत्र दे दीजिए और उसमें यह लिख दीजिए कि मैं प्यार से यह माँग कर रहा हूं ।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, आप भरत सिंह जी को अनुमति दीजिए तो वह जाकर प्यार कर लें ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अगर यही करना है तो यहीं क्यों न कर लें ?

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री लाल जी वर्मा की है ।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, 28 फरवरी को मेरे विधान सभा क्षेत्र इब्राहीमपुर के अंतर्गत एक संभ्रान्त प्रधान हैं जिनके खिलाफ आज तक एन0सी0आर0 का अपराध भी दर्ज नहीं है । कुछ व्यक्तियों से कहा-सुनी होने के उपरांत अपनी जान का खतरा बताकर पुलिस सुरक्षा की मांग की । मैं वहाँ था नहीं लेकिन जब मेरे संज्ञान में बात आयी तो मैंने थाने में पुलिस से कहा कि वह घिरे हुये हैं और उनको बचाइये । इस पर एस0ओ0 इब्राहीमपुर वहाँ जाते हैं और प्रधान को लेकर के अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं । सबसे दु:खद पहलू यह है कि वह जब इलफातगंज बाजार, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय जयराम वर्मा जी की मूर्ति लगी हुई है ।

मान्यवर, श्री जयराम वर्मा जी की मूर्ति के पास प्रधान को उतारकर उनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की गयी और पुलिस कर्मियों ने उनको गिरा-गिराकर मारा । इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का वातावरण है । सारे प्रधान आंदोलित हैं । कई बार रास्ता जाम की घटनायें हो चुकी हैं । हम सभी ने इसमें इंटरवीन किया और पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया लेकिन आज तक उस थानाध्यक्ष और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुयी है जिसके चलते उस क्षेत्र में दहशत व्याप्त है । मान्यवर, राम नयन वर्मा कर्मी जाति के हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसीलिये उनको बेरहमी से पीटा गया । मैं आपके माध्यम से इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बल देते हुये चाहूंगा कि इस घटना में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इसमें कार्यवाही तो हुयी है लेकिन आपने जो पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है, इसको मैं दिखवा लूंगा । उनको मुचलके पर छोड़ा जा चुका है । आपने जो पुलिस कर्मियों के बारे में जानकारी दी है इसको मैं अलग से दिखवा लूंगा अगर उनकी तरफ से कोई गलती है तो उस पर कार्यवाही होगी ।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है सारा दोष पुलिस का है ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इसको अलग से दिखवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 भरत सिंह और इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट हो गया है । अब अगली सूचना लेते हैं । मैं यह भी कहना चाहूँगा कि बजट पर भाषण और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब चर्चा होती है तो वह किसी विषय पर केन्द्रित नहीं होती है । यह जो आप नियम-56 में उठाते हैं इस पर बजट भाषण में चर्चा की जा सकती है । नियम-56 में इन विषयों को उठा देने से बजट में चर्चा करने वालों की संख्या सीमित होती जा रही है ।

(मुंशी लाल गौतम को पुकारे जाने पर।)

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, हमारा कार्यस्थगन नहीं लिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये ।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मैंने कल भी इस संबंध में एक सूचना दी थी जिसको आपने आज ले लिया है । इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, एक नाबालिग लड़की के साथ जो घटना हुयी है उसके बारे में मैं बताऊंगा और कुछ आंकड़े भी दूँगा ।

श्री अध्यक्ष-

आंकड़े न रखें, घटना के संबंध में बतायें ।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, 15 फरवरी, 2005 को श्री बाबूलाल पुत्र श्री सरनाम निवासी अकबराबाद थाना अहमतगढ़ अपनी बेटी कुमारी सोनू जो 14 साल की थी, लेकर चलते हैं । लगभग 7 बजे वह फतेहगढ़ बदायूं मेरठ रोड पर उतरते हैं तो वहां से उसका गांव करीबन दो-ढाई कि0मी0 है जब वह दो-ढाई सौ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मीटर चलाता है तो उसे रास्ते में चार बदमाश मिल जाते हैं और चारों ने अपने हथियार के दम पर उससे ढ़ाई-तीन सो रूपये छीन लेते हैं और हथियारों के दम पर उसको रास्ते से अलग हटाकर ले जाते हैं और बुर्जी के पास बदमाशों ने बाप को बन्धक बनाए रखा और बाप के सामने उसकी बेटी के साथ सामूहिक तीनों बदमाशों ने बारी-बारी से बलात्कार किया । इस घटना को लेकर 16 तारीख को सुबह ही ट्रेक्टर ट्राली में लोग भरकर थाने पर रिपोर्ट लिखाने गए लेकिन वहाँ पर एफ0आईआर0 दर्ज नहीं हुई । एस0ओ0 ने लोक लाज का भय दिखाया और कहा कि एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की क्या आवश्यकता है बाद में उसने कहा कि मैं अपने अधिकारियों से बात करके एफ0आई0आर0 लिख दूंगा और आपको खबर पहुंचा दूंगा । इसके बाद 19 तारीख को जो घटना हुई उसमें रामचन्द्र पुत्र जगमाल जो जिला पुलिस में तैनात है वह पत्नी गजना देवी के साथ स्कूटर पर जा रहा था । उसको भी बदमाशों ने रोक लिया उसके कट्टे की बट मारी और किनारे ले गए जहाँ पर चार पांच लोग इससे पहले ही बन्धक बने थे तो उनमें एक बन्धक छूटकर गांव आया और उसने हल्ला मचा दिया तब पुलिस वाले की बीबी की इज्जत मुश्किल से बच पायी वह थाने पर गया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई । इस बात को दैनिक जागरण अखवार वाले ने 22 तारीख को छाप दिया तब क्षेत्राधिकारी शिकारपुर से मैं मिलने गया उन्होंने कहा कि मैं उस पत्रकार के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करूंगा और उसके विरूद्ध मुकदमा चलाऊंगा । उसने झूठी रिपोर्ट दी है । डी0आई0जी0 मेरठ मौके पर गए थे वहां पर चूड़ी टूटी हुई मिली थीं लेकिन एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई इसमें एस0ओ0 सस्पेंड किए गए मैं और मेरी पत्नी को 28 तारीख को गोपनीय सूत्र से पता चला कि इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने भी अपनी जांच कराई है और उसमें तथ्य सही पाये गए लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई । मैं जब उस बेटी के घर मैं और मेरी पत्नी गये तो सारी घटना की जानकारी बैठे सैकड़ों लोगों के सामने दी जिसकी मैंने सी0डी0 तैयार कराई है । थाने गया तो हमसे उन्होंने कहा चौकीदार को साथ लेकर आएं । मान्यवर, मैं जब सात में पढ़ता था तो मेरी मां की मृत्यु हुई थी ।

श्री अध्यक्ष-

यह सब बातें बजट के समय रख लें । आपकी बात आ गई ।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मैंने अपनी माँ को बचन दिया था कि जो भी घटना दलितों के साथ होगी गरीबों के साथ होगी मैं ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और उनके लिए संघर्ष करूंगा । मैंने विधायक बनने का सपना भी नहीं देखा था ।

श्री अध्यक्ष-

आपने आवाज उठा दी ।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं कि मैं इस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता हूं [xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री मुंशीलाल गौतम-

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष-

कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री मुंशी लाल गौतम-

[xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इसमें जो आखिर में बात कही गई । आपने कहा लड़की को कहीं ले जाया गया । इसकी जांच हुई है और इसको पूरी गम्भीरता से लिया गया है । मुकदमा भी दर्ज हुआ है और परिवर्तित भी हो गया है 376 में । लेकिन लड़की अपने बयान बार-बार बदल रही है । जब लड़की खुद अपने बयान बदल दे तो पुलिस के लिये बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है । मामला दर्ज हो गया है और परिवर्तित भी हो गया है ।

श्री लाल जी टण्डन-

क्या उसका मेडिकल कराया गया ? अगर मेडिकल कराया गया तो वह बयान बदले न बदले? जब एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई तो मेडिकल कैसे हुआ होगा ? अगर एफ0आई0आर0 हुई तो मेडिकल हुआ होगा ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

बहुत देर से एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी थी और कई रोज पहले की बलात्कार की घटना बताई गई थी । अब उसमें वह चीज नहीं पाई जा सकती । इसलिये बाद में लड़की के कहने पर उसकी धारा परिवर्तित कर दी गई ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इसको निस्तारित करता हूं । इसके बाद टण्डन जी आपकी और गौर साहब की है । गौर साहब आप एक मिनट में कुछ कहना है तो कह लीजियेगा ।

(सदस्य मुंशी लाल गौतम के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

गौतम जी, आपकी बात आ गई है और उस पर संसदीय कार्य मंत्री का जवाब भी आ गया है। कानून व्यवस्था की जब बात आयेगी तब आप उस पर कह लीजियेगा ।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष जी के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, गौर साहब के बाद हमको भी विशेष उल्लेख में सुन लीजियेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, गौर साहब के बाद इनको सुन लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष-

स्वामी प्रसाद जी, बजट भाषण पर बोल लीजियेगा । हमने लक्ष्य बनाया है कि डेढ़ बजे तक यह खत्म हो जाय और उसके बाद बजट पर भाषण शुरू हो जाय । देखिये 10 मिनट बढ़ गये हैं । बजट भाषण में सारी बात कही जा सकती है ।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, फिर हमारी सदन में जरूरत क्या है । बाकी लोगों को किसलिये सुना जा रहा है । गौर साहब के बाद हमको सुन लीजियेगा ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, हमारी भी नोटिस है, बहुत गम्भीर मामला है । 200-250 लोग उजाड़ दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पढ़ा है । मैं एक-एक सूचना पढ़ता हूं जो आप लोग लिखकर देते हैं ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है । अनुसूचित जाति के साथ यह घटना हुई है ।

श्री अध्यक्ष-

यह जो लिया गया है वह भी अनुसूचित जाति का था । अब 27 सूचना है तो सब तो नहीं लिया जा सकता है । गौर साहब आप अपनी बात एक मिनट में कह दें ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक मिनट में नहीं आ पायेगा । 64 हजार शिक्षकों का चयन हो रहा है । इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत अनियमितता हो रही है । मेरे पास एक लिस्ट है, जो अनियमितताएं हो रही है उससे सदन को अवगत कराना चाहता हूं । यह एक मिनट में नहीं हो पायेगा ।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप कहें तो मैं इस पर चर्चा स्वीकार कर लेता हूं ।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)-

गौर साहब को सुन लें हम जबाव देने के लिए बैठे हुए हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हुकुम सिंह-

इनकी बात सुन लें ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के संबंध में 14 जनवरी, 2004 को शासनादेश निर्गत किया । इसमें कुछ व्यवस्था की गई कि इस आधार पर बी0एड0 और एल0टी0 के अभ्यर्थियों को चयनित किया जायेगा । मान्यवर, मेरे पास शासनादेश है । शासनादेश में व्यवस्था की गई है जो प्राप्तांकों का प्रतिशत है उसके आधार पर ऊपर के लोगों का चयन किया जायेगा । विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रथम सूची 27 मई, 2004 को तथा दूसरी सूची 25 अगस्त, 2004 को जारी की गई । इनमें चयनित अभ्यर्थियों के अन्तिम गुणांक को निम्न प्रकार दिया गया यह बहुत महत्वपूर्ण है । सामान्य पुरुष कला के छात्र का गुणांक 309.90, ओ0बी0सी0 पुरुष कला वर्ग 300.19, अनुसूचित जाति पुरुष कला वर्ग 280.03, अनुसूचित जाति पुरुष कला वर्ग 245.13, विकलांग श्रेणी 288.94, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी 262.53, सामान्य पुरुष विज्ञान 305.84, ओ0बी0सी0 पुरुष विज्ञान 281.47, अनुसूचित जाति पुरुष विज्ञान 178.90, अनुसूचित जनजाति पुरुष विज्ञान 192.44, इसके अतिरिक्त महिलाओं को जो चयनित किया गया वह निम्नलिखित है, सामान्य महिला विज्ञान 274.47, ओ0बी0सी0 महिला विज्ञान 188.12, अनुसूचित जाति महिला विज्ञान 192.44, सामान्य महिला कला 310.86 ओ0बी0सी0 महिला कला 290.56, अनुसूचित जाति महिला कला 256.58, अनुसूचित जनजाति महिला कला 170.74, महिला विकलांग श्रेणी 194.52, महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 174.98, यह गुणांक दिया गया है । दूसरी सूची के बाद कोई भी तीसरी सूची अधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुई है।

मान्यवर, तीसरी सूची गुपचुप ढंग से 5 नवम्बर 2004 को भेज दी गई । इसके पहले शासनादेश निकला था इसमें व्यवस्था थी कि प्रचारित प्रसारित किया जायेगा और प्रतिशत के आधार पर चयन होगा। जिनका मान्यवर, चयन किया है उसको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिला बलिया, संदर्भ संख्या-0000748 नाम दिव्या, पिता का नाम सी0 उपाध्याय,लिंग कोड-1, जाति कोड-1, ग्रुप कोड-2 टोटल गुणांक 285.19 है जबकि गुणांक 310.86 होना चाहिए । जिला कुशी नगर, संदर्भ संख्या-0000961 नाम नूतन श्रीवास्तव, पिता का नाम रजनीश शरण श्रीवास्तव, लिंग कोड-1, जाति कोड-1, ग्रुप कोड-2, टोटल गुणांक 265.00 और गुणांक चाहिए 310.86, इसी तरह प्रतापगढ़ जिला है संदर्भ संख्या 3302829 नाम बद्री प्रसाद तिवारी, पिता का नाम जगदीश प्रसाद तिवारी, लिंग कोड-2, जाति कोड-1 ग्रुप कोड-2, टोटल गुणांक 268.79, जबकि गुणांक होना चाहिए 309.90 । इसी तरह मान्यवर, जिला आजमगढ़, संदर्भ संख्या 0002749, नाम शैलेन्द्र सिंह पिता का नाम शिवानन्द सिंह, लिंग कोड 2, जाति कोड 1, ग्रुप कोड गुणांक 289.24, जबकि गुणांक होना चाहिए 309.90 । जिला एटा संदर्भ संख्या 0003312 नाम अजय पाल सिंह लिंग कोड 2, जाति कोड 4, ग्रुप कोड 2, गुणांक 275.65 है जबकि 300.19 गुणांक होना चाहिए । जिला एटा भृगुनाथ सिंह लिंग कोड 2, जाति कोड 4, ग्रुप कोड 2, गुणांक है 283.47 और होना चाहिए 300.19 ।

मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि इससे ज्यादा अनियमितता और भ्रष्टाचार का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है । जो लोग चुने गये हैं, उनमें से कई लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं ओर रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं । हमारे पास भी उनमें से कुछ रिट पिटीशन के नम्बर हैं, रिट पिटीशन नं0-4542, रिट पिटीशन नं0-3974, रिट पिटीशन नं0-1241 और रिट पिटीशन नं0-8157, इसमें इन अभ्यर्थियों

ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में कहा है कि हमारे अंक जो चयनित हुए हैं, उनसे ज्यादा है तो हमें भी अवसर मिलना चाहिए । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पारदर्शिता के लिए यह जो तीसरी सूची जारी की गई है, क्या उसको प्रकाशित किया गया था ? यह बिल्कुल गुपचुप ढंग से किया गया है, मेरा सुझाव है कि इस चयनित सूची की जांच विधान सभा के सभी दलों के सदस्यों की एक समिति बनाकर करा ली जाय और उसमें जो दोषी पाया जाए उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाय । मान्यवर, जब कोई भी शिक्षक नियुक्त होता है तो वह 33 वर्ष तक शिक्षक का कार्य करता है । इसलिए मेरा आग्रह है कि इसकी जांच करा ली जाए ।

एक दूसरा अनुरोध करना चाहता हूं, जिनका चयन किया गया है, उनसे अधिक अंक जो अभ्यर्थी पाए हैं, जो हाईकोर्ट गए हैं, उन सब को चयनित कर लिया जाए । अन्तिम निवेदन है, आप सारे प्रकरण को देखकर अगर चर्चा करा लें, तो अच्छा होता ।

श्री किरन पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, गौर साहब ने अनियमितता और भ्रष्टाचार की जो बात कही है, हो सकता कि गौर साहब का संबंध भ्रष्टाचार से रहा हो, हमारा तो नहीं है । मैं 1980 से लगातार विधायक हूं, केवल एक बार हारा हूं, जीवन में । यहां पर फर्जी आंकड़े देकर दाल गलेगी नहीं । जिनकी बात आप कह रहे हैं, वह लोग फर्जी आंकड़ों को दिखाकर कोर्ट जा रहे हैं । हमने चीफ स्टैंडिंग काउन्सिल से निवेदन किया है कि वह माननीय न्यायालय से निवेदन करें कि कोई निर्णय देने से पहले वह गवर्नमेण्ट का पक्ष भी सुन लिया करें । एक रैकेट है इलाहाबाद में वकीलों का जो 15-20 हजार रूपये लेकर एक लाइन लिखवा दे रहा है कि सरकार विचार करे, सरकार विचार करे । जो आपने नाम बतायें हैं, मेरी चुनौती है कि यदि आप की बात सत्य है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और यदि आपकी बात सही नहीं है तो आप क्या करोगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

चुनौती स्वीकार कर लें, सदन की समिति बना दी जाए । मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि आप एक समिति बना दें । माननीय मंत्री, किरण पाल जी ने चुनौती स्वीकार की है । सरकार पर लांछन लगा है, उसे सरकार स्वीकार करती है, एक समिति बना दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

श्री किरन पाल सिंह-

सारा पारदर्शितापूर्ण चुनाव हुआ है, इनको इस बात से चिढ़न हो गई है । सारे रिकार्ड कोई भी चेक कर सकता है । आप यहां मंगा सकते हैं । इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य और विधान परिषद् का कोई भी माननीय सदस्य सारे रिकार्ड को देखकर चेक कर सकता है । उसको मैं चाय पिलाऊंगा और पूरे रिकार्ड उसके सामने रख दूंगा । आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं । माननीय सदस्य ने अपने शब्दों में बलिया की दिव्या की बात कही, दिव्या का 285.19 है ।

मान्यवर, यह हैण्डीकेप्ट है और इसमें कट आफ 194.52 है । दूसरा जनपद कुशीनगर की नूतन श्रीवास्तव है जिनके नम्बर हैं 265.00, यह हैण्डीकेप्ट हैं और इसमें कट आफ है 194.52, इसी प्रकार जनपद प्रतापगढ़ के श्री बद्री प्रसाद तिवारी का है 268.79, यह फ्रीडम फाइटर आश्रित है और इसमें कट आफ है 262.53 इसी प्रकार जनपद एटा के श्री जयपाल सिंह का 275.65 है यह भी

फ्रीडम फाइटर आश्रित है और इसमें कट आफ है 262.53, इसी प्रकार जनपद आजमगढ़ के श्री शैलेन्द्र सिंह का है 289.24, यह हैण्डीक्राफ्ट है और इसमें कट आफ है 288.00 और छठा जनपद बनारस का, यह ओ0बी0सी0, साइन्स ग्रेजुएट है इसका है 283.47 और इसमें कट आफ है 281.47 । आपकी सूचना मिथ्या है । आपको कट आफ का कैसे पता चला ? हमने अखवारों में यह छपवाया था । हर एक कैटेगरी की कट आफ सूची दी गयी है । तीन महीने तक सबके आवेदन पत्र लिये गये । दो-दो काउण्टर इसके लिए खाले गये । एग्जामिन किया गया, एग्जामिन करने के बाद, यह सही बात है कि 2-4 लोगों का हक मर जाता है लेकिन हमने हक दिया है । न्यायालय में कितनी रिट दाखिल हो रही है । विचार करें, विचार करें लिखकर आ रहा है । कोई भी माननीय सदस्य जाकर चेक कर सकता है । इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और न किसी अभ्यर्थी का किराया खर्च हुआ है सबको घर बैठे नियुक्ति पत्र भेजे गये हैं । पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हो रही है । फिर भी मैं कहता हूं कि आपकी जो जानकारी में आया है वह बतायें । सब अखवारों में विज्ञापन छपवाया, सभी सेलेक्शन मेरिट से हुए हैं । एक-एक चीज साफ है । आप जाकर देख सकते हैं । यही मुझे कहना है । धन्यवाद।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर -

मान्यवर, मेरे पास जो सूची है वह कम्प्यूटराइजड है । उच्च न्यायालय में जो केस गये । सरकार की तरफ से स्टेण्डिंग काउंसिल है । अगर यह बात सही है तो यह बात वहाँ क्यों नहीं रखी । जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से अनुरोध किया गया । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सूची को मंगाकर देख लें ।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, यह जो हैण्डीक्राफ्ट का सर्टिफिकेट है । जब इन्होंने एप्लाई किया था तो उस समय हैण्डीकेप्ट का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था बाद में फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आये तो कैसे मान लें । कोर्ट के निर्देश के बाद सब चीजों की जांच के बाद जो सच्चाई होगी उसमें ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे । हमने कोर्ट से निवदेन किया है कि जो भी निर्णय दें तो हमको भी सुन लें ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें आप एक समिति बना दें जो इस सूची की जांच करे ।

श्री अध्यक्ष-

पूरी चर्चा हो गयी । अब इसमें क्या करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्तर आया है माननीय सदस्य ने जो अपनी बात रखी इसमें इन्होंने सारा विवरण रखा । हर कैटेगरी का अलग है, हैण्डीकैप का, सामान्य का, फ्रीडम फाइटर का अलग है । जो कोड नम्बर है यह देख लें । कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट दाखिल कर दिया हो । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया है कि इसमें चाहें तो सदन की एक समिति बना दें, तो वह बना दी जाय ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी माननीय मंत्री जी ने सारी बातें बता दी । जिसका नाम लिया है वह हैन्डीकैप है । उन्होंने यह भी कहा है कि सारे रिकार्डस निदेशालय में रखे हैं आप चाहें तो देख सकते हैं, तो फिर क्या बात है ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो इन्होंने पढ़ा है वह सारे के सारे सामान्य श्रेणी के हैं । यही तो अन्तर है । माननीय सदस्य का कहना है कि यह आरक्षित श्रेणी के हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आप मुझे सूची दे दीजियेगा । मैं दिखवा लूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, यह शिकायत आयी है कि कहीं फर्जी सर्टिफिकेट जमा करके सलेक्शन तो नहीं कर दिया गया । हम सघन जांच करा रहे हैं इसमें अगर किसी को फर्जी सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो उसको नाकैरी से निकाल दिया जायेगा और उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 की सूचना समाप्त हुई । अब माननीय मौर्या जी अपना बजट भाषण करें ।

(श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री राम इकबाल सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी व श्री मुंशी लाल गौतम इत्यादि के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी नियम-56 की सूचना को नियम-51 में परिवर्तित कर दीजिये ।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, एक दलित की बेटी का बलात्कार हुआ है । मेरे पास इसकी सीडी है ।

श्री अध्यक्ष-

सीडी मत दिखायें नहीं तो जब्त कर ली जायेगी । इनसे सीडी ले लीजिये ।

(सीडी ली गयी)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी सूचना को नियम-51 में परिवर्तित कर दीजिये

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

मैंने कर दिया है ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आज गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ी जा रही है । यह अति लोक महत्व का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायें । डेढ़ बजे का समय मैंने बजट भाषण के लिए रखा था अब इस समय दो बज रहा है। कृपया सहयोग करें ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, हमें इसमें सुन लें ।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, हमको भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी सूचना ले रहा हूं । माननीय इकबाल सिंह जी बैठ जायें । प्रागी लाल अहिरवार जी आप भी बैठ जायें । मैंने गौतम जी की सूचना को नियम-51 में ले लिया है क्योंकि वह अनुसूचित जाति का मामला था ।

(व्यवधान)

माननीय इकबाल सिंह जी, आप अपनी सूचना हमें दे दीजिये ।

श्री राम इकबाल सिंह-

ठीक है ।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, हमें भी एक मिनट का समय दे दें । हमने भी नियम-56 में सूचना दी थी और आपने उसको नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है । इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आप उसमें सवाल कर लीजियेगा ।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, [xxx xxx xxx xxx]

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) जी , आप बैठ जाएं, कुछ नहीं लिखा जाएगा । आपकी सूचना को नियम-51 में स्वीकार कर लिया गया है, तब आप, उस समय जितना प्रश्न करना चाहें कर लें, लेकिन इस समय कुछ नहीं । मौर्या जी आप इन्हें नियमों के बारे में बतायें ।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, जब इस सदन में मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(सदस्य सदन के बाहर चले गये)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आप अपना बजट भाषण प्रारम्भ करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट भाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिये मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, भाषण करने जा रहे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप जा रहे हैं । क्या आप उनके भाषण से डर गए ?

***संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-**

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ साथी हुकुम सिंह जी, बराबर बहुजन समाज पार्टी को समाज वादी पार्टी में विलय करने पर तुले हुये हैं । हम तो इसका स्वागत करते हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सन् 2005-2006 के बजट अनुमानों पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है, उसका मैंने ठीक से अध्ययन किया, उसमें व्यवहारिकता नाम की कोई चीज नहीं रही और मुख्यमंत्री जी ने अपनी गलती स्वीकार की है इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । उन्होंने शुरू में ही कहा है कि वित्तीय कारोबारी संस्कृति का दशक पूर्व लोप हो चुका था और दशक पूर्व कार्यकाल था, इस समय जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री भी यहीं थे और कारोबारी संस्कृति का लोप अपनी सरकार के समय में हुआ, इस बात को स्वीकारते हैं, उनकी इस सही बात के लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । मान्यवर, इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इस वित्तीय विवरण पुस्तिका में मान्यवर, अगर आप देखेंगे तो सन् 2003-2004 में मान्यवर, तो भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयकरों में राज्यांश सहायता अनुदान एवं कर्ज की स्थिति है वह रही है 21272.53 आय-व्ययक का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जो अनुमान रहा और वास्तविक आंकड़े जो रहे 18835.33 इस तरह से जो कमी आई मान्यवर, वह ऋण 2437.20 रहा । इसी तरह से कर राजस्व में जो अनुमानित 2003-2004 का आय-व्ययक था 14539.05 वास्तविक व्यय रहे 13601.22 और उसमें कमी आयी 937.83 करोड़ की । इसी तरीके से करेतर राजस्व में उनका 2003-2004 का जो आय-व्ययक अनुमान रहा 1747.89 वास्तविक आंकड़े रहे 2282.08 और कमी आई 534.19 की । मान्यवर, हमने इसका ब्योरा इसलिए दिया है, ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके, इसी तरह से पूंजी लेखा में जो आंकड़े रहे उसमें भी कमी आई है मान्यवर, यह तो आंकड़े रहे वर्ष 2003-2004 के, इसी तरीके से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, इसी विवरण पुस्तिका में दिया हुआ है, सन् 2004-2005 का ।

मान्यवर, सन् 2004-2005 में केन्द्रीय करों का जो राज्यांश है और सहायता अनुदान तथा कर्ज है उसका आय-व्ययक अनुमान में जो उल्लेख है वह है 23,171.34 करोड़ रूपये का और जो पुनरीक्षित अनुमान रहा वह 24,397.6[illegible] करोड़ रूपये का और कमी आयी है 1,226.26 करोड़ रूपये की । इस तरीके से यह राजस्व में कमी आयी है (-) 356.15 करोड़ रूपये की और इसी तरीके से मान्यवर, करेत्तर राजस्व में कमी आई है 282.78 करोड़ रूपये की । यह आपका 2004-2005 में यह लेखा-जोखा रहा । इसी क्रम में मान्यवर, हम सन् 2005-2006 में आना चाहते हैं । मान्यवर, 2005-2006 का जो आपका पुनरीक्षित अनुमानित मान्यवर, बजट है वह केन्द्रीय करों में राज्य के अंश और सहायता अनुदान में 24,397.60 करोड़ रूपये का है और अनुमानित है 36,480.83 करोड़ रूपये का और कमी आई है 2,082.83 करोड़ रूपये की । मान्यवर, कर राजस्व में 15,675.10 करोड़ रूपये का उल्लेख है, अनुमानित है 18,290.58 करोड़ रूपये का और कमी आई है 2,615.48 करोड़ रूपये की । यह इसका ब्यौरा हम इसलिए देना चाहते हैं कि जब दिनों-दिन हर प्रकार का इनका जो बजट प्रस्तुतीकरण है उसमें जो इनका स्रोत है उनमें जब कमी आ रही है तो कैसे आप इस प्रदेश को समुन्नत प्रदेश बनाना चाहते हैं इसे उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प आप कर रहे हैं इससे यह जाहिर होता है ।

(इस समय 2 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बंशीधर राज पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इसी क्रम में मैं आपसे निवदेन करना चाहूंगा कि यह जो इनकी पुस्तक है 2005-2006 की उसके वार्षिक विवरण के पृष्ठ-39 पर दिया हुआ है और उसमें जो राजकोषीय घाटे का विवरण दिया गया है उसको आप देख लें । मान्यवर, यह स्पष्ट रूप से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से यह चरम सीमा पर घाटा बढ़ा है । मान्यवर, जब कि इसके पूर्व में उसमें नियंत्रण था । और कमी आती रही । लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में सत्ता को संभालने का मौका मिला है, वह राजकोषीय घाटा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । यह मान्यवर, इसी पेज-39 पर दिया हुआ है । इसमें साफ लिखा हुआ है जिसमें 1995-1996 से लेकर के मान्यवर, 2005-2006 तक के बजट का यह इनका राजकोषीय घाटा है, जो प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर, इसमें मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि सन् 2001-2002 में यह 9,858.13 करोड़ रूपये का यह रहा राजकोषीय घाटा और 2002-2003 में उससे कम हो गया 9,496.91 करोड़ रूपये तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी । और अब जब समाज वादी पार्टी की सरकार आयी थी 2003-2004 में वह घाटा बढ़कर हो जाता है 16,648.11 करोड़ रूपये का । मान्यवर, यह जो वर्तमान में जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है यह भी लगभग 17,000 करोड़ रूपये के इर्द-गिर्द जा रहा है । यानी कि जब से समाज वादी पार्टी की सरकार आई है तब से राजकोषीय घाटे में बढ़ोत्तरी हुई है और उसके बावजूद यह सरकार दावा करती है कि हम उत्तर प्रदेश में समग्र विकास करके इसको उत्तम प्रदेश बनायेंगे । केवल मान्यवर, कह देने से सरकार नहीं चलती है सरकार चलाने के लिए और सही मायने में सही सांचे-ढांचे में सरकार को

व्यवस्थित करने के लिए सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए । नीयत अगर साफ नहीं है तो हम बजट कितना ही ज्यादा क्यों न बढ़ा लें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि अब तक का यह सबसे ज्यादा रूपयों का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है ।

सबसे ज्यादा रूपयों का बजट प्रस्तुत करने में वाहवाही नहीं है । वाहवाही यह है कि उसका सदुपयोग करके कैसे इस बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश को सुधार की हालत में ला सकते हैं । यह आपका प्रदेश बदहाली की हालत में जा रहा है । सारी की सारी व्यवस्था चरमराती चली जा रही है । केवल कहकर कि उत्तर प्रदेश को सरकार उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है काम चलने वाला नहीं है । यह उत्तम प्रदेश बनाने का सब्जबाग उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाना चाहते हैं इससे उत्तर प्रदेश चलने वाला नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पुस्तिका है मैं उसके आंकड़े पढ़ रहा हूं । जो इनका यह चार्ट है उसमें इनके पास तो 31 प्रतिशत खाली आय का, इनकी आमदनी है, यह 28 प्रतिशत केन्द्रीय करों में राज्यांश के रूप में आता है और 8 प्रतिशत केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में, और लोक ऋण के रूप में 24 प्रतिशत आता है और एक प्रतिशत ऋण एवं अग्रिम की वसूली से । यह इसके बूते पर उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं और इस पर चलाकर उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश बनाने का सपना सजोये हुए हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो इनकी आय थोड़ी बहुत है भी, वह जाता कहां है ।

मान्यवर, सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर 16 प्रतिशत खर्च होता है लेकिन जो ऋण लिया जा चुका है उस पर 18 प्रतिशत ब्याज देते हैं करीब पूरी प्रदेश के कर्मचारियों पर जितना हम खर्च करते हैं उससे 2 प्रतिशत ज्यादा हम कर्ज की अदायगी में देते हैं । इसी के साथ साथ जो हम ऋणों पर ब्याज देते है। 5 प्रतिशत, वही नहीं है अगर 18 प्रतिशत उसमें जोड़ दिया जाय तो यह 23 प्रतिशत होता है। 23 प्रतिशत हम ब्याज चुकाने में दे दिया करते हैं तो जो इनकी व्यवस्था है उसमें पूंजीगत परिव्यय 13 प्रतिशत अन्य राजस्व व्यय 15 प्रतिशत है । अब ढपोरखंखी बयाजबाजी ये यह उत्तर प्रदेश सुधरने वाला नहीं है । इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए । आज उत्तर प्रदेश कहां पहुंच जा रहा है । मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन दृष्टांत देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और इससे कम रूपयों का बजट प्रस्तुत हुआ था लेकिन उस कम रूपयों के बजट प्रस्तुतीकरण के पश्चात् भी हमने उत्तर प्रदेश में देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज्यादा गरीब लोगों के गांव को चुनकर अम्बेडकर गांव के रूप में, पानी बिजली सड़क, आवास, स्कूल, इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और तमाम सारे विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया । यह जो सरकार आई यह कहती तो है कि हम 73 प्रतिशत गांव के विकास पर लगायेंगे लेकिन मान्यवर, यह सरकार को लगभग डेढ साल होने जा रहे हैं और डेढ़ साल बीत जाने के बाद यह शर्म की बात है कि इसी सदन के अन्दर माननीय नेता सदन ने अम्बेडकर गांव का नाम बदलकर समग्र ग्राम विकास योजना किया था, इसका स्वागत है, किसी भी नाम पर विकास हो, मैं कहना हूं कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर कर दीजिए, डा0 लोहिया के नाम पर कर दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता-

आपको 15 मिनट से ज्यादा हो रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर 5 मिनट हो रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता-

15 मिनट आपके हो गये हे और 15 मिनट की माननीय अध्यक्ष जी ने पहले से व्यवस्था दे रखी है । आप दो मिनट और बोल लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं बहुत संक्षेप करने का प्रयास कर रहा हूं । मान्यवर, यह बजट पुस्तिका मैंने पढ़ी और साथ ही साथ जो इनका सारा ब्योरा है, वह देखा । उसको देखने से यह कहीं से भी उत्तर प्रदेश का बजट नहीं लगता है । इसको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव का प्रधान अपने गांव का बजट रख रहा हो । मुझे तो यह सैफई का बजट नजर आया, उत्तर प्रदेश का बजट है ही नहीं । सैफई में अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा संकुल, सेटेलाइट केन्द्र की स्थापना और लायन सफारी की स्थापना, यह सारी घोषणायें इसमें हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर केवल अपने घर को सजाना, गांव को सजाना, यह कहाँ की बुद्धिमानी है । इससे पूरे प्रदेश के साथ हकतलफी हो रही है । मैं तो मुख्यमंत्री जी से यह कहूंगा कि सदाशयता दिखाइये और सारे धन को बराबर-बराबर बाँटकर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करिये तो हम लोग इसका स्वागत करते । लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नीयत में कहीं न कहीं कमी है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगारपरक इस बजट को प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहा है । हम यह कह देना चाहते हैं कि रोजगार कैसे मिलता है, काम के बदले अनाज....

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्या जी, समाप्त करिये, 18 मिनट हो चुका है । दूसरे लोगों को भी बोलना है ।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा दल है और निश्चित रूप से जब हमारे दल के नेता बोल रहे हैं तो उनके लिये आधा घन्टे से कम समय तो नहीं होना चाहिये । आप कांग्रेस पार्टी के नेता का समय देख लीजिये, अगर इससे ज्यादा हमारा समय हो तो कहिये । आप इतनी नाइंसाफी न करें ।

श्री अधिष्ठाता-

नेतागण के लिये 15 मिनट, माननीय सदस्यों के लिये 10 मिनट, माननीय अध्यक्ष जी पहले ही यह व्यवस्था दे चुके हैं । हब आप समाप्त करें ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, संसदीय परम्परा में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है । इसमें आप देख लें । कांग्रेस दल की सदस्य संख्या हमारे दल की चौथाई भी नहीं है और उनके नता को आधा घन्टा का समय दिया गया और हमको 15 मिनट में सीमित करना, यह सही नहीं है, यह तो वही बर्ताव हे तो समाज हमारे साथ अभी तक करता आया है ।

श्री अधिष्ठाता-

यह व्यवस्था सबके लिये है । अगर आप व्यवस्था बनाये रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल-

सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तो मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा था कि इस बजट में बहुतायत लोगों को रोजगार देने की मंशा जाहिर की गयी है, हम इसका स्वागत करते हैं । लेकिन काम के बदले अनाज योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो भी गेहूं-चावल आता है, वह बिचौलियों के माध्यम से कहीं बांग्लादेश चला जाता है, कहीं बड़े-बड़े दुकानों पर चला जाता है । मैं बताना चाहता हूं कि 25 हजार करोड़ रूपये का यह घोटाला हुआ है । जिस खाद्यान्न से गरीबों को रोजी-रोटी दी जाती है, काम के बदले अनाज दिया जाता है, आज वह सत्ता में बैठे हुये हमारे जो माननीय मंत्रीगण हैं, उनके संरक्षण में बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हवाले हो रहा है उनके संरक्षण में बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हवाले उत्तर प्रदेश हो रहा है । मैं कह देना चाहता हूं कि यह सरकारी विवरण है, जो जिलाधिकारियों के माध्यम से, विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मिले हैं । अगर हम विवरण देना शुरू कर देगें तो बड़ा समय लग जायेगा । 25 हजार करोड़ रूपये का खाद्यान्न घोटाला था, जिससे गरीबों को रोजगार मिल सकता था ।

श्री अधिष्ठाता-

आपको 25 मिनट से ज्यादा समय मिल चुका है ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, क्या कांग्रेस के नेता से भी कम समय देगें ?

श्री अधिष्ठाता-

सभी दलों के नेताओं को बराबर का समय दिया गया है, दलों के नेताओं में कोई विभेद न कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह हर बार कांग्रेस से ही क्यों तुलना करते हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि मुगल साम्राज्य में जब राजा मस्त हो जाता था, तो राज्य के लोग दरबारी उसे सावधान करते थे वही हालत आज है ।

नहिं पराग, नहीं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल,
अली कली ही यों बंध्यो, अमर - सहारा जाल ।

मान्यवर, यह हाल हो गया है । आज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश अमर सिंह और सहारा के जाल में फस गया है और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है । सहारा का विकास हो रहा है, अमर सिंह का विकास हो रहा है, और साथ ही साथ उनके साथ में रहने वाली हीरोईनों का विकास हो रहा है, पूंजीपतियों का विकास हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि आज ऊर्जा

शहर के नाम पर सारी की सारी सम्पत्ति अम्बानी परिवार को दी जा रही है, आवास-विकास की नाम पर बड़े शहरों की करोड़ों की जमीन सहारा को दिया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश को स्वावलम्बी प्रदेश बनाना है, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना है और एक उत्तम प्रदेश बनाना है तो हमें अपनी नियति को साफ रखना होगा । मान्यवर, यह बजट एक ढपोलशंखी बजट है, इससे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होना है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री राम करन आर्य-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2005-2006 के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । अधिष्ठाता महोदय, यह बजट जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रखा है, मैं 10 वर्षो से इस विधान सभा में आ रहा हूं । सदन के लोग कुछ भी कहें, मेरी अपनी राय है कि इससे बढ़िया बजट आज तक विधान सभा में नहीं आया है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें कृषि,शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार के सम्बन्ध में सबसे ज्यादा बजट का प्रस्ताव किया गया है । अभी जो बजट में आया है, हमारी पूरी आय 66494.10 करोड़ रूपये है, हमारा व्यय 69295.19 करोड़ रूपये है और कुल घाटा 1801.09 करोड़ रूपये है । 1801.09 करोड़ रूपये का घाटा जो है लोकलेखा से समायोजित किया जायेगा । अभी हमारे साथी कह रहे थे कि यह कुछ क्षेत्र के लिए है, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि वह कौन से चश्में से देखते हैं । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सा विशेष क्षेत्र है । मा0 मौर्या जी का चश्मा गजब का होता है, जब वह यहां रहते हैं तो दूसरा होता हे और वहां रहते हैं तो दूसरा हो जाता है ।

श्री अधिष्ठाता-

आर्या जी, आप मौर्या जी का चश्मा मत लगाईये ।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा धनराशि का प्राविधान किया है । इसलिए कि यदि कृषि की तरक्की नहीं होगी तो हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती है । आज जो देश की और प्रदेश की सकल आमदनी है और जो प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की है और देश की, उसमें बहुत अन्तर है, 10 हजार और 20 हजार रूपये का अन्तर है । अगर इतना हो जायेगा तो इसका असर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा । यह बात सही है माननीय मौर्य जी, जब तक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बनाया जायेगा तब तक हमारा देश उत्तम नहीं हो सकता और दुनिया के पैमाने पर हमारे देश की साख नहीं बढ़ सकती । आपने तो इस प्रदेश को बहुत लूटा है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आपने जो किया, उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं । हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, पहली बार 12 रूपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बढ़ाया है । आज गांवों व किसानों के बीच में केवल मुलायम सिंह की चर्चा होती है, लोग वाहवाही कर रहे हैं । इन लोगों के जमाने में एक नहीं तमाम गांवों के किसानों के गन्ने सड़क पर सूख गये थे, कोई पूंछने वाला नहीं था । हम लोग उस समय विपक्ष में बैठते थे, बार-बार आवाज उठाते थे तो मौर्याजी मुस्कराते थे और ऐसा लगता था कि उनका किसानों से कुछ लेना-देना नहीं है । उस समय आपकी पार्टी की नेता ने भी कहा कि हमारे लोग कहां गन्ना पैदा करते हैं ? हमारी सरकार किसानों की हितैषी है । हमने [illegible] ब, मजदूर व किसानों [illegible] लिए बजट में प्रावधान किया है ।

हमारी सरकार ने 6 चीनी मिलों को लगाने की बात कही है । 6 चीनी मिलों के लगने से 5 हजार लोग काम पायेंगे और न जाने कितने किसानों व गरीबों को फायदा होगा, मूंगफली बेचने वाला, चाय की दुकान करने वालों को फायदा होगा । 6 मिलें लगेंगी तो आप आंकलन कीजिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि आप भी किसान परिवार से आते हैं । हमारी सरकार ने पहली बार किसानों के हित में 102 कृषि बाजार का प्राविधान रखा है । अभी किसानों को अपना अनाज,अपने सामान को लेकर दूर जाना पड़ता है, किसानों को दूर न जाना पड़े इसलिए हमारी सरकार ने 102 कृषि बाजार स्थापित किये हैं । इसके साथ ही हमारी सरकार ने सड़कों का जाल बिछाने की बात कही है । हमारी सरकार ने सड़क योजना बनायी है जिसमे हम सड़क, पुलिया, सेतु आदि बनायेंगे । हमारे यहां तमाम कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई है । हमारे यहां एक बीघे में जितना अनाज पैदा होता है, उतनी ही भूमि पर चीन में ढाई गुना अनाज पैदा होता है । अगर हम एक बीघे में 10 क्विंटल अनाज पैदा करते हैं तो चीन में 25 क्विंटल होता है । हमें चीन से मुकाबला करना पड़ेगा । हमारी जो खेती है, जो ऊसर, बंजर भूमि है उसके लिए हमारी सरकार ने भूमि सेना बनायी है । डा0 लोहिया कहते थे और हम ऐसी पार्टी से आये हैं, हमारे मौर्या जी बैठे हैं, 5-6 साल पहले यह भी डा0 लोहिया का गुणगान करते थे । डा0 लोहिया ने कहा था कि इस मुल्क में भूमिहीन गरीबों को उनकी भूमि देने के लिए भूमि सेना बनायी जाये। बीहड़ के इलाके में जितना पैसा डाकुओं के उन्मूलन पर खर्च किया जाता है वही पैसा उसको समतल करने पर खर्च किया जाये ।

मान्यवर, वहां के जो लोग हैं उनसे, भूमि सेना बनाकर, वहां की जमीन को समतल करवाया जाय और उनको मजदूरी दी जाय और जब भूमि समतल हो जाय तो गरीबो को वह भूमि बांटी जाय इससे उनकी गरीबी दूर होगी । मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई व्यक्ति ऐसा न हो जिसके पास खेती की जमीन न हो, घर बनाने के लिये जमीन न हो । मान्यवर, सरकार द्वारा जो ऊसर सुधार योजना लागू की जा रही है इससे 20 हजार एकड़ ऊसर भूमि का सुधार किया जायेगा । मान्यवर, इसी तरह से जनता को सुविधा देने के लिये 1125 नयी बसें खरीदी जा रही हैं और रोजगार योजना के अंतर्गत 440 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है । इससे गांव के लोगों को राहत मिलेगी । हमारी सरकार ने 5 हजार छोटे उद्योगों का प्राविधान किया है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा । डा0 लोहिया और महात्मा गाँधी कहा करते थे कि हिंदुस्तान में दैत्याकार मशीनों से इस देश की तरक्की नहीं होगी । इस देश में छोटे-छोटे उद्योग-धंधों और कुटीर उद्योगों की आवश्यकता है । बड़ी मशीनें गरीब को रोजगार देने में बाधा पहुंचाती है और गरीब के पेट पर लात मारती हैं । इसीलिये सरकार ने 5 हजार छोटे उद्योगों का प्राविधान किया है ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने मछुआरों के लिये 2130 मकानों की व्यवस्था की है । इसी प्रकार हमारी जो गांव में रहने वाली मातायें बहने हैं उनके लिये शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है और उनके लिये 12 लाख शौचालय बनाये जायेंगे । गांव में रहने वाली हमारी इन बहनों के जब पेट खराब हो जाते हैं तो शर्म के मारे वह बार-बार शौच नहीं जा पाती हैं जिससे वह पेट की मरीज हो जाती हैं उनका जीवन बरबाद हो जाता है इसलिये इस जनप्रिय सरकार ने उनके लिये 12 लाख शौचालयों की व्यवस्था की है । अनुसूचित जातियों के लिये हमारी सरकार ने हर जिले में एक छात्रावास की व्यवस्था की है । इसी तरह से 16 आश्रमपद्धति के स्कूलों की व्यवस्था की गयी है जिससे गरीबों के बच्चों की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी । बजट में इतनी सारी बातों को लाया गया है लेकिन यह लोग इसको पुलिंदा कह रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं । मान्यवर, कन्याधन योजना के लिये सरकार ने 300 करोड़ रूपयों की व्यवस्था की है । मान्यवर, जब मुसलमानों के कल्याण की बात आती है तो भा0ज0पा0

के लोगों को न जाने कौन सी मिर्गी आ जाती है । मान्यवर, अब जो मुसलमानों के बच्चे मैरिट में आयेंगे उनको 1 हजार रूपये महीना दिया जायेगा । इसी तरह से उनको मुफ्त कम्प्यूटर देने की बात कही गयी है । ऐसा बजट इसके पहले कभी नहीं आया है । इसके पहले लूटने वाले लोग इस प्रदेश को चला रहे थे परन्तु हमारे माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने यह सारी योजनायें प्रदेश के लोगों को दी हैं और वह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं ।

गरीबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, यह जो बजट आया है यह जनप्रिय है लोकप्रिय है किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए है छात्रों के लिए है, मजदूरों के लिए है । यह सामाजिक है यह सबसे अच्छा बजट है मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

***श्री जगदम्बिका पाल-**

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया ।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

हुकुम सिंह जी, आप मेरे बाद बोल लें । मैं आपको सुनकर ही जाऊंगा । हमारे पूर्व प्रवक्ता श्री राम करन जी जो हमारे जनपद के हैं वह बजट के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहे थे । बजट व्यय प्रदेश का वार्षिक परिव्यय होता है जो प्रस्तावित योजनाएं होती हैं राज्य में जो प्राथमिकताएं सरकार की होती हैं उन प्राथमिकताओं को पूरा करने की बचनबद्धता बजट में रहती है । चाहे घोषणा पत्र हो या अन्य जगहों पर की गई घोषणाएं हों उनको पूरा बजट के माध्यम से ही किया जाता है । यह बजट जो क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए प्रस्तुत किया गया है । इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं मैं जिस मण्डल से चुनकर आता हूं बस्ती सिद्धार्थनगर, सन्त कबीर नगर में 14 सीटें हैं और इनमें से समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है । यहां समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही थी । सर्वाधिक सीटों की भागीदारी के कारण जो कहावत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसको हिस्सेदारी इस नाते इस मण्डल की अपेक्षाएं भी अधिक थीं । पूर्वांचल की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या की 40 प्रतिशत है । आज बुन्देलखण्ड को विकास के लिए 100 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है मैं धन्यवाद देता हूं आप कहीं भी विकास के लिए धन दें उसकी आलोचना करने का सवाल नहीं है । बुन्देलखण्ड को बुन्देलखण्ड निधि से हटकर 100 करोड़ रूपये दिए गए लेकिन हमारे पूर्वांचल की परिस्थितियां सबसे ज्यादा खराब हैं यहां पर बरसात में गोरखपुर सिद्धार्थनगर और देवरिया शहर तक में पानी भर जाता है गांवों की हालत की तो कल्पना नहीं की जा सकती है । पिछले तीन वर्षो से यहां सूखे की स्थिति है । किसानो की कैश क्राप गन्ना है लेकिन यहां की 11 चीनी मिलें बन्द हैं मुंडेरवा, खलीलाबाद, गौरीबाजार, भटनी आदि जगहों की चीनी मिलें बन्द हैं । लेकिन जिस बस्ती मण्डल में समाज वादी पार्टी की आंधी चली उसका इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है । आप प्रदेश में विकास की बात कर रहें हैं लेकिन जब तक ऋण जमा अनुपात नहीं बढ़ेगा तब तक किसी प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है । प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 34 प्रतिशत है उसमें पूर्वांचल का ऋण जमा अनुपात 27 प्रतिशत है । इसको बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है । हमारे यहां कलवारी टांडा पुल न होने के कारण जो लुम्बनी बुद्धीनगर मार्ग है जो छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्यप्रदेश तीन राज्यों को जोड़ता है लेकिन कलवारी टांडा पुल न होने के कारण इसमें 15-17

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, फैजाबाद, अकबरपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, श्रावस्ती आदि के लिये आवागमन का साधन नहीं है । अगर इस बजट में इसकी कोई व्यवस्था की गई होती तो मैं इनको साधुवाद देता । आज कलवारी टांडा पुल जिसकी आवश्यकता है पूरे पूर्वांचल में अगर उसके बारे में कहा गया होता तो हम धन्यवाद देते । आज पी0जी0आई0 का लाभ सैफई, इटावा मैनपुरी के लोगों को मिल रहा है तो यह अच्छी बात है । अगर राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ को सेटेलाइट से जोड़ा जा रहा है और 131 करोड़ रूपये की इसके लिये व्यवस्था की है । जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बलरामपुर अस्पताल और सिविल अस्पताल को मेडिकल कालेज स्तर का बनायेंगे, अच्छी बात है आप करिये लेकिन लखनऊ के सारे हास्पिटल मेडिकल कालेज स्तर के हो जायं, पश्चिम के सारे हास्पिटल मेडिकल कालेज स्तर के हो जायं लेकिन कौन सा दुर्भाग्य है कि पूर्वांचल के अस्पताल को सेटिलाइट से नहीं जोड़ा जा सकता ।

पूर्वांचल से आपकी पार्टी को मैनडेट मिला है । 500 बैड का जो यह अस्पताल पूर्वांचल में बना है जिसमें सी0टी0 स्कैन की बात हम करते हैं, डॉक्टर्स की बात हम करते हैं, फोर्थ क्लास की बात हम करते हैं । पूर्वांचल में चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं । हमने इससे पहले की सरकार से भी मांग की थी कि मुन्डरवा की बन्द पड़ी चीनी मिल को चलवायें उन्होंने कहा कि एक को ही नहीं चला सकते सबके बारे में निर्णय लिया जायेगा । मुझे खुशी है कि इस सरकार ने बन्द पड़ी चीनी मिलों मे से रामपुर की चीनी मिल को चलवाया । अगर जितनी बन्द पड़ी हुई चीनी मिलें हैं उनको आप चलावायेंगे तो हम इसके लिये आपको धन्यवाद देते । रामपुर की चीनी मिल चल रही है और पूर्वांचल की मुन्डरवा चीनी मिल बन्द है। जब माननीय मुलायम सिंह जी वहां गये थे उस समय भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी । किसानों पर गोलियां चली थीं और 3 किसान मारे गये थे । माननीय मुलायम सिंह जी ने जन सभा में कहा था कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी हम मुन्डरवा चीनी मिल को चलवायेंगे और किसानों को 120 रूपये गन्ना मूल्य देगें । मान्यवर, हम अपेक्षा करते हैं कि पूर्वांचल में किसानों के पास आय का इसके अतिरिक्त और कोई स्रोत नहीं है इसलिये इन चीनी मिलों को चलाने का उपाय किया जाय । पहले कहते थे कि यह बी0वाई0एफ0आर0 में चली गई है, जब फैसला होगा तो सबका होगा ।

मान्यवर, जब तक पूरे प्रदेश के सम्यक विकास की बात नहीं होगी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है । आज जो 14 प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि इन राज्यों की तुलना में हमारे यहां प्रति व्यक्ति आमदनी 14वें स्थान पर है । प्रदेश के विकास के लिये आप कोई पैमाना बनायेंगे कि नहीं ? प्रमुख 14 राज्यों की तुलना में हम प्रति व्यक्ति आमदनी में 14वें स्थान पर हैं, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोक्ता में हम 13वें स्थान पर हैं । आज प्रदेश की आमदनी निरन्तर घटती जा रही है । हमारे राज्य की आमदनी 1 करोड़ 76 लाख है जबकि देश की 19 करोड़ 56 लाख है । हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से विकास के रास्ते पर कहां जा रहे हैं । आज उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के अलग होने के बाद सबसे बड़ा कोई भी आय का साधन अगर हो सकता है तो वह पर्यटन का हो सकता है । आज पर्यटन की दिशा में इस बजट भाषण में कोई बात नहीं कही गयी है । हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के 53 पृष्ठ के बजट भाषण को देखा है । केवल दो पैराग्राफ इस संबंध में है । ताजमहल जो अन्तर्राष्ट्रीय धरोहर है उसके 350 साल पूरे होने पर ताज महोत्सव का भव्य आयोजन किया और वहां पर शिल्पग्राम में आग लग गई थी । बौद्ध सर्किट का इसमें कोई उल्लेख नहीं है । यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि गौतम बुद्ध की यहां जन्मस्थली है । (कुछ सदस्यों के बोलने पर व्यवधान) कोई परियोजना का उल्लेख यदि इस बजट भाषण में हो तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा ।

मान्यवर, जहां गौतम बुद्ध हुए हैं जो बुद्धिष्ठ स्थल हैं, कपिल बस्तु, लुम्बनी, श्रावस्ती में, थाईलैंड मलेशिया, मनाली फिलीपीन आदि जगहों से लोग यहां आते हैं थाईलैंड से वाइ एयर आने की व्यवस्था है । बौद्ध गया को विकसित किया जाना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां होना चाहिए । क्योंकि यहां पर थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपीन आदि जगहों से विदेशों से बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं वह यहां आते हैं तो यहां के लिए रेगूलर फ्लाइट शुरू होनी चाहिए । गौतम बुद्ध जहां पैदा हुए श्रावस्ती में, जहां उन्होंने 15 वसन्त देखें और जो बहराइच के पास कुशीनगर है, वह उनका निर्वाण स्थल है, तो श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिल वस्तु, लुम्बनी जो बुद्धिष्ठ स्थान वहां है उनको विकसित किया जाए । गोरखपुर की सड़क लुम्बनी नेपाल जाती है । लुम्बनी दुद्धी मार्ग है,सिद्धार्थनगर से बस्ती की तरफ आएं वहां ऐसी सड़क है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं । बार-बार हम कहते हैं सड़कों को प्राथमिकता देने के लिए । बुद्धिष्ठ मार्गों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित कर दिया जाए ।

मान्यवर, आज प्रदेश में गन्ना मूल्य की बात होती है गन्ना मूल्य की बात हम उठाते हैं 2002-2003 का अंतर मूल्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला है उसमें निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों के हक में फैसला करना होगा । जो डिफर मूल्य है 2002-2003 का उसको दिया जाना चाहिए । 2003-2004 का जो डिफर मूल्य बकाया है उसको लेकर आपके सामने संकट आता है हमारे सामने संकट आता है । हमारे किसान गन्ना मूल्य नहीं पाते हैं उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से किसानों को गन्ना मूल्य मांगने पर जो उनका हक होता है दुर्भाग्य से तीन बार गोलियां किसानों पर चलवाई गई । रामकोला, पडरौना में गोलियां चलवाई गई । दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी । दोनों बार निहत्थे किसानों पर गोलियां चलीं । तीसरी बार भाजपा बी0एस0पी0 की मिली जुली सरकार थी तीन बार किसानों पर गोलियां चली हैं ।

श्री डी0 प्रसाद अहिरवार-

मान्यवर, क्या पाल साहब अपने दल के नेता हैं । 15 मिनट हो रहे हैं इस सदन में बार-बार हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगें ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मैं अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल में कांग्रेस की सरकार ने गेंदा बाबू शोध संस्था की स्थापना कराई । जिसके बारे में कहा गया कि कोयम्बटूर से बड़ा सेन्टर है । गन्ने के लिए सबसे बड़ा रिसर्च सेन्टर होगा । आज गेंदा बाबू शोध संस्थान की दयनीय स्थिति है । इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं । मान्यवर, समय से बजट प्रस्तुत हो रहा है, इसके लिए मैं निश्चित तौर से सरकार को बधाई देता हूं लेकिन इस बजट को पारित कराने के बाद भी दो स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है ।

श्री अधिष्ठाता-

पाल जी, समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस बजट को पारित कराने के बाद भी दो स्वीकृतियों की आवश्यकता होगी । बजट समय से पारित हो रहा है, वित्तीय स्वीकृति और विभागीय स्वीकृति भी अप्रैल में अगर मिल जायेगी तो उसका ढ़ग से सदुपयोग होगा अन्यथा जैसा उल्लेख हुआ है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, मेरे पास भी बहुत से आंकड़े हैं । अगर समय से स्वीकृतियां जारी हो गई तो पैसे का सदुपयोग हो सकेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

***श्री हुकुम सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय नेता सदन ने जो बजट प्रस्तुत किया, शुरूआत यहीं से की थी कि अनुशासित एवं मर्यादित वित्तीय संस्कृति को विकसित करने का यह बजट है । जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मर्यादित और अनुशासति तभी कहा जायेगा जब इस विधायी स्वीकृति का भी कुछ ध्यान रखा जाए । जिस मद के लिए स्वीकृति हो, वह धन उसी मद में खर्च किया जाय । यदि स्वीकृति किसी काम के लिए होती है और खर्च कहीं और होता है तो वह बजट न मर्यादित न अनुशासित है । जहां के लिए स्वीकृति दी गई उससे न करके आकस्मिक निधि से पैसा लेकर खर्च किया गया । इसलिए यह न मर्यादित रहा और न अनुशासित रहा । इसलिए यदि इस विधान मण्डल की गरिमा रखनी है तो यहां से जो पास कराया जाए, उसको ध्यान में रखा जाए । इस सारे के सारे बजट में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया क्योंकि यहां की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ानी है और इसके लिए एक औद्योगिक विकास परिषद् का गठन कर दिया गया । उसको मीडिया के माध्यम से इतना हाईलाइट किया गया कि ऐसा लगता था कि प्रदेश में उद्योगों की बाढ़ आने वाली है । बैठकें होती रही, मण्डी परिषद् का एक कार्यालय है, बड़ा अच्छा है और जो विकास परिषद् के सदस्य हैं, उनकी गरिमा और मर्यादा के अनुरूप ही है । यह पूरे प्रदेश ने देखा । मैं पूछना चाहता हूं कि विकास परिषद् के गठन के बाद कौन उद्योग इस प्रदेश में आया । बम्बई से लोग वहां आए, एक भी प्रमुख उद्योग का नाम आप बता दें जो सवा साल में आया हो । कहा गया है कि मार्गो का निर्माण कराया जायेगा और उसके लिये प्राधिकरण गठित कर दिया गया। हमें मार्ग चाहिए, प्राधिकरण नहीं, उद्योग चाहिए, परिषद् नहीं । पी0डब्ल्यू0डी0 क्या करेगा ? आपके पास इतना बड़ा विभाग है, इतने बड़े कार्यालय हैं, आप उसका कोई उपयोग नहीं ले पाए, उसकी आवश्यकता नहीं रह पायी । इसलिए मैं चाहूंगा कि बजाय लुभावने नारे देने के, आकर्षक नारे देने के, धरातल पर कुछ करके देखें । एक बड़ी विडम्बना की स्थिति पैदा हो जाती है कि औद्योगिक विकास परिषद् के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ब्राजील गया। पूरा प्रदेश जानता है । कौन-कौन सदस्य थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं । उसमें कोई किसान, मजदूर नहीं था, कोई राजनेता भी नहीं था । अच्छा रहता के प्रदेश का कोई मंत्री चला जाता, एक नहीं गया ।

मान्यवर, एम0पी0 गये । मान्यवर, जरा चेहरा देख लें जो एम0पी0 गये हैं । ब्राजील गये, स्काटलैंड गये और स्काटलैंड से आने के बाद कहा कि स्काटलैंड के व्यापारी प्रदेश में स्काच का उत्पादन करने के लिए निवेश करेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि कहां चला गया श्री लोहिया जी की बात करने वालों, किसानों की बात करने वालों का चेहरा । दूध का उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे,अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे 1 यहां तो ठर्रा पीकर गुजारा कर रहे हैं क्यों उनको स्काच की आदत डालकर खराब करने जा रहे हो ।

---

*वक्ता ने [illegible] पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री किरन पाल सिंह-

उनका स्तर बढ़ा रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह-

जैसे लोग जायेंगे वैसा ही स्तर होगा । श्री किरन पाल जी जाते तो ऐसी बात करते, श्री वीरेन्द्र सिंह जी जाते तो ऐसी बात करते ।

श्री अधिष्ठाता-

पड़ोस का मामला है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जहां तक गन्ने की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि गन्ने का मूल्य 12 रूपये बढ़ा दिया और मेरी तरफ यह भी कहा कि आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हो । मेरे मन में वेदना हुई कि दो हजार रूपये चीनी का भाव है । कहीं तो किसान के गन्ने और चीनी के भाव में अनुपात रखते हैं । आज जब 2000 से 2200 रूपये प्रति कुन्तल चीनी का भाव है तो 12 रूपये बढ़ा दिया तो उसे उपलब्धि मान रहे हैं । पड़ोस में उत्तराचंल है । मुझे खुशी इस बात की है कि प्रथम पंक्ति में 4 बहुत ही आकर्षक चेहरे बैठे हुए हैं । जिनको इस बात की जानकारी है कि आखिर वहां पर चीनी मिल मालिक 135-140 रूपये प्रति कु0 गन्ना मूल्य दे सकते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिक 120-125 रूपये प्रति कु0 नहीं दे सकते । मुजफ्फरनगर के चीनी मिल मालिक किसानों को 120-125 रूपये प्रति कु0 गन्ना मूल्य देने को तैयार हैं । तीन दिन तक यह चला लेकिन तीन दिन बाद उनका गला दबाया गया, गुण्डा एक्ट में बंद करेंगे, मीसा में बंद करेंगे । इसके लिए बधाई दे आपको । पीड़ा की बात है । गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है । जो किसानों की बात करते हैं वह पैसे वाले किसान है । जानकारी आपको भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते । वहां पर आदमी शहरों में रिक्शा चला लेगा, मजदूरी कर लेगा । बिहार, नेपाल के मजदूरों से काम लेना पड़ता है । वहां पर अपराधी आते हैं, और अपराध करके चले जाते हैं वहां पर कई गन्ना किसानों की हत्या कर दी गयी । इसका कारण यह है कि आर्थिक विषमता पैदा हो गयी है । आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए । अगर प्रयास करते तो सोचते कि किसान की माली हालत क्या है । वहां पर लोकल मजदूर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं । कारण यह है कि उनको मनमाफिक रोजगार नहीं मिलता । बुन्देलखण्ड के लिए 100 करोड़ दे दिया, पूर्वांचल के लिए पैकेज दे दिया । पूर्वांचल में पूर्वांचल विकास निधि है । मुझे खुशी है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए यह विकास निधि होनी चाहिए । उसमें मुझे एतराज नहीं है और बढ़ा दीजिये, अच्छी बात है । लेकिन पश्चिम के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है । हम पूर्वांचल विकास निधि नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको दीजिये चाहे और बढ़ा दीजिये, बुन्देलखण्ड विकास निधि दीजिये लेकिन एक सरकार ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुछ दिया था और उससे सरकार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य शुरू हुआ था, मथुरा में पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय वहां पर खड़ा किया गया था, आज उसके लिए पांच करोड़ रूपये की सिर्फ बजट व्यवस्था की गयी है । आज उस महापुरूष के नाम से स्थापित विश्वविद्यालय को एक पैसा नहीं दिया गया है । वहां के भवनों का निर्माण अवरूद्ध हो गया है । आप इस बात के लिए प्रयास करो कि जो योजनाएं चलायी गयी हैं उनको पूरा करें,कोई भेदभाव न करें । अगर आप यह प्रयास नहीं करोगे तो जो वहां के लोगों की जो मांग खड़ी

है अलग प्रदेश की उसे आप रोक नहीं पाओगे । अंत में मैं प्राथमिकता की बात कहना चाहता हूं । प्राथमिकता क्या है । डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम से आप कोई यूनिवर्सिटी बना देते, कोई मेडिकल कालेज बना देते, कोई हास्पिटल बना देते तो खुशी की बात होती क्योंकि डा0 राम मनोहर लोहिया जी एक विचारक थे, एक अच्छे चिन्तक थे, एक दार्शनिक थे, उनको इस कैटेगरी में न लाते कि उनके नाम से सैकड़ों करोड़ों रूपयों का पार्क आप बना रहे हैं वह इससे थोड़े न खुश होंगे । हॉ अगर इससे नौजवानों के लिए आप कुछ सुविधा देते तो खुश होते ।

आज यह कम्पीटीशन क्यों चल रहा है कि एक ने किसी एक नाम से पार्क बनाकर करोड़ों रूपया खर्च किया और उसके जवाब में आपने करोड़ो रूपया दूसरे के नाम से पार्क बनाकर खर्च कर दिया । यह क्यों हो रहा है । अरे पार्क मत बनाओ । कुछ ऐसा करो जिससे प्रदेश के नौजवानों को सुविधा मिले और प्रदेश का विकास हो । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मर्यादा की बात करते हैं तो जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है क्या यह मर्यादित है । यह अमर्यादित है क्योंकि इसमें प्राथमिकता ही नहीं है। इसमें न तो किसानों का ध्यान रखा गया है, न अध्यापकों का नाम रखा गया है, न छात्रों का ध्यान रखा गया है । मान्यवर, शहीद विजय सिंह हुए हैं उनके नाम से महाविद्यालय बनाया गया है । लेकिन वहां बायो टेक्निक, माइक्रो टेक्निक, मिलेट्री साइंस का अध्यापक नहीं है । यह गर्वमेंट का है कोई प्राइवेट भी नहीं है । श्यामली महिला पालीलेक्निक की तरफ में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । वहां पर जो छात्राएं कम्प्यूटर साइंस पढ़ती हैं तो वहां पर उसको पढ़ाने के लिये कम्प्यूटर नहीं है, न वहां पर अध्यापक है । कानपुर से जो छात्रा पढ़ने जाती है उसको कितनी असुविधा होती है । छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है । वहां पर टाइपराइटर भी नहीं था, मैंने अपनी विधायक निधि से एक टाइपराइटर दिलाया । मैं चाहूंगा कि यह सरकार संवेदनशीलता का परिचय दे, विकास की दिशा में कोई कारगर कदम उठाये ताकि विकास हो सके । मुख्यमंत्री जी मेरठ गये थे । वहां पर यह विषय मैंने रखा था लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसको देखें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

बाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, यह जो बजट भाषण 2005-2006 का है यह लोकप्रिय बजट है,कल्याणकारी है और इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी तथा रोजगार को प्राथमिकता दी गयी है । वर्ष 2004-2005 के सापेक्ष में चालीस प्रतिशत अधिक इसमें व्यवस्था की गयी है । ग्रामीण क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहली बार जब वह मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक बजट देंगे, उसके अनुरूप इसमें 71.3 प्रतिशत का बजट का प्राविधान किया है । मान्यवर, ऐसे भी बजट आये हैं जब हॉ या ना दोनों में ही सिर्फ बोलने का मौका मिला है और हम सुन नहीं पाये और बजट एक दो मिनट में पास हो गया ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सन् 1990 में भी एक मिनट में पूरा बजट पास हो गया था ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय खन्ना जी, आपको भी समय मिलेगा तब आप अपनी बात रख लेना । अभी माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, पूर्व में देखा गया है कि जब कोई बजट पेश करना होता था तो आवाज उठती थी कि

मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे रहते हैं, इतना समय किसी मुख्य मंत्री ने नहीं दिया । मान्यवर, इस बजट में सभी वर्गो का ध्यान दिया गया है, मछुवा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 41 हजार के सापेक्ष अब 42 हजार मछुवा समितियों के सदस्यों के लिए बीमा योजना रखी गयी है । जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं । उनके लिए मछुवा आवास योजना के अन्तर्गत 2130 मछुवा आवास का प्राविधान किया गया है जिनको 25 हजार प्रति लाभार्थी की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी व्यवस्था की है । मान्यवर, 21 जनपदों में राष्ट्रीय समय विकास योजना के तहत काम शुरू हो गया है, इतनी तेजी से काम हो रहा है कि जो काम दस साल से अधूरे पड़े थे, वह अब पूरे किए जा रहे हैं और हर जिले में काम चालू हो गया है । इसके अलावा हम देखते हैं कुछ सदस्य बुन्देलखण्ड का नाम लेते हैं कि बुन्देलखण्ड को सौ करोड़ का पैकेज क्यों दिया गया है ।

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी चले गये, उनको शायद बुन्देलखण्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मान्यवर, गर्मी का सीजन आ रहा है,गर्मी के दिनों में दूर-दूर तक वहां पानी का नामोनिशान नहीं रहता है, वहां का वाटर लेबल बहुत नीचा हो जाता है और पानी की समस्या हो जाती है, इसलिए अविकसित क्षेत्र को विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौ करोड़ का पैकेज दिया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं चूंकि पहले देखा जाता था कि उत्तराचंल सबसे पिछड़ा अब हमारा बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा है । बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा नहीं रहना चाहिए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बुन्देलखण्ड को समुचित बजट दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज की योजना के तहत धन की जो व्यवस्था की गई है उसके तहत 551 करोड़ रूपये से अधिक की नकद धनराशि एवं 5.40 लाख टन से अधिक खाद्यान्न श्रमिकों को उपलब्ध कराया जायेगा, क्योंकि देखने में मिलता है कि हमारे प्रदेश के मजदूर काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, यह हो जायेगा तो उसे दूसरे प्रदेश में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चालू की है, यह बहुत ही कल्याणकारी है, इससे मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम होगा । मान्यवर, कन्या विद्याधन योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत कक्षा-12 उत्तीर्ण गरीब परिवारों की पात्र बालिकाओं को 20 हजार रूपये दिया गया है, इससे हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद मिल रहा है । मान्यवर, यह एक ऐतिहासिक योजना चालू की गयी है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और गत वर्ष इस योजना के लिए दो सौ करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया था और इस वर्ष तीन सौ करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है, इसके लिए । मान्यवर, सभी वर्गो के अर्ह छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 1466 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है । मान्यवर, हम लोगों ने स्कूलों में देखा है चार-पांच साल का बच्चा जब स्कूल जाता था और जब जुलाई में उसको किताबें मिलनी चाहिए थी तो किताबों के अभाव में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी वह अपने स्कूली मास्टर से रो-रोकर कहता था आखिर हमें किताबें एवं छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है । वह अपने घर में जाकर अपने माता-पिता से भी रो-रोकर कहता था कि हमको किताब एवं छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली, हम स्कूल नहीं जायेंगे ।

मान्यवर, उस हीन भावना को दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है । आज सरकार ने पिछड़े वर्ग के सभी छात्रों को तथा दूसरे गरीब वर्ग के छात्रों को किताबें देनें का काम किया है यह ऐतिहासिक काम है । माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिये दुआयें मिल रही हैं । आप देखें विपक्ष में बैठे सदस्य इस की चर्चा तक नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, माननीय मौर्य जी अभी

बोल रहे थे वह पिछड़े वर्ग की अगुवाई करते हैं उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की । जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति और किताबें देने का काम किया है ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त इस बजट में आप देखें आदर्श जनपद योजनान्तर्गत 13 जनपदों को 175 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है और जो जनपद भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ढ़ाई सौ करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है ।

मान्यवर, हम लोग देखते हैं कि नदी के किनारे जो लो झोपड़ियां बनाकर रहते हैं वह मछुआ समुदाय के लोग हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी और उनकी कई साल से मांग चली आ रही थी उनकी कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की । उनमें कुछ जातियों जैसे मझंवा, बेलदार आदि जो 4-5 जातियां है उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता था, मल्लाह, बिन्द, कश्यप, कहार-इनको उसकी सुविधा नहीं मिलती थी और उसकी उस मांग को किसी सरकार ने नहीं सुना लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके संबंध में आवश्यक प्रस्ताव पास कराके यहां की सर्वेक्षण रिपोर्ट को उसमें सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवा दिया है कि उनको अनुसूचित जाति में शामिल करवाया जाय । हम पूरे समाज के लोग उन्हें इसके लिए बधाई देते हैं ।

मान्यवर, यह जो 2005-2006 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही अच्छा है हम उसका समर्थन करते हैं । धन्यवाद ।

श्री रामहेत भारती-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के 2005-2006 के बजट अनुमानों पर आधारित बजट प्रस्तावों पर हो रही सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, कोई भी बजट प्रदेश का और देश का जो पेश किया जाता है वह बजट एक आईना होता है, वह प्रदेश के विकास की एक तस्वीर होती है । जिसमें नजर आता है कि बजट की प्राथमिकताएं क्या हैं और बजट की विशेषतायें क्या हैं । मान्यवर, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसके पेज तीन पर इस बात का उल्लेख किया गया है और इस में सरकार द्वारा कृषि, शिक्षा, सिंचाई, बिजली, सड़क, पानी तथा रोजगार के क्षेत्र की प्राथमिकता बतायी गयी है । माननीय अधिष्ठाता जी, यह कुछ ऐसे बिन्दु हैं जो प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इस बजट में जिनका उल्लेख किया गया है । मान्यवर, इस बजट में कृषि के बारे में सरकार बहुत चिंतित है। हमारे माननीय नेता जी और दल के नेताओं ने इस बात की ओर इंगित भी किया है कि आज कृषि और कृषि से जुड़े जो छोटे-छोटे उद्योग धन्धे है और जो हमारे सीमान्त और लघु कृषक हैं उनकी दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी है । मान्यवर, सरकार दावा करती है कि हम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलायेंगे और गन्ना किसानों को भी गन्ने का अधिकतम रेट दे करके बड़ा एहसान कर रहे हैं। मान्यवर, आज 112 रू0 प्रति कु0 गन्ने की कीमत देने की बात कही जाती है ।

मान्यवर, अगस्त 2003 के पहले का अगर हम देखें तो गन्ने का मूल्य 95 और 100 रूपये कुन्तल गन्ना किसानों को भुगतान किया जाता था और तब चीनी की कीमत 900 रूपये थी । मान्यवर, तब एक कुन्तल चीनी की कीमत 900 रूपये थी और आज 2000 रूपये कुन्तल चीनी का मूल्य है । आज गन्ना किसानों को जब अपने खेतों में यूरिया खाद डालनी होती है तो बाजार में यूरिया खाद नहीं मिलती, डीएपी नहीं मिलती, किसान मारा-मारा घूमता है,ब्लैक में खाद मिलती है, चोर बाजारी में खाद मिलती है, मंहगे दामों में खाद मिलती है और खाद जो मिलती है उसमें मिलावट होती है । खाद समय से नहीं मिल पाती, पानी समय से नहीं मिल पाता । नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की बात की

जाती है मेरे निर्वाचन क्षेत्र जनपद सीतापुर में कई ऐसी नहरे हैं जहां आप टेल तक पानी पहुंचना छोड़ दीजिए हेड तक पानी नहीं पहुंचा है । नहरों की सफाई नहीं होती है । सीतापुर ब्रांच में और खीरी ब्रांच में सफाई नहीं हुई है । किसानों को पानी नहीं मिल पाता कहां से कृषि का विकास हो पायेगा, आप टेल तक पानी पहुंचाने की बात करते हैं । इस बजट में स्वास्थ्य की बात कही गयी है कि हम प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य ठीक करेंगे ।

मान्यवर, मेरी निजी जानकारी में इस सदन में बड़े जोर से हल्ला मचाया जाता है कि एक रूपये का पर्चा कर दिया है लेकिन आज हालत क्या है, आज अस्पतालों से दवाएं गायब हैं जनपद सीतापुर के जिला चिकित्सालय मे रैबीज का इंजेक्शन नहीं है क्षय रोग की दवा नहीं है और आप कहते हैं कि हमने एक रूपये का पर्चा कर दिया है । जब दवा नहीं मिलती है तो एक रूपये के पर्चे से क्या होगा । रैबीज का इंजेक्शन और क्षय रोग की दवाएं नहीं मिलती है । इस बजट में कितना प्राविधान है स्वास्थ्य और दवाओं के उपलब्ध कराने के बारे में ? मान्यवर, बिजली पर बड़ी बहस हो चुकी है पूरे प्रदेश की जनता जानती है अभी तो सर्दियों का समय था अभी गर्मी आ रही है और जो बीत चुका है गर्मी का मौसम उससे शहरों और गांवों में हाहाकार मचा हुआ था । आपके ही जनपद लखीमपुर खीरी में पता नहीं कितनी तोड़फोड़ हुई, कितने धरना प्रदर्शन हो गये । पूरे प्रदेश के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है । आपने कहा कि 16 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि 4-5 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है, गांव में बिजली नहीं मिल रही है और आज आप कहते हैं कि एक उद्योगपति को लेकर उत्तर प्रदेश में पावरहाउस लगाने जा रहे हैं । मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जनपद सीतापुर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र इमलिया सुल्तानपुर में विद्युत उपकेन्द्र बनाना प्रस्तावित था लेकिन उसके लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है । हम पूरे प्रदेश के विकास का पैसा कहां ले जा रहे हैं आपने बजट में कह दिया कि पूरे प्रदेश की जनता का पैसा कहां ले जा रहे हैं । यह सब इस पुस्तिका में उल्लिखित है । मान्यवर, यह आपके बजट भाषण में है कि हम सड़कों को प्राथमिकता देगें । आज कैसी सड़के हैं आप ही देख लीजिए लखनऊ से सीतापुर के लिए जाते होंगे तो जो रोड़ है उस पर चलना मुश्किल हो गया है ।

लखनऊ से जब आप चलते होंगे, लखीमपुर के लिये तो देखते होंगें कि गांवों की दशा क्या है । माननीय अधिष्ठाता जी, अगस्त 2003 से पहले, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजपार्टी की नेता बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो पूरे प्रदेश में अम्बेडकर गांवों के माध्यम से सड़कों को डामरीकरण कराने का काम किया गया, लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देने का काम किया गया, आज उस योजना का नाम समग्र ग्राम विकास योजना रख दिया गया, लेकिन इस योजना में से बिजली का प्राविधान खत्म कर दिया गया, बिजली का बिन्दु गायब कर दिया तो इस तरह से गांव का विकास होने वाला नहीं है । पानी के लिये अभी इन्डिया मार्का हैण्डपम्प की बात हो रही थी, आप सब जानते हैं कि वाटर लेविल पूरे प्रदेश में कहां जा रहा है । पूरे प्रदेश में इन्डिया मार्का हैण्डपम्प देने की घोषणा की गयी थी, लेकिन आज तक उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पाई है । मान्यवर, इसी प्रकार रोजगार की बात कही गयी ।

इस बजट में तमाम सारी चीजें हैं, उसमें कुछ किन्हीं स्थानों के लिये हैं और कुछ जिलों के लिये हैं । यह तो ठीक बात है कि आप इसकी व्यवस्था करिये लेकिन मान्यवर, यह प्रदेश 70 जिलों में है । इस प्रदेश के अन्दर 70 जनपद हैं । इन 70 जिलों में तमाम गरीब लोग रहते हैं, उनके लिये क्या व्यवस्था की गयी ? उनके लिये कौन से रोजगार सृजन की बात कही गयी है ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 80 प्रतिशत गरीब लोग हैं, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, कैसे उनका विकास

होगा, कैसे उनके बच्चे तरक्की करेंगे, इस बात का इस बजट में कहीं कोई प्राविधान नहीं है । इस बजट में रिक्शा चालकों के लिये रिक्शा मालिक बनाने की बात कही गयी है । लेकिन कौन से रिक्शे का रिक्शा मालिक आप बनाने जा रहे हैं ? आपने पूरे समाज को विकलांग समझ लिया या फिर आप कौन सा रिक्शा देने का काम कर रहे हो ?

मान्यवर, मुसलमान समाज के लिये, उन्हें रोजगार करने के लिये अलसंख्यक कल्याण विभाग उन्हें धन मुहैया कराता था, उसकी व्यवस्था भी आपने खत्म कर दी तो उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठेगा ? इसी तरह अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये, उनके समाज की बेहतरी के लिये कोई प्राविधान इस बजट में नहीं है । यह वर्ग ही इस समाज में सबसे गरीब और कमजोर है ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री रामहेत भारती-

मान्यवर, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिये कोई व्यवस्था की जानी चाहिये, उनको पैसा उपलब्ध कराया जाना चाहिये लेकिन इस बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है । अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट योजना के द्वारा व्यवसायिक क्षेत्रों में वित्त विकास निगम के द्वारा दुकानें बनवाकर आवंटित की जाती थी, इस बजट में उसका भी कही प्राविधान नहीं है। इस वित्त विकास निगम द्वारा जमीनें खरीदकर गरीब भूमिहीन लोगों को दी जाती थी, इसका भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, मैं कई बार कह चुका हूं, दूसरे लोगों को भी बोलना है ।

श्री रामहेत भारती-

मान्यवर, यह बजट कर-विहीन बजट बताया गया है । माननीय अधिष्ठाता जी, इस समय मैं तुलना कर रहा हूं । अगस्त, 2003 से पहले और अब की । इस बजट में हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कर्ज में जा रहा है । अगस्त, 2003 में सीमेंट की बोरी 115 रूपये की थी । इस समय 175 रूपये की बिक रही हैं । अगर कर नहीं बढ़ाया है, टैक्स नहीं बढ़ाया है, तो यह क्या है? 2003 में 115 रूपये की सीमेन्ट की बोरी थी, आज 175 रूपये की हो गई है, सरिया 1600 और 1800 रूपये प्रति क्विंटल थी, आज 2800 और 2900 रूपये प्रति क्विंटल हो गई है, ईंटा जो 14 सौ रूपये प्रति हजार था आज इस समय 22 सौ रूपये प्रति हजार हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप कृपया बैठ जाएं,कुछ लिखा नहीं जाएगा ।

(सदस्य श्री राम हेत भारती के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप कृपया बैठ जाएं।

कृषि एवं धमार्थ कार्यमंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार द्वारा इस प्रदेश में लोकहितकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, पिछले 28 वर्षो से मुझे इस सदन की सेवा करने का अवसर मिल रहा है । कई बार विभिन्न सरकारों ने अपने बजट को प्रस्तुत किया, उन बजटों को मैंने देखा, लेकिन पहली बार ऐसा बजट जो कि ऐसे समय में प्रस्तुत हुआ है, जिससे जो एक वित्तीय अनुशासन और वित्तीय संस्कृति समाप्त हो गई थी, वह फिर से कायम होगी । फरवरी माह में बजट प्रस्तुत हो गया और मार्च के महीने में यह बजट समय से पारित हो जाएगा और सभी विभागों को आवश्यक धन समय से प्राप्त हो जाएगा । पिछले वर्षो में जब मई, जून और जुलाई में बजट पास होता था, तो स्वीकृतियां विलम्ब से जाती थीं और काम के मामले में लीपापोती हुआ करती थी । पिछली बार भी और इस बार भी बजट समय से प्रस्तुत हुआ, जिसके कारण 96 प्रतिशत पिछले वर्ष की बजट स्वीकृतियां रिलीज हो गई । यही स्थिति इस वर्ष की भी रहेगी । माननीय हुकुम सिंह जी जब बजट पर बोल रहे थे, मैं नहीं समझता कि हुकुम सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति बजट को न समझ पाये हों । पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें समाज के हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, जिसके हितों का ध्यान न रखा गया हो । मजदूर, किसान, कृषि, कर्मचारी, शिक्षक और महिला, हर वर्ग के हितों को साधने का काम किया गया है । सभी वर्ग के उन्नयन के लिए योजनाएं समायोजित की गई हैं । ग्रामीण क्षेत्र, जो कि हमारी प्राथमिकता है, इस वार्षिक बजट में 71 प्रतिशत से अधिक हमने खर्च करने का निर्णय लिया है ।

मान्यवर, महिलाओं के विकास की बात हमेशा करते रहने वाले लोग हमारे सामने बैठे हैं लेकिन कभी कुछ नहीं किया गया । पहली बार जेण्डर बजटिंग में यह व्यवस्था की गयी है कि कुल बजट का 33 प्रतिशत धन महिलाओं के विकास वाली योजनाओं पर खर्च किया जायेगा । महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा योजनायें बनायी जायेंगी । महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम को पूरा बल देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने की हमारी सरकार की मंशा है जिससे महिलायें स्वावलम्बी हों और सम्मान के साथ जी सकें तथा महिलाओं को अन्याय और उत्पीड़न से बचाया जा सके । इसी तरह से शिक्षा हमारी प्राथमिकता रही है । प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम हमारी सरकार ने किया है । इसके बाद भी आने वाले दिनों में शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, चाहे शिक्षा मित्र के रूप में ही, विषय विशेषज्ञ के रूप में हो या विशिष्ट बी0टी0सी0 के रूप में हो । तमाम बी0एड0 और एल0टी0 किये हुये नवयुवकों का विश्वास समाप्त हो गया था कि उनको भी कभी नौकरी मिलेगी । लेकिन हमारी सरकार ने उनको नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया है । शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है, चाहे उच्च शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा हो या बेसिक शिक्षा हो । नये विद्यालयों की स्थापना हमने की है, जर्जर भवनों का पुर्ननिर्माण तथा नये विद्यालयों की स्थापना की है । मित्रों, शिक्षा हमारी प्राथमिकता है ।

स्वास्थ्य के ऊपर भी हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है । 1600 करोड़ रूपये हमने केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया है । इसके पीछे उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सालय है, वहां दवायें उपलब्ध हों और लोगों का सही इलाज हो सके, जो बड़े अस्पताल है वहां पर विशिष्ट स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हैं । अभी तक ऐसा अस्पताल केवल एक पी0जी0आई0 था । अब हम तीन और केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं जो पी0जी0आई0 के सैटेलाइट संस्थानों के रूप में विकसित किया जायेगा। मान्यवर, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आवागमन हो । आवागमन के मामले में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सामने जो मित्रगण बैठे हुये हैं, उन्होंने गड्डा मुक्त सड़कों का नारा दिया था । जो जर्जर हालत सड़कों की रही है वह किसी से छिपी नहीं है । हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 500

की आबादी को पक्की सड़कों से जोड़ेगें । यह केवल औपचारिकता नहीं होगी । हमने अच्छी सड़कें बनाने के लिए सड़क प्राधिकरण गठित करने का काम किया है जिसके माध्यम से उत्कृष्ठ कोटि की सड़कें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बनायेंगे जिससे प्रदेश के नागरिकों को आवागमन की कठिनाई न हो। हम आवागमन की कठिनाई से आम जनता को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे । नहरों की सिंचन क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम है, जिसमें हम टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे । 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और जब तक बिजली के मामले में स्वावलम्बी नहीं हो जाते हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दो साल के बाद नये संयंत्र चालू हो जायेंगे जिससे हम 24 घंटे बिजली दे सकेंगे । यह हमारी सरकार की किसानों और गांवों के प्रति सोच है ।

जहां तक किसानों का सवाल है प्रतिपक्ष को यह बात अच्छी नहीं लगी कि सरकार ने गन्ना मूल्य एक साथ 12 रूपये प्रति क्विंटल क्यों बढ़ा दिया? खेती-किसानी से आप लोगों का रिश्ता नहीं है । केवल घड़ियाली आंसू बहाने से इसे छिपाया नहीं जा सकता । जब-जब हमारी सरकार बनी है, जो भी पैदावार हो, हमने मूल्य बढ़ाने का काम किया है । 1989 में भी गन्ना किसानों का दाम बढ़ाया है, 1993-1994 में भी बढ़ाया है और तीसरी बार सरकार बनी है तो हमने एक साथ 12 रूपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किया है । हमने प्रदेश की 104 चीनी मिलों को पूरी क्षमता से चलवाकर पेराई कराया है । फरवरी तक जो पेराई लक्ष्य था उससे 60 लाख मीट्रिक टन ज्यादा पेराई करके किसानों का अधिक से अधिक गन्ने की खपत कराने का काम हमारी सरकार ने किया है । हम जानते हैं कि प्रदेश में चीनी उद्योग की बहुत भारी सम्भावनायें हैं । किसान गन्ने का उपयोग कैश क्राप के रूप में करता रहा है । प्रदेश में चीनी उद्योग की सम्भावनाओं को देखते हुये नई चीनी उद्योग नीति बनायी है और सरकार ने उदारतापूर्वक नीति में तमाम सुविधायें दी हैं । निजी क्षेत्र में जो उद्यमी आयेंगे सरकार उनको संरक्षण देगी और उन्हें बढ़ावा देने का काम करेगी ताकि हमारे यहां उद्योगों की सम्भावनायें बढ़े और किसानों को उनके गन्ने की अच्छी कीमत मिल सके । प्रतिस्पर्धा होगी तो किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा । इसी तरह से गेंहू के बारे में 630 रूपये सरकारी मूल्य था लेकिन किसी जगह पर 630 रूपये से कम पर गेहूं बिकने नहीं दिया गया । किसानों ने जहां चाहा अपना गेहूं बेचा उसको गेहूं की पूरी कीमत मिली । इसी तरह से धान की कीमत किसान को सरकारी मूल्य के बराबर बाजार में मिली और उसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं रही ।

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, कृषि विविधीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक से एक हजार करोड़ रूपये स्वीकृति कराने का लक्ष्य है ताकि प्रदेश में जो परम्परागत तरीके से किसान खेती करते हैं उस खेती में आधुनिकता को बढ़ावा मिले और आधुनिक तरीके से खेती करें । हमारी जो अनु-उपजाऊ भूमि है, जैसे ऊसर, बन्जर इसको उपजाऊ बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है । असिंचित जमीन को सिंचित बनाया जा रहा है । इस बार बीस हजार हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया है । मान्यवर, इसी तरह से जलागम वाली जो जमीन है, वहां से पानी निकालने की व्यवस्था करके जमीन को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके । माननीय हुकुम सिंह जी को उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की बड़ी चिन्ता है । वह यह कहते हैं कि इसका गठन क्यों किया गया है । उत्तर प्रदेश में 5-6 साल तक आपकी सरकार रही है और उसके पहले आपके सहयोगियों की सरकार रही है । लेकिन एक भी उद्योग इस प्रदेश में नहीं आया जिसकी लागत एक हजार करोड़ रूपये की हो । पिछली बार जब उच्च न्यायालय के आदेश से दिल्ली से उद्योग हटाये गये तो यह विश्वास जगा था कि दिल्ली से हटाये गये उद्योग गाजियाबाद और नोयडा में आयेंगे लेकिन

दिल्ली का एक भी उद्यमी अपने उद्योग को उत्तर प्रदेश में नहीं लाया जिसका नतीजा यह हुआ कि औद्योगिक विकास की दर लगभग शून्य पर पहुंच गई है और विकास ठप्प हो गया है ।

पिछली सरकारों ने औद्योगिक वातावरण नहीं बनाया जिससे उद्यमियों ने उद्योग यहां नहीं लगाया आज आप यह कहते हैं कि औद्योगिक विकास परिषद् के लोगों ने विदेश में जा कर क्या किया । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार जब थी तो मंत्री, अधिकारी जब विदेश जाते थे तो आपने क्यों ऐसी सुविधायें नहीं दी जिससे बाहर के उद्यमी यहां आकर उद्योग लगा सकें । आपके जमाने में एक भी एम0ओ0यू0 साइन नहीं किया गया और न किसी बाहरी उद्यमी ने यहाँ कोई औद्योगिक निवेश किया । हमने औद्योगिक विकास परिषद् बनाई जिससे प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ी । 13 हजार करोड़ रूपये की लागत से चार हजार मेगावाट का बिजली घर लगाया जा रहा है जिससे बिजली का उत्पादन होगा हमारे माननीय नेता सदन के प्रयास करने पर कुमार मंगलम बिड़ला एक हजार मेगावाट क्षमता का बिजली घर लगा रहे हैं और आनपरा-सी के लिए बातचीत चल रही है । हमारे प्रदेश में यदि बिजली का उत्पादन होगा तो हमारा प्रदेश विद्युत के मामले में स्वावलम्बी होगा और प्रदेश के विकास की गति तेज होगी ।

मान्यवर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति हमारी सरकार द्वारा घोषित की गयी है इससे खाद्यान्नों का प्रसंस्करण होगा और खाद्यान्नों को परिरक्षित किया जा सकेगा । खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग नीति से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगेंगे इससे किसानों के उत्पादन का उपयोग होगा और उनको सुविधा मिलेगी। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार योजना लागू की गयी है । हमारे सामने के साथी कह रहे थे कि इस योजना के लिये क्या किया गया है । यह जो पुस्तिका छपी है उसमें इसके बारे में दिया गया। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि इसके लिये 440 करोड़ रूपये का बजट में प्राविधान किया गया है ।

इसके माध्यम से 551 करोड़ रूपये का भौतिक लक्ष्य रखा गया है । स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्व रोजगार योजना के माध्यम से 2.75 लाख मानव दिवस सृजित करने का निर्णय लिया गया है । इसी तरह से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की दस्तकारी, कारीगरों व इन सबके माध्यम से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया है । मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना पहली बार प्रदेश में प्रारम्भ की गई है । इस योजना के माध्यम से पांच हजार औद्योगिक इकाइयां लगाने का लक्ष्य है जिसमें 35 हजार लागों के लिए रोजगार का सृजन होगा । इसी तरह से मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत 3000 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जायेगी जिसमें 25,000 रोजगार सृजित होंगे । इसी तरह से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 17 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है जिसमें 440 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है । इसी तरह से दुग्ध विकास की योजना के अन्तर्गत 39,000 लोगों को दुग्ध पालन की ओर जोड़कर इनको रोजगार देने जा रहे हैं । इससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों की आय भी बढ़ेगी । इसी तरह से लघु औद्योगिक इकाइयों के स्थापना का लक्ष्य बढ़ाकर 30,000 किया गया है इससे 77,359 लोगों को रोजगार मुहैया होगा । इसी तरह से प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत हमने स्वरोजगार हेतु 52,000 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष माह नवम्बर 2004 तक 49000 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है वर्ष 2005-2006 में भी 52 हजार का लक्ष्य है ।

इसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि वह तीन लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियों में लोगों की भर्ती की जा रही है जबकि इसके पूर्व की जो सरकारें रही है उन्होंने कभी विश्व बैंक के दवाब में कभी अन्य कारणों से प्रतिबन्ध लगा रखा था । हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि हर हाथ को काम मिले और कोई भी आदमी खाली न रहे । इसीलिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम

से लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम किया है । इसी तरह से विकलांगों की दशा सुधारने के प्रति हमारी सरकार गम्भीर है और उनके पुर्नवास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है । अल्पसंख्यकों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल वर्षों किया गया लेकिन सही मायने में अगर उनका किसी ने कल्याण किया है तो वर्तमान सरकार ने किया है और सरकार ने केवल चिन्तन ही नहीं किया बल्कि उसे कार्य रूप में परिणित किया है । हमने उनकी भाषा को सम्मान देने का काम किया और उसे रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया है और उनके भविष्य को संवारने का काम किया है । मौलाना अली जौहर जिनका देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था जहां वह कैद रहे उसको धरोहर स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया है व उनकी स्मृति में छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई । हमारी सरकार ने पांच हजार रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने का काम किया । समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जो किसी से छिपी नहीं है । व्यापारियों को अभी तक केवल मतदाता समझा गया उसको वोट बैंक मानकर उसका दोहन किया गया लेकिन उनके बारे में कोई कार्य नहीं किया गया पहली बार हमारी सरकार ने व्यापारियों के सम्मान के लिये कार्य किया और उनको अपना व्यापार सम्मान के साथ चलाने का अवसर दिया । अधिवक्ताओं के हित के लिए जो पहले से खुली जगहों पर बैठते थे जब पानी बरसता था तो उनकी फाइलें तक भीग जाती थी सरकार ने उनके लिए डेढ़ करोड़ में शेड बनाने का कम किया ताकि वहां वह अपने क्लाइंट के साथ आराम से बात कर सकें । इसके अलावा उनके लिए बार काउंसिल भवन निर्माण के लिए 30 करोड़ रूपये सरकार ने दिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कृषि मंत्री बजट पर बोल रहे हैं यह केवल इतना बता दें कि इस बजट में किसानों को अच्छे बीज, उर्वरक आदि देने का कोई प्राविधान किया गया है कि नहीं ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, अगर कहें तो वह भी बताऊं । वैसे तो कृषि के लिये अलग से बजट आयेगा । श्रीमन्, पहली बार योजना आयोग से साढ़े तेरह हजार करोड़ की स्वीकृति मिली है जो कि अपने आप में इस सरकार की उपलब्धि है । श्रीमन् हमने विकास की एक रूप-रेखा बनाकर अपने संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया है । हमने कोई नया कर नहीं लगाया है । हमारी सरकार ने फिजूलखर्ची को राकने का निर्णय लिया है । जो अनावश्यक रूप से व्यय होता था उनको रोककर प्रदेश के एक एक पैसे को संचित करके विकास में लगाने का निर्णय लिया है । वर्ष 2005-2006 में कुल व्यय 69295.19 करोड़ रूपये निर्धारित किया है जो अपने में एक मिसाल है । इस वर्ष 14864.36 करोड़ रूपये आयोजनागत व्यय अनुमानित है । यह तब ही सम्भव हो सका है जब हमने अपने संसाधन को बढ़ाया है और फिजूलखर्ची को रोका है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपके लिये 15 मिनट का समय निर्धारित था । लेकिन आपका समय ज्यादा हो गया है ।

डॉ अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, जैसी आज्ञा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, अभी तक जो माननीय सदस्य बोले हैं उसमें सत्ता पक्ष से 4 और बहुजन समाज पार्टी से 2 सदस्य बोल चुके हैं । भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भी मौका मिले ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय मंत्री जी पेट पर हाथ रखकर बोले हैं, दिल पर हाथ रखकर नहीं बोले हैं इसलिये इनको तो इसका गुण-गान करना ही था ।

***श्री राम इकबाल सिंह-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2005-2006 के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह 674.17 करोड़ रूपये के घाटे का बजट पेश हुआ है । श्रीमन् सरकार ने कर्जे को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की है । वर्ष 2004-2005 में 1,15,25,669 रूपये कर्जा था जो कि अब वर्ष 2005-2006 में 1,29,15,491 रूपये हो जायेगा । मान्यवर, पूरे बजट में ऋण को समायोजित करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश में हर आने वाले बच्चे पर हम कर्ज का बोझ थोप रहे हैं । जैसी घोषणा इन्होंने बजट में की है उसका मूर्त रूप जनता में जाना चाहिए । पिछले साल भी कई गांव समग्र विकास में प्राथमिकता पर लिये गये थे । एक एक लाख रूपया विधायकों को उनके द्वारा चयनित 10 गांवों के लिये दिया गया था लेकिन कहीं कोई सम्पर्क मार्ग नहीं बना है । एक मीटर कहीं सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है । हो सकता है किसी जिले में हुआ हो लेकिन हमारे क्षेत्र में एक मीटर सड़क का निर्माण वर्ष 2004-2005 में समग्र विकास गांव के तहत नहीं हुआ । बजट में आश्वासन दिया गया था कि डा0 राम मनोहर लोहिया सम्पर्क मार्ग का भी निर्माण किया जायेगा लेकिन वह भी कहीं देखने को नहीं मिला । इसलिये मान्यवर, बजट बनाना महत्वपूर्ण नहीं है ।

समाजवादी हम लोग विश्वविद्यालय में साथ पढ़े हैं वहां भी भाषण के समय सांड भैंसा इकट्ठा हो जाते थे लेकिन योजना का मूर्त रूप सामने आने में बड़ी चुनौती होती है । इसलिये जो यहां बजट पेश किया गया है जो बजट पहली बार की तरह से आवंटित है ।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी के कुछ कहने पर)

आपसे बाद में बात होगी आपको सितार बजाने के बहुत अवसर मिल जायेंगे । मान्यवर, कन्या विद्या धन एक स्वागत योग्य कदम हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली बालिकायें हैं यह उनके लिए है । लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2004-2005 में किसी बेटी को कन्या धन मिला हो यह हमारे संज्ञान में नहीं है । अखबार में पढ़ने के लिए मिलता है कि इस बार 300 करोड़ रूपये का प्राविधान कन्या विद्या धन योजना के लिए किया गया है जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली बेटी हैं जो इण्टरमीडिएट पास होंगी । उनको 20 हजार रूपया देने की व्यवस्था की जायेगी । मान्यवर, हमारा सरकार से अनुरोध है कि कथनी और करनी में अन्तर न करें । रोजगार सृजन के लिए पूरा धन दे दिया गया है लेकिन यह घुमाफिराकर किस तरह से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए किया गया है ? हिन्दुस्तान में जिस तस्वीर के नीचे हम आप सब बैठे हैं जिसने जंगे-आजादी से हिन्दुस्तान की आबादी को आजाद कराया ।

(कुछ सदस्य बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अच्छी चीजों को ग्राह्य करें । जिस महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही, आम आदमी का राज्य होगा जिसके समर्थन में लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हर हाथ को काम मिलेगा । मान्यवर, किसानों की 82 प्रतिशत आबादी है । शहरों की 18 परसेन्ट आबादी है उसमें भी गांवों के 10 प्रतिशत लोग हैं । सेना का सिपाही हो चाहे पुलिस का सिपाही हो और चाहे होमगार्ड हो अगर पैसा होगा तो वह गोमतीनगर में ही प्लाट खरीदता है । गांव से लोग पलायन कर रहे हैं । 100 प्रतिशत पलायन हो रहा है । पलायन करके लोग शहरों में रोजगार के लिए आते हैं । जो 10 रूपया भी कमा रहा है वह गांव नहीं जाना चाहता है । जिन्दगी भर शहर में रहकर उजाले में भोजन करना चाहता है तो उसको अपने बीबी का चेहरा दिखाई नहीं देता है उजाले के बिना चेहरा दिखाई नहीं देता है और रिजवी साहब सोलर लाइट लगाए हैं ताकि व्यवस्था ठीक रहे । हम किसानों से बार-बार कह रहे हैं आप भी,मान्यवर, गांव से चुनकर आए हैं गांव में पैदा हुए होंगे । हम भी गांव में पैदा हुए हैं श्रीमन गांव को चमकाने के लिए लाइटें जलती है लेकिन गांव में बिजली नहीं मिलती है हमारे लड़के शाम को नहीं पढ़ते हैं वह गम मिटाने के लिए नशा करते है । गुटखा खाते हैं । उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष एक लाख हजार लोग कैंसर के रोग से मर रहे हैं गुटखा से यह रोग हो रहा है । शहरों में लोग टी0बी0 देखने में जुटे रहते हैं देहात में लोग टी0बी0 नहीं देख पाते हैं समाचार नहीं देख पाते हैं। मान्यवर, रोज उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का कीर्तन हो रहा है एक जिक्र हो रहा था उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की अध्यक्षता में ब्राजील में एक डेलीगेशन गया था । इसमें हिन्दुस्तान के जाने-माने किसान गये थे, जया प्रदा गयी थी, जया बच्चन जी गई थी । अध्यक्ष जी, आप पुराने समाजवादी रहे हैं, क्षमा करियेगा, समाजवाद की जो आवाज रहती थी, उसे पूरी तरह पूंजीवाद में कन्वर्ट कर दिया । मान्यवर, यह जो चीन की झालरें आ गई हैं जो मोम बत्तियां आ गई हैं, क्या होगा कुम्हार के दिये का? आप डब्ल्यू0टी0ओ0 के सामने नतमस्तक हो गए ।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)-

केन्द्र की आपकी सरकार थी, बदलाव कर देते ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, नरसिंह राव की सरकार थी, वह हिन्दुस्तान के किसानों का, मजदूरों का हाथ काटकर डब्ल्यू0टी0ओ0 के सामने नतमस्तक हो गए । आज निवेश का कल्चर खड़ा किया गया है, शिक्षा का बाजीकरण कर दिया गया है । हम शिक्षा के विरोधी नहीं है, आप इंजीनियरिंग कालेज खोलिए, आप आई0ए0एस0 के कोचिंग सेण्टर चलाने जा रहे हैं । क्या बिगाड़ा है उन गांवों के रहने वालों ने,क्या बिगाड़ा है गांव के रहने वाले गरीब बच्चों ने, क्या उनके पूर्वजों ने जंगे-आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी ?

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो गया है, समाप्त करें ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, हमारे पुराण, उपनिषद्,गीता ये सब संस्कृत भाषा में हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आज संस्कृत के साथ क्या हो रहा है । संस्कृत के अध्यापकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां भी नहीं दी गयी हैं । हम चाहते हैं कि मदरसों का भी कम्प्यूटीकरण हो । हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के

सारे प्राथमिक से लेकर इण्टरमीडिएट तक के सारे विद्यालयों का कम्प्यूटरीकरण हो जाना चाहिए क्योंकि आज रोजगार कम्प्यूटर पर गया है । मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों में भोजन के समय दाल की जगह लोबिया, खिचड़ी में मिलाई गई । यह घास होती है ।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें ।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, 2 मिनट और । गांवों में खाद्यान्न योजना दी गई है । पूरा खाद्यान्न बंगलादेश और नेपाल जा रहा है, उसकी सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए ।

मान्यवर, अब मैं थोड़ी क्षेत्रीय समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे पूरे जनपद मे जो स्टेट हाईवे एथारिटी है, बलिया से लेकर सुनौली मार्ग तक सड़क गड्ढों में बदल गई है । मेरे क्षेत्र में जो अन्य टूटी सड़कें हैं, वह बननी चाहिए । वर्ष 2002-2003 का पूर्वांचल विकास निधि का अवशेष नहीं गया है, उन सड़को का बनना चाहिए और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 500 करोड़ का स्पेशल बजट देना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट, जनहितकारी बजट है । इसमें सभी लोगों का ध्यान दिया गया है चाहे वह किसान हों, मजदूर हों, बुनकर हों, उद्यमी हों, या व्यापारी हों । लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि 674.17 करोड़ के घाटे का बजट मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। वर्ष 2005-2006 के बजट को उपयुक्त कहा जा सकता है लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश की ऋण-ग्रस्तता में कोई कमी नहीं आई है । परन्तु जहां इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 116 हजार करोड़ का घाटा है, वहीं वर्ष के अन्त में जाकर 129 हजार करोड़ हो जाएगा ।

मान्यवर, प्रदेश में कर्ज बढ़ रहा है उससे उबरने के लिए कोई उपाय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है । पिछले साल 4.4 प्रतिशत था अब वही इस साल के अन्त तक 5.3 प्रतिशत पर आ जायेगा । केन्द्र सरकार व केन्द्रीय योजना आयोग का आभारी होना चाहिए कि प्रदेश सरकार द्वारा 11 हजार करोड़ रूपये की मांग करने के बावजूद भी 13 हजार 500 करोड़ रूपये का परिव्यय दिया गया । जो जी0डी0पी0 रेशियों 44.5 प्रतिशत था वह वर्ष 2005-2006 में बढ़कर 54.6 प्रतिशत हो जायेगा । महिलाओं के उत्थान के बारे में सरकार ने सोचा है । जो जेंडर स्कीम लागू की है वह पहली बार है । महिलाओं के बारे में जो बातें की जा रही है उसमें पेंशन की धनराशि सवा सौ से बढ़ाकर रू0 150 कर दी है । इसके अलावा यहां हम जो कुछ विधान सभा में कहते हैं जब जिला स्तर पर आ जाते हैं तो वह चीज नजर नहीं आती । आज भी तमाम विधवायें भटक रही हैं विधवा पेंशन का बजट बढ़ाया जाय । प्रदेश में जिला प्लान की बैठक होती है,योजनायें भी बनती है लेकिन यहां भारी कटौती कर दी जाती है ।

योजना विभाग में बड़ी गड़बड़ी है । जैसे पर्यटन विभाग ने रू0 4 करोड़ 31 लाख का बजट भेजा गया, दान दक्षिणा नहीं मिली तो उसे लटका दिया तथा वित्त विभाग में देर से भेजा गया जिससे अनुपूरक

बजट या मुख्य बजट में आने से रह गया । मथुरा की एक सड़क योजना का प्रस्ताव 1 करोड़ 40 लाख का भेजा था, दान दक्षिणा न चढ़ने के कारण उसको लटकाये रखा और बाद में उसमें कटौती करके 1 करोड़ 6 लाख का कर दिया । योजना विभाग और मूल्यांकन विभाग में फाइल लटकी रहती है क्योंकि जिला स्तर से दान-दक्षिणा नहीं मिलती । मथुरा की क्या दुर्दशा है यह बात आप स्वयं जानते हैं । जहां तक पर्यटन का मामला है । उत्तरांचल बन जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं । जैसे अभी श्री जगदम्बिका पाल जी ने पूर्वांचल के कुशीनगर सर्किट के बारे में कहा । उसी प्रकार से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज हम ताजमहल की 350वीं वर्षगांठ बना रहे हैं । मथुरा में भी देश-विदेश से करोड़ों धार्मिक पर्यटक आते हैं, माननीय मंत्रीगण आते हैं । वहां की जो सड़कें हैं उसमें 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं । मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, नन्दगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी समेत अन्य जगहों की भी बहुत बुरी हालत है । मैं मांग करता हूं कि काशी, मथुरा, अयोध्या और कुशीनगर को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 500 करोड़ रूपये का एक विशेष पैकेज दिया जाये जिससे स्थिति में सुधार हो सके । जब देश-विदेश से टूरिस्ट और हमारे मंत्रीगण मथुरा आते हैं तो वहां की दुर्दशा देखकर हमें बड़ी शर्म आती है । जब इनकी सरकारें रहीं तो गढ्ढा मुक्त सड़कों की बात कही, उस विभाग के मंत्री रहे । हमने पता नहीं कितनी एप्लीकेशन दी लेकिन एक भी स्वीकृत नहीं हुयी । इनके एजेंडे में काशी, मथुरा और अयोध्या का एजेण्डा पहले रहे ।

बस मन्दिरों को तोड़ने फोड़ने,मस्जिदों को गिराने का इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था । वहां के डेवलेपमेंट के मामले में यह मूक दर्शक बनकर रह गये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन तीन स्थानों का विकास होना चाहिए । जहां तक संस्कृति विभाग का प्रश्न है,उत्तर प्रदेश की कल्चर और संस्कृति खत्म होती जा रही है । इसका बजट नगण्य है । गंगा महोत्सव, शरद महोत्सव, वृंदावन महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, ब्रज महोत्सव हेतु अलग-अलग बजट एलाटमेंट किया जाता था आज वह नहीं किये जाते है । लखनऊ भातखंडे संगीत संस्थान यह एक डीमड यूनिवर्सिटी है। यहां पर रजिस्ट्रार की पोस्ट नहीं है, न यहां पर फाइनेंशियल आफिसर है और न परीक्षा नियंत्रक है । वाइस चांसलर की नियुक्ति कर दी गयी है । इसके लिए स्पेशल बजटिंग की जानी चाहिए । इस सरकार का अच्छा प्रयास है कि जो पुराने कार्य हैं उसको पूरा करें ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, जब हम लोगों की सरकार थी तो हमने गोकुल बैराज योजना बनायी थी जिससे मथुरा, वृन्दावन के लोगों को पानी उपलब्ध हो सके । उस समय तत्कालीन नगर विकास मंत्री, सम्प्रति नेता विरोधी दल जी की सरकार थी इन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया । मान्यवर,मथुरा में गोकुल बैराज योजना को पूर्ण करने के लिए 35 करोड़ की आवश्यकता है तथा इस बैराज के रख-रखाव के लिए एक करोड़ रूपया प्रतिवर्ष की आवश्यकता है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इसको नगर विकास विभाग द्वारा पूर्ण कराया जाय तथा सिंचाई विभाग द्वारा इस बैराज की रख-रखाव की व्यवस्था की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें । मैं अजीम भाई को बुला रहा हूं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे दल की ओर से भी बोलने के लिए आमंत्रित करें ।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यमुना आज इतनी प्रदूषित हो गयी है । लोग यहां पर आचमन करने के लिए आते हैं लेकिन वह इतनी प्रदूषित है कि हिम्मत नहीं पड़ती । मान्यवर, वृंदावन में राधा कृष्ण पौड़ी का निर्माण कराया जाय, के0सी0 घाट वृंदावन, बंगाली घाट, ध्रुव घाट मथुरा इत्यादि घाटों की दशा गंभीर है इसको ठीक कराय जाय । मथुरा में एक बस स्टैंड के निर्माण की घोषणा माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने की थी, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वहां पर एक अन्तर्राज्यीय बस अड्डा नेशनल हाईवे पर बनाया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें ।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मथुरा में बाबा जय गुरूदेव की समस्या लिट्टे की तरह होती जा रही है उनकी इस समस्या से निजात दिलायी जाये । इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग द्वारा रजवाहों की सफाई हेतु धन दिया गया है परन्तु माइनरों के सफाई हेतु धन नहीं दिया गया है । अधिकारियों द्वारा माइनरों की सफाई हेतु विधायक निधि से धन मांगा जाता है तो इस ओर ध्यान दिया जाय और माईनरों की सफाई के लिए भी धन दिया जाय । मान्यवर, मैं इसके अतिरिक्त गृह विभाग के मामले में यह कहना चाहूंगा कि भू-माफियाओं के सम्बन्ध में लगाम कसी जाय । पहले मुख्य मंत्री जी ने लगाम कसी थी लेकिन इधर वह ढीली होती जा रही है औ[illegible] जनता भू-माफियाओं से त्रस्त है । तो वहां की जनता को इससे निजात दिलायी जाय । मथुरा में जैत चा[illegible] नगर चौकी व ओल चौकी को थाने में तब्दील किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

अब आम समाप्त करें आपका लिखा नहीं जायेगा । अजीम साहब आप बोलें ।

***श्री अजीम भाई-**

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । बजट भाषण में पक्ष और विपक्ष के बहुत लोग बोलते रहे । हम लोगों ने बहुत से वरिष्ठ सदस्यों के भाषण को सुना। चूंकि हम सत्ता पक्ष के हैं और बजट ऐसा आया है कि हम तारीफ करेंगे लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे तकलीफ होती है । जिन लोगों ने हिन्दुस्तान में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था और जो समाज के चिन्तक थे और जो समाज में समता मूलक समाज स्थापित करना चाहते थे, जो यह चाहते थे कि लोगों में समानता आए उन्होंने यह फैसला किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, यह बहुत दबे कुचले लोग हैं, उनको आरक्षण की सुविधा दी जाए और उन्हें सुविधा दी गई, इसी तरह से पिछड़ा वर्गो को सुविधा दी गई । एक पिता के अगर चार बच्चे हैं और उनमें एक बच्चा कमजोर है और उसे पोलियो हो जाए तो उस पिता के दिल में यह जरूर हो जाता है कि उस विकलांग बच्चे के प्रति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण का नहीं किया ।

उसकी हमदर्दी बढ़ जाती है । मैं यहां सुन रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं पहली बार यहां पर आया हूं, लेकिन अध्यक्ष जी यह बात कई बार आई और आज भी आई, आज भी माननीय राम इकबाल सिंह जी, के द्वारा यह बात आई, अगर मुसलमानों के लिए कोई सरकार थोड़ा बहुत कुछ करना चाहती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हें ही होती है । कल जनसंख्या के बारे में बात उठती है, पूरे धर्म विशेष पर उंगली उठाई गई । जब कि केन्द्र की रिपोर्ट है कि जनसंख्या वहीं पर बढ़ रही है जहां पर शिक्षा की कमी है, किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं कहा गया ।

सालों से मांग चली आ रही है कि कामन सिविल कोर्ट लागू किया जाए, अल्पसंख्यकों के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि अगर कोई गरीब अल्प संख्यक का लड़का या लड़की सी0पी0एम0टी0 या एम0बी0बी0एस0 वगैरह में आ जाता है तो उनको एक हजार रूपये महीना दिया जाएगा । रिक्शा चलाने वाले जाहिर है गरीब ही रिक्शा चलाते हैं, डा0 लोहिया कभी रिक्शा नहीं खींचते थे, वही गरीब जिसके चेहरे पर मुस्कराहट नहीं है, उसके लिए अगर सुविधा दी गई, तो उन्हें ऐतराज है, उन्हें तकलीफ होगी । इसके पहले जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उनके द्वारा उर्दू के टीचर रखे गये थे, अध्यापक रखे गये थे, उसके बाद इतने दिनों तक बहुजन समाज वादी पार्टी और भाजपा की सरकार ही एक भी उर्दू टीचर नहीं रखे गए । आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में तीन हजार उर्दू अध्यापक रखें जाऐंगे, इस पर भी उनको ऐतराज है, मुसलमानों का जहां नाम नहीं कि उनको तकलीफ होने लगी । पता नहीं हम इस देश के रहने वाले हैं कि नहीं हैं । शिक्षा के क्षेत्र में हम कमजोर हैं । अनुसूचित जाति, जनजाति को इसलिए आरक्षण दिया गया ताकि यह बराबर खड़े हो जाए, पिछड़े वर्ग को आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि यह भी समाज के बराबर खड़े हो जाए, जिस तरह से यह सब शिक्षा के तौर पर, आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उसी तरह से मुसलामन भी आर्थिक तौर पर और शिक्षा के तौर पर कमजोर हैं, हमें भी आरक्षण दिया जाए । कल आंकड़े बताये गए बहुत अच्छा लगा । बताइये, आर्थिक स्थिति में हम कहां है, शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां है और नौकरियों में हम कहां हैं ? जब यह देश गुलाम था तब 35 सैकड़ा मुसलमान नौकरियों में हुआ करते थे आज आधा-एक सैकड़ा भी कहीं हैं, माईनस है । उस मुसलमान के लिए, जिसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, बैंकों से जिसको लोन नहीं मिलना चाहिए, जो मुसलमान अपने बल-बूते पर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु बनाता है, कैंची वह बनाता है, ताला वह बनाता है, सैकड़ों चीजें वह बनाता है, अगर कोई भी मुख्यमंत्री उन्हें थोड़ी सी सुविधा दे दे तो इन्हें तकलीफ होती है । भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया 1996 से लगातार आप हुकुमत कर रहे हैं कोई एक सुविधा दे देते । मन्दिर-मस्जिद के नाम पर दंगा हो जाता है, शहरों को बरबाद किया जाता है । गुजरात में कत्ले-आम हो सकते हैं ।

मान्यवर, धर्म के नाम पर नश्लपुशी हो रही है और वह लोग जिनको आप नौकरी नहीं दे सकते हैं जिनकी आप आर्थिक तौर पर मदद नहीं कर सकते हैं और जो लोग आज अपने दम पर रोजी रोटी पैदा कर रहे हैं उनकी हमदर्दी में अगर कोई मुख्यमंत्री दो लफ्ज बोल रहा है और थोड़ी बहुत उनको सुविधा दे रहा है तो आपको क्या ऐतराज है ? आज प्रदेश में कन्या विद्या धन योजना लागू की गयी है उसमें गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 20 हजार रू0 की सहायता दी जा रही है, आप बतायें कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें कि गरीब लोग नहीं होते हैं, आज चारो तरफ इस योजना की तारीफ है, उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं । क्या गरीब रिक्शा वाला नहीं होता है, अगर सरकार द्वारा उसको रिक्शा दिया जा रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए । आपने तो अपने समय में नहीं दिया क्यों नहीं दिया ? क्यों आप इतनी नफरत करते हैं, आज भी आपकी मानसिकता वही है । मान्यवर, हमें खुशी हुई कि भाई राम इकबाल सिंह जी ने उस बापू की तस्वीर को देखकर अपनी बात

कही उस तरफ देख लिया, आप उससे भी नफरत करते हैं, आपने उसकी हत्या करा दी जिस व्यक्ति ने एक डंडे और एक धोती के सहारे चलकर देश को आजाद कराया । आप उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं । मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए मुसलमानों के लिए अनेक घोषणायें की हैं । मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । जयहिन्द ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, कल से लेकर आज तक मैंने कई नेताओं के भाषण को सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण को भी सुना । मान्यवर, एक समाजवादी चिन्तक है-मुन्नवर राणा और शायर भी हैं वह । उन्होंने अभी पिछले जनवरी माह में एक शेर कहा था वह मैं आपको भी नजर करता हूं । इस व्यवस्था के ऊपर वह शेर है-

एक दो जख्म नहीं,
जिस्म है पूरा छलनी,
दर्द बेचारा परेशां है,
कहां से गुजरें ।

मान्यवर, इस बजट में चौधरी चरण सिंह जी और डा0 राम मनोहर लोहिया जी का नाम लिया गया है और उनकी अनुयायी यह सरकार है । मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी नूरपुर गांव में पैदा हुए थे और छपरौली उनका विधान सभा क्षेत्र था और बागपत उनका संसदीय क्षेत्र था । आप बता दें कि छपरौली, बागपत और नूरपुर-ने कहां से अलग से विकास कर लिया है । मैं सैफई और इटावा के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । मान्यवर, सरकार ने विकास वर्ष के रूप में इस बजट को प्रस्तुत किया है । आप इसे विकास वर्ष का नारा देना चाहते हैं । मान्यवर,किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वह है आबादी पर नियंत्रण और शिक्षा का प्रचार और प्रसार । आबादी के बारे में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है आज 2.5% की दर से आबादी की वृद्धि दर है । पिछले तीस वर्षों में किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की थी कि उसके ऊपर चेक लगा सके ।

श्री अध्यक्ष-

आपने कोई प्रयास किया इस पर ?

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, शादी इन्होंने नहीं की । (हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बढ़ती आबादी को रोकने के लिए सबसे आवश्यक है शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में अभी पहले मंगलवार को माननीय किरन पाल सिंह जी का बयान आया था । हमारे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया था कि 76405 अध्यापक और 15319 प्रधान अध्यापक प्राइमरी में कम हैं जूनियर में 12,791 अध्यापक और 12,654 प्रधान अध्यापक कम हैं इस तरह से

कुल मिलाकर 1 लाख 16 हजार अध्यापकों की आज कमी है और बेसिक शिक्षा का जो हाल है, मान्यवर, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं बेसिक शिक्षा का हाल आप बखूबी जानते हैं । 33 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रूपये तक एक जिले में खर्च हो रहा है और हालत यह है कि सम्पन्न परिवार के लोग प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते । आप विकास का नारा दे सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं लेकिन उसे यथार्थ पर धरातल पर नहीं ला सकते हैं । जहां तक जेन्डर बजट की बात कही गयी हमने लोकसभा की कार्यवाही पढ़ी है जब महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात आई तो यही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में उस बिल को प्रस्तुत नहीं होने दिया और आज वही लोग यहां जेन्डर बजट की बात करते हैं । हमको इस बात की खुशी है कि बुन्देलखण्ड को 100 करोड़ रूपया अतिरिक्त इस बजट में दिया गया है ।

मैं स्वागत करता हूं कि इस सरकार की उस नीति और नीयत का जिसमें 100 करोड़ रूपये अतिरिक्त बुन्देलखण्ड को दिये गये । पूर्वांचल के लिए व्यवस्था पहले से चली आ रही है । 2001 में एक व्यवस्था की गयी थी पश्चिमांचल के लिए और मध्यांचल के लिए जिसमें लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और बरेली मंडल के दो जिले शाहजहांपुर और पीलीभीत इस तरह से 14 जनपद को मध्यांचल और पश्चिमांचल बरेली से लेकर गाजियाबाद तक इसके लिए 35 करोड़ और 25 करोड़ को अलग से व्यवस्था की गयी । आज इस बजट भाषण को पूरा पूरा मौन चश्मा लगाकर पढ़ा है लेकिन कहीं भी मध्यांचल के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है और एक भी बात पश्चिमांचल की नहीं कही गयी है । विकास की बहुत बात की गयी है अगर बुन्देलखण्ड को 100 करोड़ रूपया दिया है तो पश्चिमांचल के लिए भी देना चाहिए था । जब हम सेक्शन के रूप में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । अगर मध्यांचल पैकेज की, किसी जनपद में पश्चिमांचल पैकेज की कोई व्यवस्था की होती तो आज हम उसका स्वागत करते । मान्यवर, उधर से कई माननीय मंत्री ने कहा पिछले वर्ष के मुकाबले, इस बार बढ़ाकर 13500 करोड़ की योजना आयोग ने वार्षिक योजना की मंजूरी दे दी तो मैं पूछना चाहता हूं कि 40 प्रतिशत नहीं 80 प्रतिशत बढ़ा दिया जाय, साढ़े 13 हजार करोड़ नहीं 20 हजार करोड़ की वार्षिक योजना पास करा लें, सवाल यह पैदा होता है कि 2004-2005 के 31 दिसम्बर तक कितनी स्वीकृतियां जारी की गयी और कितना पैसा खर्च किया यह यथार्थ के धरातल पर देखना होगा कि हम कितना दे रहे हैं प्रदेश में नारा देना बहुत अच्छी बात है लेकिन कितनी स्वीकृतियां जारी हुई ? अभी जिला योजना की बैठक हुई थी, ओम प्रकाश जी यहां पर नहीं हैं किसी विभाग में 40 प्रतिशत, किसी विभाग में 50 प्रतिशत, किसी में 60 प्रतिशत हुई हैं, 70 प्रतिशत से ऊपर किसी विभाग की स्वीकृतियां जारी नहीं हुई हैं । किसी माननीय सदस्य ने उधर से बोलते हुए यह नहीं बताया कि 2004-2005 में हमारा यह टारगेट था और हमने इतने प्रतिशत एचीव कर लिया ।

विद्युत के बारे में उधर से बहुत बार कहा गया । हम स्वागत करते हैं कि रिलायंस इनर्जी ने यहां पर इकरार किया है, दादरी में कारखाना लगाने के लिये, स्वागत योग्य कदम है । लेकिन मान्यवर, यह लांग टर्म प्लानिंग है । मैंने कई बार विधान सभा में पूछा कि आखिरकार कौन सी शार्ट टर्म प्लानिंग होगी, जिसके तहत हम आम आदमी को महीने, दो महीने-6 महीने में विद्युत उपलब्ध करा पायेंगे । मान्यवर, एक भी प्रयास इस सरकार ने शार्ट टर्म प्लानिंग में विद्युत को बढ़ावा देने के लिये नहीं किया है । फिर से गर्मी आ रही है, हर शहर में जाम, प्रदर्शन, धरने होंगे, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे विद्युत की व्यवस्था की जा सके । हमारे शाहजहांपुर में वर्ष 1996 में एक पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था, जिसको मुख्यमंत्री जी ने भी यहां कई बार कहा है, कुमार मंगलम बिरला साहब यहां पर आना चाहते हैं और इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं ।

यह मान्यवर, 567 मेगावाट का कारखाना लगाने के लिये पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था । पूर्व ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कई बार अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन कुमार मंगलम साहब कारखाना लगाने नहीं आ रहे हैं, वह अपने व्यवहार और आचरण से इस बात को प्रदर्शित भी नहीं करते हैं कि वह नहीं आयेगें । लेकिन आज 9 साल हो गये, कई बार कहा गया कि वह आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, इस हाउस में कई बार मैंने सवाल पूछा, लेकिन इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में भारत सरकार पूरी विद्युत व्यवस्था को रिवेम्पिंग करने के लिये पैसा देती है, हर बार यहां सवाल लगते हैं और पूछा जाता है, लेकिन बार-बार यह जवाब आता है कि टेन्डर की प्रक्रिया चल रही है । मान्यवर, यह टेन्डर की प्रक्रिया 13 महीनों से चल रही है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद शाहजहांपुर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अंतर्गत 44.8 करोड़ रूपया स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुयी और इस वजह से काम प्रारम्भ नहीं हो पाया ।

मान्यवर, समग्र ग्राम विकास योजना का यहां बड़ा ढिंढौरा पीटा गया, पहले इस योजना में विद्युतीकरण शामिल था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से इसे हटा दिया गया । इसी तरह 5-5 ग्राम विद्युतीकरण के लिये चयनित किये गये थे, अब पता नहीं करेंगे कि नहीं ? समग्र ग्रामों के संबंध में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी विधायकों से कहते हैं कि 4 हम करा देंगे, 2 आप बनवा दें। मान्यवर, आप किसी भी क्षेत्र में परीक्षण करवा लें । हमारे क्षेत्र में तो एक ब्लाक आता है, 80 हजार पापुलेशन है ग्रामीण क्षेत्र की । भावल खेड़ा ब्लाक में 10 ग्राम चयनित किये गये थे, लेकिन एक भी ग्राम सारी दृष्टि से संतृप्त नहीं हुआ है । आप चाहें तो इसका परीक्षण करा लें । मान्यवर, इस बजट में 1250 करोड़ रूपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की बात की गयी है । आप बजट का पृष्ठ-52 देख लें, 1212.38 करोड़ रूपये को हिसाब से लेते हुये अन्तिम ऋणात्मक शेष 674.17 करोड़ रूपये होना अनुमानित है । इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के श्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

मान्यवर, पूरे समाचार-पत्रों में आया कि यह कर विहीन बजट है । अब आय में वृद्धि कैसे होगी, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है । बाद में कोई न कोई कर लगा देगें । इसी प्रकार व्यय में कमी कैसे करेंगे, इसका कहीं कोई ब्योरा नहीं है । रोज किसी न किसी को मंत्री का दर्जा देकर बैठाया जा रहा है और व्यय में कमी की बात कही जा रही है । आप स्वयं देख लें कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अन्तर है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 1991 में कोलाघाट पुल का शिलान्यास हुआ, आज 14 साल हो गये, उसका पत्थर बाढ़ में बह गया, 250 ईटें चली गयी, आज तक वह पुल नहीं बना । जब मैंने विधान सभा में सवाल लगाया तो बताया गया कि अभी योजना स्वीकृत नहीं है और आज से 14 साल पहले कोलाघाट पुल का शिलान्यास हो गया । यह इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है । मान्यवर, कथनी और करनी का इतना बड़ा अन्तर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा ।

एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति है । किसी भी स्तर के वर्गों को आर्थिक सहायता दी जाए, लेकिन जब उनके सामने उनसे भी ज्यादा कमजोर वर्ग के लोग मौजूद हों तो उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए । बहुत से दलित और बैकबर्ड के भी रिक्शा चालक हैं, अगर आप उनके लिए भी कुछ करेंगे तो हम भी उसका स्वागत करेंगे । हम यह मांग भी करेंगे कि जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनको भी लाभान्वित किया जाए, तो हम आपका स्वागत करेंगे । इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसका स्वागत किया जा सके । यह एक प्रकार से वेस्टेज पेपर है, जिसमें पुरानी लकीरें बार-बार दोहराई गई हैं, इसलिए हम इस प्रस्तुत बजट का विरोध करते हैं ।

***श्री पूर्णमासी देहाती-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह विकासोन्मुखी बजट है और इस बजट में आवश्यकता की सारी चीजें सम्मिलित हैं । जो गांव के गरीब किसान और मजदूर के लिए चाहिए, वह सब कुछ इस बजट में है । हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज गन्ना किसान खुशहाल हैं, जब सामने बैठे हुए साथियों की सरकारें थीं तो रामकोला, पडरौना, मुंडरेवां में गोली चली थी । आज जो नीति सरकार ने बनाई है, उससे पूरे प्रदेश का किसान खुशहाल है । हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पिछली सरकारों में विधायक एक हैण्डपंप भी लगवा सकता था, आज हर क्षेत्र में सौ-सौ हैण्डपंप लग रहे हैं, पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण भी हुआ है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जो पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश की अनेक चीनी मिलों को बन्द कर दिया था, उन्हें भी चलाने की योजना चलाई जा रही है । पडरौना और कटकुइंया चीनी मिलें भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की चीनी मिलें हैं, लेकिन इस बात को जनता नहीं जानती है । हम निवेदन करेंगे कि उन मिलों को भी भारत सरकार से बात करके चलवाने का प्रयास किया जाना चाहिए । आप भी इस बात से अवगत हैं कि गन्ना किसानों की स्थिति पिछली सरकारों में दयनीय हो गई थी, कप्तानगंज और रामकोला जैसी अनेक चीनी मिलों पर लाखों क्विंटल गन्ना सूख गया था, लेकिन आज किसान यह महसूस कर रहा है कि यह किसानों की सरकार है । इस बजट का एक भाग गांवों में जा रहा है । अपने विपक्ष के साथियों के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो इनकी बहन जी ने इसी सदन में कहा था कि मैं माइके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियों, और वह यहां से भाग भी गई । मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भी अपने किये पर अफसोस करना चाहिये ।

मान्यवर, आज जो विकास के काम जगह-जगह हो रहे हैं उसी की देन है कि जगह-जगह सरकार की सराहना हो रही है । जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली में काफी सुधार हुआ है लेकिन कुछ सुधार की आवश्यकता है । मान्यवर, हम आपसे यह भी निवेदन करेंगे कि जो विकास की गति चल रही है अगर ऐसी ही गति रही तो सामने बैठे हुये साथियों का कहीं अता-पता नहीं चलेगा । अभी तक ये लोग बहुत हल्ला कर रहे थे लेकिन हमने सुना है कि झारखण्ड में उल्टा हो गया । अभी पौने पांच बजे कौन मुख्यमंत्री वहां हो गया ? वहां शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हो गये । मान्यवर, यह लोग नौटंकी ज्यादा करते हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी समय-सीमा के अन्दर रहते हुए एक गड़बड़ रामायण का दोहा सुना रहा हूं :-

पतित, पतित की भावना, पतित पतित घर जाएं ।
पतित बनावें, पतित परोसे, पतित बैठकर खाएं ।।

मान्यवर, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और साथियों से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो विकास के काम कर रही है उसकी सराहना आपको करनी चाहिए । यह सही है कि आपका कल्चर है कि चाहे कितना ही अच्छा काम होगा लेकिन उसका विरोध करेंगे । तो मान्यवर, यह जो विकासोन्मुखी बजट पेश हुआ है हम उसकी सराहना करते हैं और समर्थन करते हैं । इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपन बात समाप्त करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

***श्री देव नारायन उर्फ जी0एम0 सिंह-**

मान्यवर, आपने मुझे मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं । मैं सिर्फ इसलिए विरोध नहीं करना चाहता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हूं बल्कि इसलिए कि मुझको विरोध करना पड़ रहा है । जो सरकार में बैठे हुये लोग हैं, समाज वादी पार्टी के लोग यह परिवारवाद की पार्टी के रूप में पहले भी उभर चुकी है और क्षेत्रीय पक्षपात भी पूरे उत्तर प्रदेश में उभरकर सामने आया है । इस बजट को पढ़ने से यह पता चलता है, मैं तो सैफई नहीं गया हूं, सैफई कोई राज्य है या कोई डिस्ट्रिक्ट है लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सैफई की जनता की तरफ से कि अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति टाऊन एरिया या प्रधानी लड़ेगा तो कभी हारेगा नहीं । मान्यवर, समझिये क्योंकि पूरे प्रदेश का विकास सिर्फ सैफई में नजर आ रहा है । हमारे अजीम भाई बोल करके चले गये, वह दबी जुबान यह भी कह गये कि सत्ता में हैं इसलिए पक्ष में बोलूंगा ही, लेकिन वह दबी जुबान से बोले । उनकी मजबूरी नजर आयी । मैं वरिष्ठ साथियों की मजबूरी को भी समझ सकता हूं । यह बात उसी तरह से है कि दुर्योधन के साथ रहकर युद्ध करेंगे ही। लेकिन इतिहास इसको माफ नहीं करता है । मान्यवर, इस प्रदेश की जनता के साथ, विकास के साथ जो हो रहा है । भले ही समर्पण करना मेरी आदत रही हो, समर्पण करें लेकिन अगर समग्र गांव और अम्बेडकर गांव की तुलना की बात करते हैं तो आप हमारे क्षेत्र में चलें आप स्वयं देख करके बता देंगे कि यह अम्बेडकर गांव है और यह समग्र गांव है । बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 12 बिन्दुओं पर संतृप्त करने का काम किया लेकिन आपने 16 बिन्दुओं की घोषणा कर दी ।

मान्यवर, उसका नतीजा यह हुआ कि बिजली नदारद हो गई 2003 में अम्बेडकर समग्र ग्राम जो चयनित हुए मुख्यमंत्री जी सूचना मंगवा लें, करतहरी गांव आज तक किसी सड़क से नहीं जोड़ा गया । विकास की झूठी घोषणाएं की जाती है । हमारे वरिष्ठ साथी अभी कह रहे थे कि आनपरा-सी के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है और बातचीत चल रही है । मान्यवर, इसको देखकर मुझे एक कहानी की याद आ रही है । एक जंगल में राजा का चुनाव हुआ वहां पर एक बन्दर था उसने कहा कि हम भी राजा बनेंगे । जंगल के जानवरों ने बन्दर को राजा बना दिया । जब बन्दर राजा बन गया तो एक दिन शेर आया उसने दूसरे बन्दर को खाना शुरू किया तो जो बन्दर राजा बना था वह इस डाली और उस डाली पर उछल कुछ करने लगा । जिस बन्दर को शेर खा रहा था उसने राजा से कहा कि तुम हमें बचा क्यों नहीं रहे हो इस पर बन्दर राजा ने कहा देखो मैं कितनी उछल कूद कर रहा हूं मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है ठीक वैसा ही यह सरकार कर रही है । रिजल्ट कहीं कुछ नहीं यह सरकार खाली उछल कूद कर रही है । जब हमारी सरकार थी तो जो सरकार इरादा करती थी वह काम पूरा होता था ।

बहुजन समाज पार्टी की हमेशा काम करने की नीति रही है । आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें । मान्यवर, जनसंख्या की बात कही गयी है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत हाजिर जबाव भी हैं और विद्वान भी हैं उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूं । मान्यवर, जब 1975 में इमेंरजेंसी थी तो जबरदस्ती नसबन्दी की जाती थी । मान्यवर, हमें अपने पर प्रतिबन्ध लगाना है । अगर हर विधायक दो बच्चे पैदा करे तो उसका अच्छा असर होगा। जिनके दो बच्चों से ज्यादा हों उनके जिला पंचायत प्रमुख आदि का चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए तो जनसंख्या पर अपने आप प्रतिबन्ध लग जायेगा । आज हालत यह है कि राजनीति का जिक्र गांव-गांव, घर-घर में है । अगर विधायक अपने पर प्रतिबन्ध लगायेंगे तो इससे सबसे बड़ी प्रेरणा मिलेगी । नहीं तो आने वाले समय में देश की जनता हमें माफ नहीं करेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मन्जूर)-

अगर किसी के बच्चे न हों और वह पार्टी का नेता हो तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जायेगा या नहीं ?

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, मैं जानता हूं आप कहेंगे तो मैं सारे नाम बता दूंगा जिन्होंने दस-दस बच्चे पैदा किए हैं। अगर आप विधायक स्वयं बच्चा पैदा करने पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो प्रदेश की जनता जनसंख्या नियंत्रण की बात कभी नहीं कर सकती । आप चाहे कोई भी बजट ले आयें, कोई भी योजना ले आये जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक कोई योजना सफल नहीं होगी ।

श्री नरेश अग्रवाल-

इसमें हम चाहेंगे कि यह प्रस्ताव बहुजन समाज पार्टी की ओर से आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री देव नरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

तो इतनी देर तक क्या आप दूसरों की बातें कर रहे थे ?

श्री देव नरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

हमारे यहां गीडा इण्डस्ट्रियल एरिया है वहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि इण्डस्ट्रियल एरिया जहां डेवलप होती है वहां पर स्थानीय निकाय का अस्तित्व नियम 12 क के अन्तर्गत समाप्त हो जाता है । यह मेरी विधान सभा क्षेत्र में आता है वहां पर 300 गांव है कौड़ीरामपुर और सहजनवाँ विधान सभा क्षेत्र में यह आता है तो जब पंचायतों का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा तो विकास कैसे होगा यह बहुत बड़ी समस्या है । मैं चाहता हूं अगर 12 क का नियम यहां लागू होता है तो सभी पंचायतों नगर पंचायतों ग्राम पंचायतों को इण्डस्ट्रियल एरिया की एथारिटी में दे दिया जाय ताकि सभी क्षेत्रों का विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री दिलीप कुमार वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने का मौका दिया । मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारा क्षेत्र महसी जो एक अति पिछड़ा क्षेत्र है और अनेकों नदियों से घिरा हुआ है । हमारा महसी क्षेत्र घाघरा नदी और सरयू नदी से विभाजित है बल्लू वन्दू पुरवा घाट पर पुल पुरवा-घाट जो शिवपुर ब्लाक को दो भागों में बांटता है । इसी के साथ खरकट्टन-पुरवा के पास नदी पर पुल की मांग करता हूं । इससे बहराइच खीरी की दूरी 45 कि0मी0 कम हो जाएगा । इसी के साथ मैं परागी राजी चौराहा, इमान गेहन होते हुए नानपारा तक के मार्ग की मरम्मत की मांग करता हूं । यह प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है । महसी महसील से उत्तर छोटी सरयू पर पुल की आवश्यकता है। इस पर पुल

बनवाया जाय । महसी तहसील में फायर स्टेशन नहीं है इससे जब जब आग लगती है दिक्कत होती है अत: वहां पर फायर स्टेशन का निर्माण किया जाय । उमरपुर घाट पर पुल बनवाया जाय जिससे महसी और बहराइच के बीच की दूरी 17 कि0मी0 कम हो जायेगी । इसके साथ मैं अपने क्षेत्र इटहा के पास पावर सब स्टेशन की मांग करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री धर्मपाल सिंह (बरेली)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वर्ष 2005-2006 के बजट भाषण पर विपक्ष में बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । अध्यक्ष जी कोई भी बजट तभी अच्छा माना जाता है जब उसमें आय के साधन ज्यादा हों व्यय कम हो और कर्जा बिल्कुल न हो । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है इसमें आय के साधन है नहीं व्यय ज्यादा है और कर्जा भी प्रदेश में सबसे ज्यादा है । मैं संक्षेप में बताना चाह रहा हूं वर्ष 1993-94 ऋण 30.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर 51.4 प्रतिशत हो गया ।

इस समय उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक ऋणग्रस्त प्रदेश है और आज सरकार पर वर्ष 2005-2006 में 674.17 करोड़ रूपये ऋण बकाया है । जब इस तरीके से इसकी व्यवस्थाएं हैं और बजट बहुत बढ़-चढ़कर प्रस्तुत किया गया है तो मुझे यह बात याद आ जाती है । 'यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम् पीवेत्' जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो । यह उत्तर प्रदेश की स्थिति बजट में है । बजट में कुड आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं । मान्यवर, इसमें आंकड़ों में बजट की व्यवस्था की गई है । बजट में प्राविधान भी किया गया है और प्रस्तुत भी किया गया है । प्राविधान और बजट का अंतर यह स्पष्ट कर दें । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या किसानों की है । वास्तव में आज उत्तर प्रदेश में किसान परेशान हैं । किसान आज सोचने को बाध्य है कि वह खेती कैसे करे? अगर खेती न करे तो क्या करे ? आज किसान के प्रयोग में आने वाला डीजल मंहगा है ।

केन्द्र सरकार ने डीजल के रेट बढ़ायें तो प्रदेश सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी ने उस पर टैक्स लगा दिया । आज प्रदेश में किसान डीजल खरीदने की हैसियत में नहीं है । यह सरकार किसानों को बिजली नहीं दे रही है । इस तरह से आज प्रदेश में किसान को खाद, पानी, डीजल, बिजली का अभाव है । बुआई के समय किसान को बिजली उपलब्ध नहीं हुई, खाद उपलब्ध नहीं हुई, यूरिया, डी0ए0पी0 नहीं मिली । आज मान्यवर, किसान इस तरीके से परेशान है । मान्यवर, बजट में जिस तरह से किसानों के लिये बढ़ चढ़कर कहा गया है वह सब मिथ्या प्रतीत होती है । शिक्षा के बारे में काफी कुछ कहा गया है । प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है । प्राथमिक शिक्षा में जो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं उनका वेतन भी ठीक-ठाक है । आज अधिकांश विद्यालय एकल हैं और उनमें कहा गया है कि शिक्षा मित्रों का चयन कर दिया गया है । एकल विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई नहीं होती । आज प्रदेश में छात्र संख्या इन प्राथमिक विद्यालयों में बहुत कम होती चली जा रही है। उन विद्यालयों में गार्जियन बच्चों का एडमीशन नहीं कराते हैं वे अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं । इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो विद्यालय स्वीकृत होते हैं चाहे जूनियर हाई स्कूल या प्राथमिक विद्यालय हो, शासन की व्यवस्था रही थी कि वह विद्यालय संबंधित गांव पंचायत ने जो जमीन दी है उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की जानकारी में उसी जगह पर बताया जायेगा । लेकिन इधर कुछ इसमें कमी हो रही है मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा अध्यापक से मिलकर जो जगह गांव पंचायत ने आवंटित की थी उससे इतर दूसरी जगह पर निर्माण कराना प्रारम्भ करा दिया । मैंने इस संबंध में कई बार निवेदन भी किया कि जिस जगह को गांव पंचायत ने विद्यालय हेतु आवंटित किया है वहां पर ही विद्यालय बनाया जाय लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

मान्यवर, इसी तरह से कहना चाहता हूं कि इस बजट में नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई है । आज प्रदेश में किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला है । मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि यहां सेवायोजन कार्यालय है इसमें सरकार इतनी व्यवस्था कर दे कि जो सरकारी जगह निकलती है, सरकारी विज्ञप्तियां होती है उनको इन सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से लिया जाय तो जरूर कुछ बेहतर व्यवस्था हो जायेगी । नौजवानों को रोजगार तो नहीं मिला है लेकिन उसके बदले में उनको अपराध में जरूर झोंक दिया गया है । बिना पूंजी निवेश में कुछ काम ऐसे हो रहे हैं कि नौजवान लोगों के अपहरण का काम कर रहे हैं । मान्यवर, इस तरह की परिस्थिति प्रदेश में बनी हुई है । अभी कहा गया था कि बजट में रिक्शाचालकों के बारे में भी कहा गया है कि हम उनके लिये बीमा योजना लागू करेंगे । हम चाहते हैं कि सरकार उनका बीमा करे ।

लेकिन उन गरीबों के पास प्रीमियम का पैसा नहीं होता है तो क्या सरकार उनका प्रीमियम जमा कराने की व्यवस्था करेगी । यह सरकार गरीबों की हितैषी है ।

श्री अध्यक्ष-

पाँच बज गया है । माननीय मंत्री जी चाहे तो कोरम देख लें टाइम बढ़ा दें, अन्यथा कल भी इनमें चर्चा जारी रहेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल-

ठीक है ।

श्री धर्मपाल सिंह-

मैं अपनी बात कह दूं । इसमें बहुत अच्छी कानून व्यवस्था की बात कही गई है यह कानून व्यवस्था की बात करते हैं । ललितपुर जनपद में एक रामेश्वर लोधी नाम के व्यक्ति को गोली से मार दिया गया और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई ।

श्री सतीश महाना-

श्रीमन्, समय बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने कहा है आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाए ।

श्री नरेश अग्रवाल-

आधा घंटा बढ़ा दें, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आधा घंटा बढ़ाया जाता है ।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मात्र दो रूपये किराए के पीछे उसे गोली मार दी गई और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी

गई । पुलिस ने साधारण धाराओं में रिपोर्ट लिखी है । ललितपुर जनपद मे भा0ज0पा0 अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी जी भी गए लेकिन पुलिस वाले 302 में इस केस को शामिल नहीं कर रहे हैं । थाना ऑवला में....

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें ।

श्री धर्मपाल सिंह-

इसी तरह से लोधी परिवार के लोगों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्यायें की जा रही है । लोधी राजपूत बिरादरी के लोगों के साथ घटनायें घटित हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आप तो मंत्री रहे हैं कुछ नियमों का पालन करेंगे । मेरा निवेदन मान लें ।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, थाना ऑवला में लोहिया महाविद्यालय है वहां विज्ञान की कक्षायें हैं लेकिन इसके संचालन के लिए शिक्षक नहीं है मेरा अनुरोध है कि वहां पर विज्ञान की कक्षाएं चलाई जाएं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । 2005-2006 का बजट, जो सही समय में फरवरी, मार्च में पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं । प्रस्तुत बजट में बेरोजगारी को मिटाने का संकल्प है । बजट में वित्तीय अनुशासन को लागू करते हुये फिजूल खर्ची पर पाबन्दी लगाने और विकास कार्यो में तेजी लाने का प्रयास किया गया 5,312 करोड़ रूपया इस वर्ष बजट गत वर्ष की तुलना में अधिक दिया गया है । इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी की योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है । महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने एवं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राविधान किया गया है । इस बजट में गरीबों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है । खेतिहर मजदूर को 6 महीने का अतिरिक्त रोजगार देने रिक्शा चालकों को लाभ देने, महिलाओं को लाभान्वित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है । ऊसर भूमि के सुधार की व्यवस्था की गई है । बजट में शुद्ध घाटा 674.17 करोड़ होना अनुमानित है । गत वर्ष की तुलना में 555 करोड़ रूपया अधिक है । इस बजट में गांव के विकास के लिए 72 प्रतिशत धनराशि सुनिश्चित की गई है जो सराहनीय उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन, नई ऊर्जा नीति, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नीति, नई आवास नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति, चीनी उद्योग नीति प्रारम्भ की गई है । राजस्व घाटे के बजाय पूंजीगत घाटे में, इस बजट में वृद्धि है, जिसका साफ अर्थ है कि राज्य सरकार की मंशा अनुत्पादक व्यय में कमी करने की है और सड़क, पुल, बिजली, सिंचाई, शिक्षा और पेयजल जैसे अवस्थापना कार्यो में व्यय बढ़ा रही है । बजट में शुद्ध घाटा मात्र 674.17 करोड़ का है, जो गत वर्ष की तुलना में मात्र 55 करोड़ रू0 अधिक है । अवस्थापना क्षेत्र में व्यय बढ़ाने से रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेगें ।

मान्यवर, पहली बार जेण्डर बजटिंग की शुरूआत की गई है जिसमें बजट का एक तिहाई भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं के लिए रखा गया है । चीनी उद्योग को मजबूत करने के लिए चीनी उद्योग नीति-2004 घोषित की गई है । यह किसानों की खुशहाली और चीनी उद्योग को मजबूत करने के लिए किया गया है । मान्यवर, गन्ना किसानों के भुगतान के संबंध में कहना चाहता हूं, जो भुगतान किया गया है, वह स्वागत योग्य है लेकिन गन्ना पेराई सत्र 2002-2003 का भुगतान प्रदेश के किसानों का अभी बकाया है, गन्ना भुगतान के लिए हमें सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय खत्म हो गया है ।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, अभी तो मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है । हमारी बात भी नहीं आ पाई है ।

श्री अध्यक्ष-

अभी और भी सदस्यों को बोलना है । आप विद्वान सदस्य है, डाक्टर भी है । अब आप बैठे हैं।

श्री धर्मराज निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2005-2006 का प्रदेश के लिए बजट पेश किया है । अध्यक्ष जी,मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इस बजट में कहा गया है कि वर्ष 2005-2006 में 4700 नए स्कूलों की स्थापना होगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, अम्बेडकर नगर जनपद में कटहरी, भीटी ब्लाक है वहां के विद्यालयों में मानक के विपरीत एक-एक विद्यालय में 200-200 बच्चे हैं । सरकार ने 40 हजार विशिष्ट बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति की है लेकिन हमारे यहां विद्यालयों में जो विशिष्ट बी0टी0सी0 के अध्यापक नियुक्त हैं उनको मानेदय नहीं दिया गया है । जो भोजन पका-पकाया दिया जाता है, बच्चों को, उन्हें रोटी-दाल नहीं दिया जा रहा है, केवल हलुआ और खिचड़ी दी जा रही है । वहां अध्यापक न होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति के हों या सवर्ण जाति के हों, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं । वह केवल खाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं । मान्यवर, हमारे जनपद अम्बेडकर नगर में रघुनाथपुर है, शिक्षा मंत्री जी चले गये हैं, मैं कहना चाहता हूं, जो छात्र-वृत्ति जा रही थी अनुसूचित जाति के बच्चों को, वह नहीं गयी है। मान्यवर, पिछड़े वर्ग के लोगों को टर्म लोन दिया जाता है, इसमें सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को जीप खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है, लगभग 2 साल से पैसा नहीं गया है और जो भी दिया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि 50 हजार रूपये से ज्यादा उनको न दिया जाए । मान्यवर, हमारे सिंचाई मंत्री जी हैं, 18 दिसम्बर को हमारे यहां उप चुनाव चल रहा था, मान्यवर, हमारे क्षेत्र की खासकर एक बड़ी समस्या है दखनझील कई सौ हेक्टेयर जमीन वहां पानी से भरी रहती है और इस समस्या से 15-20 ग्राम पंचायतें प्रभावित हैं । मंत्री जी ने भरे मंच से कहा था कि इसके लिए 33 लाख रूपया आ गया है, वहां पर मशीन भी आ गई थी लेकिन चुनाव के बाद चली गई और कोई काम नहीं हुआ ।

मान्यवर, डेढ़ करोड़ रूपये नाले पर रेलवे पुल के लिए जो बहन कु0 मायावती जी ने दिये थे तो वहीं पैसा गया है । मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो घोषणाएं होती है उसको कम से कम पूरा करवा दें । इसी सदन के तीसरी बार मुख्यमंत्री जी हैं । मैं तो दूसरी बार चुनकर आया हूं । मान्यवर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी मंत्री थे तो मा0 मुख्य मंत्री द्वारा पुल का शिलान्यास किया गया था। अबकी बार भी उप चुनाव में माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने घोषणा की थी लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ । माननीय अध्यक्ष जी, डा0 राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेकर यह जो बजट पेश कर रहे हैं। तो कह रहे थे गृह जनपद । सैफई और इटावा को दिया । लेकिन उनकी जन्म स्थली अकबरपुर है वहां पर तो कताई मिल भी बंद कर दी । मेरा कहना है कि उसमें जो कताई मिल बंद है उसको चालू किया जाये । हमारे समग्र ग्राम्य विकास मंत्री जी चले गये है । उन्होंने कहा कि घोषित योजना है । मान्यवर, वर्ष 2003-2004 में जो भी समग्र ग्राम थे उसमें पूरे अम्बेडकर नगर में एक पैसा भी लेपन के लिए नहीं दिया गया । जबकि शासनादेश भी है कि जिन सड़कों पर मिट्टी का काम हो गया हो वहां पर लेपन का कार्य करवाया जाये । लेकिन वह भी नहीं किया गया । वह सड़कें वैसी की वैसी पड़ी हुयी है ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

***श्री विद्या सागर गुप्ता-**

मान्यवर, बजट के विरोध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में लघु उद्योगों की बड़ी अवहेलना की है । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी इत्यादि को प्राथमिकता दी है किन्तु उद्योग को इस श्रेणी में नहीं रखा है। मान्यवर, किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि और उद्योग एक कड़ी के दो पहलू है । यदि उद्योग की उन्नति प्रदेश में नहीं होती है तो प्रदेश राजस्व की दृष्टि से कमजोर होगा । रोजगार के आयाम नहीं लगेगें तो रोजगार कहां से बढ़ेगा और जनता को रोजगार नहीं मिलेगा । श्रीमन् माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2004-2005 की तुलना में वर्ष 2005-2006 में सड़क एवं यातायात पर 900 करोड़, शिक्षा पर 1600 करोड़ रूपये, ऊर्जा पर 400 करोड़ रूपये,सिंचाई परियोजनाओं पर 2 हजार करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है । किन्तु मान्यवर, बजट भाषण की इस पुस्तिका में लघु उद्योगों के लिए एक भी पैसे का प्राविधान नहीं किया है । प्रदेश के 80 प्रतिशत उद्योग लघु उद्योगों में है । बड़े उद्योग केवल 20 प्रतिशत है और 80 प्रतिशत लघु उद्योग है । इसके अलावा अधिकतर जनसंख्या को रोजगार के आयाम लघु उद्योगों में मिलते हैं । मुख्यमंत्री जी ने 30 हजार नए उद्योग लगाने की घोषणा की है । लेकिन जब इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, नयी इण्डस्ट्री नहीं लगेगी तो 30 हजार लघु उद्योग कहां से लगेंगे । इस हालत में तो तीन हजार भी लगने मुश्किल हो जायेगी । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम एक हजार करोड़ रूपया उद्योगों की उन्नति के लिए प्राविधान किया जाय । मान्यवर, आपने उद्योगों पर एक नया कर विकास कर लगाया है । श्रीमन् पुराने उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं और नये उद्योग नहीं लगेंगे तो कहां से रोजगार आयेगा, राजस्व वृद्धि कहां से होगी । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि विकास कर को तुरन्त वापस लिया जाय जिससे इस प्रदेश के बार्डर ऐरिया के उद्योग हैं वह दूसरे प्रदेशों में न जायें और दूसरे प्रदेश के उद्योग यहां पर आ सकें । इसलिए अपनी बात पर बल देते हुए यह निवेदन करूंगा कि विकास कर समाप्त किया जाय । अंत में अपने क्षेत्र के लिए दो बातें कहना चाहता हूं । हमारी पूर्वी विधान सभा लखनऊ में जुगौली एक जगह है, जो कि एक गांव है गोमती नगर में, वहां सड़क बनी है । उस सड़क से गोमती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

नगर से फैजाबाद रोड आने के लिए 15 मिनट का समय लगेगा जबकि उसमें चार किलोमीटर जाना पड़ता है और आधा पौन घंटा लगता है । मैं आवास एवं विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस सड़क को शुरू कराया जाय । इसी तरह से दो फलाई ओवर लखनऊ में-एक मुवैया में और एक सदर में बन रहा है इसको जल्दी से पूरा कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री अध्यक्ष-

देखिये 15 मिनट का समय है इसमें तीन लोगों को बोलना है आप लोग तय कर लें ।

श्रीमती गुलाब देवी-

मान्यवर, हमको बोलने का अवसर दे दें ।

श्री अध्यक्ष-

आप महिला हैं आप बोल लें ।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

मान्यवर, महिला के बाद विकलांग सदस्य को भी मौका दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक हैं ।

***श्रीमती गुलाब देवी-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में सेतु परियोजना के लिए नौ सौ करोड़ रूपया प्रस्तावित किया है और ग्रामीण सड़क के लिए सम्पर्क मार्ग बनाने के लिए 375 करोड़ रूपयों का प्राविधान रखा है, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि यह मेरे दुर्भाग्य की बात है कि इस समय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी दोनों यहां पर नहीं है लेकिन माननीय नरेश अग्रवाल जी बैठे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरी बात वहां तक पहुंचा देगें । मेरे क्षेत्र चंदोसी में जो जिला मुरादाबाद में है और यह सुरक्षित सीट है विकास की दृष्टि से पिछड़ा है । जहां नौ सौ करोड़ रूपया का प्राविधान रखा है तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे यहां एक मिनी पुल बना है बुद्धनगर, खंदवा में जिसके बारे में, मैं पहले भी कह चुकी हूं और आज भी आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहते हुए माननीय श्री अग्रवाल साहब से कहना चाहूंगी कि बुद्ध नगर खण्डुवा में जहां पर यह पुल है उसको बनवाने की आप कृपा करें । दूसरा जो मैंने बताया कि ग्रामीण सम्पर्क मार्गो को जोड़ने के लिए 375 करोड़ बजट में रखा हुआ है उसमें ऐसे इलाकों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने की बात है, पिछली बार भी मैने इसे उठाया था कि चन्दौसी-रतन पुर वेरनी मार्ग से छावड़ा धनुपुरा होते हुए रामपुर सीमा तक जो सड़क जाती है, वह इतनी टूटी-फूटी हुई है कि उस पर चलना बहुत कठिन है, उसको ठीक कराया जाय । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यहां नहीं बैठे हैं, इसमें 375 करोड़ रूपये के बजट का प्राविधान है, मान्यवर, अगर उनके क्षेत्र के लिए कोई सड़क जा रही है तो उसका निर्माण कार्य होना आवश्यक है, चूंकि यह मुख्य मार्ग है और रोजाना इस पर ट्रकें-बसें वगैरह चलती हैं इसलिए इसकी मरम्मत होना परम आवश्यक है । मान्यवर, ग्राम पुरा से सैजनी मार्ग जोड़ने के लिए है, चिड़िया भवन से वरौली, करेली मर्डया से चन्दौसी मार्ग जोड़ने के लिए है, इन्हें बनाया जाय । मान्यवर, बहुत से ऐसे मार्ग हैं जहां आज भी कोई यातायात की सुविधा नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हुई, यह कह देना चाहूंगी कि जैसे सदन में यह तय हुआ था कि जो कार्य विधायक के द्वारा प्रस्तावित हैं चाहे मण्डी समिति के हों, चाहे प्रधानमंत्री योजना के हों चाहे पंचायतीराज के हों जो विधायकों द्वारा प्रस्तावित हों, उनका जब शिलान्यास हो, जब बोर्ड लगे तो उस पर वहां के सम्बन्धित विधायक का नाम जरूर होना चाहिए और इसके लिए आप जिलाधिकारी, मुरादाबाद को निर्देशित करें कि जितनी भी सड़कें इस तरह से बनाई जा रही हैं, उनमें शिलान्यास के समय संबंधित क्षेत्र के विधायक का नाम जरूर अंकित किया जाए । मान्यवर, वहां पर कहीं भी विधायक का नाम किसी भी रूप में नहीं डाला जा रहा है, यह एक आपत्तिजनक विषय है । वैसे भी सड़कें नहीं बन पा रही हैं और जो किसी भी तरह से बन भी रही हैं, उनमें संबंधित क्षेत्र के विधायक का नाम नहीं डाला जा रहा है । मान्यवर, दूसरी मुख्य बात मैं हय कहना चाहती हूं कि जिला योजना में विकास के लिए 20-20 लाख रूपये मिले हैं, एक तो यह वैसे भी नहीं हो रहा है दूसरे अधिकारियों की लीपा-पोती या अपने मातहतों की जनरों में बहुत अच्छा बनने के चक्कर में उस पैसे को दूसरी विधान सभा क्षेत्रों में भेज दिया जा रहा है तो मैं चाहूंगी कि जो पैसा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए दिया गया है उसे दूसरे क्षेत्र में न भेजा जाए । इसी के साथ मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

***श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक'-**

मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, इस बजट में न ही कहीं कोई कृषि में, न ही शिक्षा में, न ही परिवहन में, न ही चिकित्सा शिक्षा में, न ही ग्राम विकास में, न ही राजकीय विकास योजना में, न ही पंचायती राज में, न ही अवस्थापना में, न ही सड़क एवं यातायात में ।

मान्यवर, न ही सिंचाई विभाग में, न ही ऊर्जा विभाग में, न ही परिवहन विभाग में और न ही अतिरिक्त ऊर्जा विभाग में और न ही किसी विभाग में मान्यवर विकलांगों के लिए बजट में क्या-क्या प्राविधान किया गया है इसका कोई उल्लेख है । मान्यवर, इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो भी सड़े-गले कानून विकलांगों के लिए किसी जमाने में बने होंगे आज तक मान्यवर, आजादी के बाद से देश में और इस प्रदेश में कितनी ही सरकारें बनी हैं किसी ने भी विकलांगों के संदर्भ में कोई चिन्ता नहीं की ।

मान्यवर, मैं जिस समय गाड़ी चलाता हूं और बिना लाइसेंस के चलाता हूं अगर किसी रास्ते पर किसी सफेद वर्दी वाले सिपाही ने देख लिया और लाइसेंस दिखाने की मांग कर ली तो आप समझ सकते हैं कि उस स्थिति में एक पूर्व मंत्री और एक विधायक की क्या स्थिति हो सकती है । मान्यवर, आप कहें तो मैं चाहें अम्बेसडर गाड़ी हो, फियेट हो, मारूति हो, ट्रक हो, बस या ट्रेक्टर हो, मैं इस पूरे सदन के कुछ सदस्यों को बिठा कर, केवल एक जगह को छोड़ कर, किसी भी जगह ले जा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मेरे यहां एक लड़का है जिसके दोनों हाथ नहीं है और पैर से वह जीप चलाता है, ट्रेक्टर चलाता है मैं आपके सामने उसे कभी लाउंगा । वह भी कहना है कि लाइसेंस मिल जाए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, आप जानते हैं कि जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट है वह भारत सरकार का ऐक्ट है राज्य सरकार का नहीं है । इस मारे या तो भारत सरकार की ऐसी कोई नीति बन जाए या फिर यह सदन इस बारे में कोई संस्तुति कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दें ।

श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक'-

मान्यवर, मुझे इसका भी भान है । मान्यवर, अब जैसे कटिया मशीन है । मान्यवर, आज इस वैज्ञानिक युग में कितने सुरक्षात्मक उपाय विकसित हो गये हैं लेकिन यदि कोई हमारे गांव का किसान दिन-रात मेहनत करता है ट्यूबवेल में काम करता है थ्रेशर में कटाई करता है और अगर उसका गलती से कटिया मशीन में हाथ फँस जाता है तो उसका हाथ चला जाता हे । भगवान न करें कोई ऐसी स्थिति में विकलांग हो जाए, लेकिन यह बात होती है ।

(श्री अरूण कुमार मेहरोत्रा, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री प्रदीप जैन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रदीप जैन जी आप एक लाईन बोल दें उसके बाद आपकी चर्चा कल जारी रहेगी ।

डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, यह घोषणा कर दें कि जो लोग नहीं बोल पाए हैं वह कल बोल लेंगे और उनके नाम प्राथमिकता पर रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, यह जो सूची होती है यह पीठ के विवेक पर होता है और यह सूची अध्यक्ष की सहासता के लिए होती है आप अपने नेताओं से बात करिए ।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड का इलाका आर्थिक असमानताओं के कारण पिछड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी चर्चा कल जारी रहेगी ।

मैंने कल नियम-300 की एक सूचना पर आज निर्णय देने को कहा था लेकिन वह टाईप होने में थोड़ा विलम्ब हो गया है, इसलिए वह निर्णय मैं कल दूँगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 2 मार्च, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 49 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री डी0 प्रसाद अहिरवार की जनपद चित्रकूट की जो कर्वी तहसील में पुलिस लाइन निर्माण हेतु, अधिगृहित भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना,

श्री श्याम देव राय चौधरी की, जो संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में गुर्दा रोगियों के लिए डायलिसिस का रजिस्ट्रेशन बंद किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना, श्री हुकुम सिंह की, जो जनपद मुजफ्फरनगर के कण्डेला में पर्याप्त क्षमता का ट्रांसफामर लगाये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौथी सूचना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो जनपद रायबरेली के ऊंचाहार स्थित अम्बेडकरनगर, पुरौली में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । पांचवीं सूचना, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की, जो जनपद महोबा के डाक्टर भानुप्रताप सिंह राजपूत की निर्मम हत्या करने वाले लोगों की गिरफ्तारी न होने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । छठी सूचना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की, जो श्रम विभाग में सहायक कारखाना निदेशकों की ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाने,के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं सूचना, श्री दीनानाथ कुशवाहा की, जो जनपद देवरिया की ग्राम पंचायत लाहिल पार स्थित स्कूल भवन को पंचायत भवन बनाये जाने एवं अनियमितता किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । आठवीं सूचना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की, जो नियम 56 में प्राप्त जनपद गोरखपुर स्थित धर्मशाला रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । नवीं सूचना, श्री बैजनाथ दूबे की, जो जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 की अवशेष धनराशि का भुगतान किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जो, अम्बेडकरनगर में सहायता प्राप्त समस्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों को सेवा निवृत्ति के उपरांत जी0पी0एफ0 का भुगतान न किये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अध्यक्ष-

ग्यारहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की नियम 56 में प्राप्त हुई, जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पन्नाटिकरी में अनुसूचित जाति के तीन लोगों को गोली मारकर घायल करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में है ध्यानकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । बाहरवीं सूचना, श्री मतेश चन्द्र सोनकर की जो जनपद कौशाम्बी के ग्राम कमालपुर में पानी की ओवरहैड टैंक बनाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । तेरहवीं सूचना, श्री आलम बदी की जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद स्थित कठवां के जर्जर पुल के निर्माण के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

अब क्या व्यवस्था का प्रश्न है ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम हैं-

1-श्री विश्राम सिंह यादव

2-डा0 राम बाबू हरित, श्री छोटे लाल वर्मा

3-श्री राम चन्द्र यादव

4-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
5-श्री छोटे लाल वर्मा
6-श्री मदन चौहान
7-श्री आर0के0 सिंह पटेल
8-श्रीमती विद्या चौधरी
9-श्री जगदीश नारायण राय
10-श्री प्रागी लाल अहिरवार
11-श्री अमर जीत सिंह 'जनसेवक'
12-श्रीमती राजरानी रावत
13-श्री मुंशी लाल गौतम
14-श्री अनिल कुमार वर्मा
15-श्री आलोक कुमार शाक्य
16-श्री सुरेश कुमार खन्ना
17-श्री राजेश कुमार
18-श्री आर0एस0 कुशवाहा
19-श्री विनय शाक्य
20-डा0 सुशील चौधरी
21-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
22-श्री उदय भान करवरिया
23-श्री राम करन आर्य
24-श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया
25-डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा
26-श्री राम इकबाल सिंह
27-श्री काली चरण राजभर
28-श्री रणवीर राणा
29-श्री मशहूद खां
30-श्री जियाउद्दीन रिजवी
31-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर
32-श्री कौशल किशोर
33-श्री राम हेत
34-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय
35-डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी
36-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुन: बैठेगें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 2 मार्च, 2005

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 49 विधान सभा (86)-28-6-2005-813 (कम्प्यूटर)।